Azadi Ka Amrit Mahotsav

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

प्रधानमंत्री 30 जनवरी, 2022 को शहीद दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

विषय सूची

1. एक अवलोकन 7
2. प्रमुख झलकियां 11
3. नई पहल 27
4. सूचना क्षेत्र 33
5. प्रसारण क्षेत्र 67
6. फ़िल्म क्षेत्र 85
7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग 125
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 129
9. सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व 135
10. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 139
11. महिला कल्याण 141
12. सतर्कता संबंधी मामले 143
13. नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण 145
14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संबंधित का कार्यान्वयन 149
15. लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा 153
16. लेखा पैरा 163
17. कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन 165
18. योजना परिव्यय 167
19. मीडिया इकाई-वार बजट 169
20. सांगठनिक ढांचा 173

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईआईएफएफ-2021) के 52वें संस्करण के लिये 19 नवंबर, 2021 को तैयार पणजी, गोवा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 14 फरवरी, 2022 को हैदराबाद में दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण करते हुए।

1 एक अवलोकन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जन संचार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फ़िल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, विज्ञापनों, नए माध्यमों जिसमें डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ-साथ जन संचार के पारंपरिक तरीकों-नृत्य तथा नाटक के जरिए जनसामान्य तक जानकारी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

मंत्रालय, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती), मल्टी-मीडिया प्रचार और भारत सरकार के कार्यक्रमों की नीतियों, फ़िल्म प्रसार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन विभागों- सूचना, प्रसारण और फ़िल्म विभाग में विभाजित किया गया है। मंत्रालय अपनी 10 मीडिया इकाइयों/संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों, 03 स्वायत्त निकायों तथा 03 प्रशिक्षण संस्थाओं और 02 सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रमुख, सचिव होते हैं। सचिव की सहायता के लिए एक विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए), एक अतिरिक्त सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार होते हैं। इनके अलावा निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ पीपीएस/पीएसओ स्तर पर 21 अधिकारी, अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस स्तर पर 36 अधिकारी, 68 सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/पीएस स्तर के अधिकारी और 290 अराजपत्रित अधिकारी/पदधारी होते हैं।

सूचना विभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों की प्रस्तुति और व्याख्या, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीति निर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 को लागू करने एवं भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के कैडर प्रबंधन और मंत्रालय के सामान्य प्रशासन का प्रभारी है।

प्रसारण विभाग, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अनुरूप आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकलापों की देखरेख करता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीए ऑपरेटरों को संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन को भी नियंत्रित करता है।

फ़िल्म विभाग सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फ़िल्म उद्योग से संबंधित मुद्दों; वृत्तचित्रों के निर्माण तथा वितरण, फ़िल्मों के संरक्षण; अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सवों के आयोजन और अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने इत्यादि संबंधी कार्य करता है।

मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित मामले, एकीकृत वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आर्थिक विभाग योजना, बजट, योजना समन्वय, ओ एंड एम गतिविधियों के अलावा समय-समय पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय को विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचित करता है। आर्थिक सलाहकार के कार्यों में शामिल हैं- शासन पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ (एसजीओएस-09), इलेक्ट्रॉनिक्स

तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर-मंत्रालयी समूह के लिए नोडल अधिकारी और न्यू इंडिया कोड पोर्टल, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठक संबंधी समन्वय, साइबर सुरक्षा कानून तथा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल की निगरानी से संबंधित कार्य आदि।

पिछले वर्ष, मंत्रालय के कार्यों में ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया। मंत्रालय को आवंटित कार्य विनियम, 1961 में संशोधन संबंधी 9 नवम्बर, 2020 को जारी केन्द्र सरकार की अधिसूचना को देखते हुए ऐसा किया गया।

22ए. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा फ़िल्मों एवं ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना।

22बी. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रमों की सामग्री।

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)
3. भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)
4. प्रकाशन विभाग
5. न्यू मीडिया विंग
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. फ़िल्म प्रभाग
8. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)
9. भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (एनएफएआई)
10. फ़िल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
3. भारतीय बाल फ़िल्म सोसायटी (सीएफएसआई)

शैक्षणिक संस्थान

1. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
2. भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2021 को वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री श्री गुयेन मान हंग के साथ डिजिटल मीडिया में सहयोग पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर आज़ादी का अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के एक भाग के रूप में 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में "संविधान का निर्माण" और फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी "चित्रांजलि@75" पर वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए।

2 प्रमुख झलकियां

नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) और कोविड-19 टीकाकरण अभियान

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के साथ-साथ, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी और भ्रामक जानकारी के कारण होने वाले 'इन्फोडेमिक' से निपटने के लिए गतिविधियों की श्रृंखलाओं का आयोजन और संचालन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोविड-19 महामारी के दौरान संचार और जागरूकता पैदा करने में सबसे आगे रहा है। लोगों की भागीदारी के साथ **जन आंदोलन**, आदतों तथा व्यवहार में परिवर्तन, संचार और केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, निजी मीडिया, सोशल मीडिया आदि सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वित अभियान पर जोर दिया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों को व्यापक कवरेज और दृश्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया। माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री की राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बातचीत में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड उपयुक्त व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने और टीकाकरण का आग्रह, **माननीय प्रधानमंत्री का 'टीका उत्सव'** - कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण का आह्वान, सभी **भारतीय नागरिकों के लिए मुफ़्त टीका** और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सह-रुग्णता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक की घोषणा, **पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन** के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा, **कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव** में उनका संबोधन और विश्व स्तर पर कोविन को खुला स्रोत बनाने, टीकाकरण का 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर उनके भाषण और कोविड-19 से संबंधित अन्य अपीलों तथा घोषणाओं को न्यू मीडिया विंग और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने व्यापक रूप से कवर किया।

डीडी न्यूज, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) और उनकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड-19 पर सरकार की पहलों का प्रसार किया है। डीडी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट, अपडेट, चर्चा, **टीका लगवाने वाले लोगों के बाइट, साक्षात्कार** और 'डॉक्टर्स स्पीक' के माध्यम से शीर्ष विशेषज्ञ डाक्टरों के

साथ **लाइव फोन-इन, 'आरोग्य भारत', 'टोटल हेल्थ' और 'कोरोना से जंग जीतेंगे हम', 'कोरोना पर वार टीकाकरण 100 करोड़ के पार'** सहित कई अन्य दैनिक/साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए। **'दवाई भी कड़ाई भी'** के संदेश को फैलाने के लिए लक्षित अभियान **'मास्क अप इंडिया'** को हैशटैग *#Unite2FightCorona* का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया है। ओमिक्रॉन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए **'ओमिक्रॉन पर सरकार की तैयारी', 'आप भी रहें सतर्क और सावधान'** तथा अन्य विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। **म्यूकोर्मिकोसिस** पर आशंकाओं को दूर करना, प्रख्यात डॉक्टरों की विशेषज्ञ सलाह; **मेडिकल ऑक्सीजन, वैक्सीन की खुराक, रेमडेसिविर और एम्फोटेरिसिन-बी की शीशियों की आपूर्ति** के बारे में जानकारी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली **विदेशी सहायता; 'सुर्खियों में'** खंड के तहत भारत और विदेशों से कोविड-19 पर सकारात्मक कहानियों आदि पर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विभिन्न विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) ने आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई अभियान शुरू किए जैसे- **'दवाई भी कड़ाई भी'** और **'सफाई दवाई और कड़ाई: जीतेंगे कोरोना से लड़ाई'** और **'सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन।'** चार राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया गया। आम जनता के बीच डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से **'सब के लिए टीका, मुफ्त टीका'** विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। 100 करोड़ टीकाकरण को चिह्नित करने के लिए एक विशाल अभियान चलाया गया था, जिसका विषय था **'लक्ष्य विशाल उपलब्धि बेमिसाल - भारत द्वारा 100 करोड़ टीकाकरण का सफर'**। संदेश के व्यापक प्रसार के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के साथ बीओसी ने भी सहयोग किया। इसके तहत **50,000** से अधिक होर्डिंग/बैनर लगाए गए।

प्रकाशन विभाग ने महामारी पर प्रमाणिक जानकारी देने वाली विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखित पुस्तक- **कोविड-19 महामारीः इतिहास, विज्ञान और समाज** का प्रकाशन किया। कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराक देने की राष्ट्रीय उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए देश भर के सिनेमाघरों के साथ **'100 करोड़ से 100 प्रतिशत कोविड-19 वैक्सीन'** शीर्षक वाला एक पीएसए वीडियो साझा किया गया।

न्यू मीडिया विंग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान, कोविड टीके/म्यूकोर्मिकोसिस/डेल्टा प्लस वेरिएंट/बाल स्वास्थ्य कोविड प्रबंधन प्रयासों, **हर घर**

डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाला दैनिक कार्यक्रम 'कोरोना से जंग जीतेंगे हम'

दस्तक, 100 करोड़ टीकाकरण अभियान आदि के बारे में, **समर्पित हैशटैग #We4Vaccine** और **#VaccinationForAll** का इस्तेमाल करते हुए व्यापक कवरेज प्रदान किया गया। कोविड उपयुक्त व्यवहार और नए वेरिएंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए रचनात्मक वीडियो/इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से कोविड-19 के बारे में संदेशों को समर्पित ट्विटर हैंडल **@COVIDNewsByMIB** के माध्यम से साझा किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर उनसे कोविड-उपयुक्त व्यवहार, पात्र व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी प्रसारित करके **'दवाई भी कड़ाई भी'** के संदेश पर अधिक जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।

आज़ादी का अमृत महोत्सवः भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष

आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 साल और अपने लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर **आत्मनिर्भर भारत** की भावना से प्रेरित भारत 2.0 को सक्रिय करने की शक्ति और क्षमता भी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 मार्च, 2021 को भारत की **'आज़ादी का अमृत महोत्सव'** अभियान शुरू किए जाने के बाद से इसके तहत गतिविधियां चला रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **आज़ादी का अमृत महोत्सव के 25 दिवसीय कर्टेन रेज़र** कार्यक्रम का उद्घाटन और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा समापन, को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों द्वारा सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कवर/स्ट्रीम किया गया था। डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार बुलेटिन, विशेष कार्यक्रम, पैकेज, स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से विशेष प्रचार अभियान चलाया गया।

भारत के लोगों के संघर्षों और बलिदानों की स्मृति में **14 अगस्त को विभाजन की भयावहता के स्मरण दिवस** के रूप में घोषणा, **भारत छोड़ो आंदोलन** के प्रतिभागियों को श्रद्धांजलि और संग्रहालय गैलरियों सहित **जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर के उद्घाटन** को दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर व्यापक रूप से कवर किया गया था।

बीओसी ने **41 फोटो प्रदर्शनियों** का आयोजन किया, जिनमें स्वतंत्रता के लिए देश भर में संघर्ष की प्रमुख घटनाओं को दिखाया गया। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग ने हैदराबाद और गुजरात में **पुस्तक प्रदर्शनियों** का आयोजन किया और अपनी पत्रिकाओं में इस बारे में लेख प्रकाशित किए। पत्र सूचना कार्यालय ने माननीय संस्कृति मंत्री के एक **विशेष लेख** को अखिल भारतीय प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराया। इसे 40 से अधिक राष्ट्रीय दैनिक और 90 क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

संविधान की रचना को दर्शाने वाली एक डिजिटल-फोटो प्रदर्शनी **'मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन'** और भारतीय सिनेमा के 75 वर्षों का प्रतिनिधित्व करने वाली आभासी फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी **'चित्रांजलि@75'** का उद्घाटन किया गया था। इसका डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारण किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम पर एक प्रदर्शनी साल भर चली, जो **जन-भागीदारी** की दिशा में एक कदम है।

विभिन्न राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर एक विशेष **शृंखला *'आज़ादी के रंग'*** और **'ऑपरेशन पोलोः द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद'** पर एक विशेष कार्यक्रम डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर प्रसारित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाने वाला विशेष खंड ***'आज़ादी का सफर'*** तथा ***'स्वतंत्रता की गाथा'*** और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कवर करने वाली अभिलेखीय सामग्री पर ***'डीडी दस्तावेज़'*** का प्रसारण डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर किया गया है। सरदार पटेल और नेताजी के **भाषणों के संक्षिप्त अंशों का उनकी आवाज में प्रसारण** किया गया और **विभिन्न मंत्रालयों के आइकॉनिक सप्ताह समारोह** का भी प्रसारण किया गया है।

प्रकाशन विभाग ने अंग्रेजी में *द स्टोरी ऑफ पार्टीशन* और *द स्टोरी ऑफ रीहैबिलिटेशन*, हिंदी में *भारत विभाजन की कहानी, ज़ब्तशुदा गीत, ज़ब्तशुदा तराने, नेताजीः ए लाइफ इन पिक्चर्स एवं द वारियर डेमोक्रेटः श्यामा प्रसाद मुखर्जी* पुस्तकें प्रकाशित कीं।

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म/मृत्यु वर्षगांठ को हैशटैगः **#HonouringIndianLegends** का उपयोग करते हुए विशेष शृंखला में शामिल किया गया है। श्री गुरु

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक के अंतर्गत 'संविधान का निर्माण' और फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी 'चित्रांजलि@75' पर वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, श्रीमती मीनाक्षी लेखी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं।

तेग बहादुरजी और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर न्यू मीडिया विंग द्वारा तैयार किए गए विभिन्न ग्राफिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए गए थे।

बीओसी 13 सितंबर, 2021 से **व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर इन्फोग्राफिक श्रृंखला** चला रही है। दिसंबर 2021 के दौरान, इस इन्फोग्राफिक श्रृंखला के माध्यम से **38 गुमनाम नायकों को याद** किया गया, इस प्रकार **दिसंबर 2021 तक कुल 115 गुमनाम नायकों** को स्मरण किया गया।

फ़िल्म प्रभाग ने 2 और 3 अक्टूबर, 2021 को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल (1,179 ऑनलाइन दर्शक) पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए **'शत-शत नमन'** फ़िल्म समारोह का आयोजन किया। **'आज़ाद हिंद दिवस'** को चिह्नित करने के लिए, फ़िल्म प्रभाग ने 21.10.2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक्स और आईएनए की झांसी रेजिमेंट की रानी के एक सैनिक पर एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया।

फ़िल्म प्रभाग ने 28 से 30 नवंबर, 2021 तक अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उल्लेखनीय जनजातीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की समृद्ध संस्कृति, विरासत और योगदान को प्रदर्शित करते हुए **'पूर्वोत्तर के रंग' फ़िल्म महोत्सव** का भी आयोजन किया। प्रभाग ने **लाला लाजपत राय** की पुण्यतिथि और **महारानी लक्ष्मीबाई** की जयंती पर उनके नाम पर बायोपिक्स की स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया। भारतीय बाल फ़िल्म सोसायटी (सीएफएसआई) ने भारत भर में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से **देशभक्ति की फ़िल्मों के 38 शो** आयोजित किए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आइकॉनिक सप्ताह

मंत्रालय ने **23 से 29 अगस्त, 2021 तक अपने आईकॉनिक सप्ताह** के उत्सव के दौरान **'जन-भागीदारी** और **जन आंदोलन'** की समग्र भावना के तहत सहक्रियात्मक और अभिनव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की।

- डीडी न्यूज ने कई **विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला** का प्रसारण किया, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर ***'हम हैं प्रतिबद्ध'***, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ***'नए भारत का सफर'*** और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अभिलेखीय सामग्री पर ***'डीडी दस्तावेज़'***।

- डीडी नेटवर्क ने 'नेताजी', 'रियासतों का विलय' आदि जैसे वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला और 'राज़ी' जैसी लोकप्रिय भारतीय फ़िल्मों का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए डीडी न्यूज/इंडिया पर विशेष खंड ***'आज़ादी का सफर'*** और ***'सागा ऑफ फ्रीडम'*** का प्रसारण किया जा रहा है।

- आकाशवाणी ने एक अनूठा दैनिक कार्यक्रम ***'आज़ादी का सफर, आकाशवाणी के संग'***- *'टुडे इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल'* सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों में 16.08.2021 से शामिल किया। ***राष्ट्रीय और क्षेत्रीय*** **'अमृत महोत्सव थीम क्विज़'** 75 एपिसोड का आयोजन क्रमशः 05.08.2021 और 16.08.2021 से किया गया।

- आकाशवाणी ने **कई विशेष लघु साप्ताहिक कार्यक्रम** शुरू किए, जैसे कि धरोहर, अपराजिता, निशान, द अनसंग हीरोज़, आज़ादी के तराने, आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला आदि।

- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म www.cinemasofindia.com पर 'आइलैंड सिटी', 'क्रॉसिंग ब्रिजेज़ आदि जैसी विशेष रूप से क्यूरेट की गई फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के लिए एक फ़िल्म समारोह का आयोजन किया।

- फ़िल्म प्रभाग ने **भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर फ़िल्मों की विशेष स्क्रीनिंग** (3,192 दर्शक) का आयोजन किया और **'आज़ादी का अमृत महोत्सव फ़िल्म महोत्सव'** में 15 से 17 अगस्त, 2021 तक स्वतंत्रता संग्राम पर 20 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर की। **दो फ़िल्म समारोह** यानी 'ए वॉयोज ऑफ प्रोग्रेस' तथा 'भारत के रत्न' और फ़िल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति पर एक **वेबिनार** भी 23 से 29 अगस्त, 2021 के बीच आयोजित किया गया था।

- फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने **भारत में अन्य देशों के विभिन्न दूतावासों में फ़िल्मों** की स्क्रीनिंग के लिए विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग किया।

- **भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार** (एनएफएआई) ने 23 से 29 अगस्त, 2021 तक अपनी वेबसाइट पर **क्लासिक सिनेमा पर एक लाइव वर्चुअल फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी** आयोजित की।

- बीओसी **88 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों** (आईसीओपी), **लोक संचार प्रभाग के माध्यम से 1,016 सांस्कृतिक कार्यक्रमों**, 500 से अधिक समाचार पत्रों और कई निजी क्षेत्रीय टीवी चैनलों में क्षेत्रीय भाषाओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर गतिविधियों की कवरेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। बीओसी के आरओबी ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर फ्रीडम वॉक/फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। इन गतिविधियों में गणमान्य व्यक्तियों- राज्यपाल और उपराज्यपाल और केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों ने भाग लिया।

- बीओसी ने देश भर के 1,700 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में **आधे पृष्ठ का रंगीन प्रिंट विज्ञापन** जारी किया, जिसमें पहली बार एक **क्यूआर कोड के माध्यम से एक वीडियो एम्बेड** किया गया था। बीओसी ने **'मेकिंग आर्फ द कॉन्स्टीट्यूशन'** पर एक ई-पुस्तक का भी लोकार्पण किया।

- **'संकल्पित भारत सशक्त भारत'** के विषय पर **न्यू इंडिया समाचार (एनआईएस)** के अगस्त 2021 पाक्षिक संस्करण को 13 भाषाओं में प्रकाशित किया गया और बीओसी द्वारा देश भर में वितरित किया गया। MyGov India के ई-संपर्क प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से एनआईएस के ई-संस्करण, 65 मिलियन से अधिक पाठकों तक पहुंचाए गए थे।

- प्रकाशन विभाग ने 20.08.2021 से 04.09.2021 के बीच कोलकाता, मुंबई, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली मुख्यालय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक भारत के निर्माताओं आदि पर कई **पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन** किया। MyGov प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता एवं **पुस्तक कवर डिजाइन प्रतियोगिता** का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

- प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं में विशेष लेखों के अलावा,

सोशल मीडिया हैंडल पर **जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशेष श्रृंखला** चलाई गई। न्यू मीडिया विंग द्वारा तैयार किए गए ग्राफिक्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस

राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 के अवसर पर विभिन्न मीडिया इकाइयों ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। फ़िल्म प्रभाग ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर ***'लौह पुरुष सरदार पटेल'*** शीर्षक से एक बायोपिक की अपनी वेबसाइट तथा यूट्यूब चैनल पर स्क्रीनिंग की और दूरदर्शन ने भी इसका प्रसारण किया। आकाशवाणी पर प्रतिष्ठित वार्षिक **सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान,** भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 'राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका' पर दिया था। राष्ट्रीय एकता दिवस विषय पर पूरे देश में बीओसी के आरओबी/एफओबी द्वारा **52 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)** आयोजित किए गए थे। *'एक भारत श्रेष्ठ भारत'* विषय पर **7 आईसीओपी** और **3 वेबिनार** आयोजित किए गए। प्रकाशन विभाग ने सरदार पटेल पर शीर्षकों को प्रदर्शित करते हुए पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया और अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए स्लोगन **लेखन प्रतियोगिता** को प्रोत्साहन दिया।

जनजातीय गौरव दिवस

प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने **भगवान बिरसा मुंडा** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने में देश का नेतृत्व किया और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। डीडी न्यूज और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने इस कार्यक्रम की व्यापक कवरेज की और प्रचार किया। रांची में **भगवान बिरसा मुंडा उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन** समारोह को दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर कवर किया गया था। डीडी न्यूज पर विशेष चर्चा आधारित कार्यक्रम **'जनजातियों की गौरवगाथा', 'जनजातीय गौरव दिवस'** और माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री के विशेष साक्षात्कार की एक श्रृंखला प्रसारित की गई। डीडी न्यूज ने **45 मिनट की एक फ़िल्म** भी तैयार की जो **'जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन'** के दौरान दिखाई गई थी। न्यू मीडिया विंग ने **ग्राफिक्स, वीडियो, पोस्ट और यूट्यूब वीडियो** के माध्यम से व्यापक सोशल मीडिया कवरेज/प्रचार किया। फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब पर भारत की विभिन्न जनजातियों पर छह फ़िल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। बीओसी ने इस विषय पर **09 एकीकृत संचार तथा आउटरीच कार्यक्रम 'आईसीओपी'** तथा **08 वेबिनार** आयोजित किए और समूचे भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में एक पूर्ण पृष्ठ रंगीन प्रिंट विज्ञापन जारी किया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना में **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** पर आरओबी, बीओसी द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 12 से 14 दिसंबर, 2021 तक आयोजित प्रदर्शनी में युग्मित राज्यों हरियाणा और तेलंगाना के विभिन्न दिलचस्प पहलुओं जैसे कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि पर प्रकाश डाला गया।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान पर बेहतर ध्यान देने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय ने अक्टूबर 2021 से एक नई कार्यनीति अपनाई। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' प्रारूप के अनुसार जोड़े में व्यवस्थित किया गया है। राज्यों की प्रत्येक जोड़ी को एक गहन केंद्रित अभियान चलाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इस अभियान में विभिन्न गतिविधियों जैसे लेखों का प्रकाशन, सोशल मीडिया गतिविधियां, वेबिनार, प्रेस टूर या किसी अन्य गतिविधि से संबंधित अभियान में दृश्यता उत्पन्न करने के लिए युग्मित राज्यों के संबंध में अन्य गतिविधियां चलाना शामिल है। पहली जोड़ी अक्टूबर माह के दौरान गुजरात और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालयों की थी। दोनों क्षेत्रों ने प्रेस टूर, लेखों के प्रकाशन, वेबिनार, सोशल मीडिया गतिविधियों, प्रेस विज्ञप्तियों, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रमों सहित महीने के दौरान सफलतापूर्वक 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की।

52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव

52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफ आई) का आयोजन फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ),

माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु 12 दिसंबर, 2021 को हैदराबाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 20 से 28 नवंबर, 2021 तक पणजी, गोवा में हाइब्रिड तरीके से (वास्तविक और आभासी) किया गया था। इसमें **300 से अधिक फ़िल्मों** का प्रदर्शन किया गया, जिसमें **73 देशों की 148 फ़िल्में** थीं। दुनिया भर से **10,000 से अधिक प्रतिनिधियों** ने हाइब्रिड प्रारूप में भाग लिया। महोत्सव में 12 वर्ल्ड प्रीमियर, 36 एशिया प्रीमियर, 64 इंडिया प्रीमियर और 7 इंटरनेशनल प्रीमियर हुए। अभिनेत्री और सांसद ***सुश्री हेमा मालिनी*** और जाने माने गीतकार तथा सीबीएफसी के अध्यक्ष, **श्री प्रसून जोशी को इंडियन फ़िल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021** प्रदान किया गया।

प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच **भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने** और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए **एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए**। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से, दूरदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों/संगीत कार्यक्रमों/नृत्य के प्रदर्शन पर आधारित साप्ताहिक आधे-आधे घंटे के 52 एपिसोड का निर्माण करेगा।

सत्यजीत रे जन्म शताब्दी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महान फ़िल्म निर्माता **श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य** में समूचे भारत और विदेशों में साल भर के समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक कर्टेन रेज़र वीडियो लॉन्च किया गया। सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने एक **लोगो तैयार** एवं लॉन्च किया। **एक समर्पित वेबसाइट raytoday.in** भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में सरकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों को प्रदर्शित करना है। फ़िल्म प्रभाग ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित **बायोपिक 'सत्यजीत रे'** की स्क्रीनिंग की, उसके बाद **तीन दिवसीय फ़िल्म फेस्टिवल 'रे टुडे'** अपनी वेबसाइट पर 7 से 9 मई, 2021 तक आयोजित किया जिसमें उनकी फ़िल्मों का एक क्यूरेटेड पैकेज प्रदर्शित किया गया। इसके ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 12,661 दर्ज की गई। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म **www.cinemasofindia.com.** पर 2 से 5 मई, 2021 के बीच ***'सत्यजीत रे फ़िल्म महोत्सव 2021'*** का आयोजन किया।

प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अधिकारियों ने 20 दिसंबर, 2021 को भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

'सेवा और समर्पण: 20 साल सुशासन के' पर समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी द्वारा विशेष कार्यक्रम

सेवा समर्पण अभियानः सुशासन के 20 साल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले 20 वर्षों में की गई विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल देते हुए **सेवा समर्पण अभियान** के दौरान संचार के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है। विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा **सोशल मीडिया** पर 20 दिनों तक **व्यापक अभियान** चलाया गया।

दूरदर्शन (डीडी) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा को समर्पित चर्चाओं, विशेष साक्षात्कारों, कार्यक्रमों, विशेष कार्यक्रम श्रृंखला– **''सेवा समर्पण : सुशासन के 20 साल''** सहित सेवा समर्पण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को व्यापक रूप से कवर किया। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों और पहलों को रेखांकित करने के लिए **देश की बात डीडी न्यूज के साथ** जैसे **डीडी कॉन्क्लेव** आयोजित किए गए। इस नेटवर्क ने देश के विकास से संबंधित विविध विषयों पर आयोजित **फिक्की के वेबिनारों** को भी कवर किया। सभी कार्यक्रम **यूट्यूब** और अन्य **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों** के माध्यम से साझा किए गए।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने **''स्पॉटलाइट – सेवा और समर्पणः 20 साल सुशासन के''** जैसे समाचारों और विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया। **एफएम गोल्ड** और क्षेत्रीय भाषाओं में **आकाशवाणी के सभी प्राथमिक चैनलों** ने एक विशेष कार्यक्रम **''कर्मयोगी नरेन्द्र मोदी''**– प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की घटनाओं पर आधारित बायोपिक का प्रसारण किया। जनता तक पहुंच बनाने के लिए **यूट्यूब** और अन्य **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों** का इस्तेमाल किया गया।

पीआईबी ने कई विशेष लेख अधिकृत किए। ये लेख देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। **इनमें माननीय प्रधानमंत्री का एक विशेष लेख** *'टीम इंडिया – रिस्पॉन्डिंग टू एडवर्सिटी विद अचीवमेंट'* तथा केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय उपलब्धियों पर लिखे गए विशेष लेख शामिल हैं।

एनएमडब्ल्यू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस अभियान के संबंध में विभिन्न **स्टेटिक एंड कोट ग्राफिक्स, वीडियो, मोशन ग्राफिक्स और रील** तैयार और पोस्ट किए। इन 20 दिनों में **@MIB&India** से लगभग 152 ट्वीट किए गए, जिनमें पीएम के उद्धरण, हाइलाइट वीडियो और दिलचस्प **इन्फोग्राफिक्स** शामिल रहे। जनता तक पहुंच बनाने के लिए **बीओसी** ने विभिन्न **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स** का भी इस्तेमाल किया।

इस अभियान के तहत इन सभी गतिविधियों को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गई और उसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

पराक्रम दिवस

फ़िल्म प्रभाग ने 23.01.2022 को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल (दर्शकों की संख्या 4960) पर फ़िल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया और सीएफएसआई द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों में लगभग 200 बच्चों के लिए कई स्थानों पर इसकी फ़िल्म के 8 शो भी प्रदर्शित किए गए। एनएसडीः आकाशवाणी ने 23.01.2022 को विशेष कार्यक्रम 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम गाथा' – आकाशवाणी के साथ सुर्खियों में और स्पॉटलाइट में 'लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस' प्रसारित किया।

नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के सहयोग से प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित एक नयी पुस्तक *नेताजी – अ लाइफ इन पिक्चर्स* का 23.01.2022 को विमोचन किया गया। डीपीडी द्वारा 'नेताजी–अ लाइफ इन पिक्चर्स' और राष्ट्रीय युवा दिवस पर लघु वीडियो भी तैयार किए गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए।

राष्ट्रीय युवा दिवस

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर फ़िल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया तथा डीपीडी ने 10 जनवरी, 2022 से 13 जनवरी, 2022 तक अहमदाबाद में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म www.cinemasofindia.com पर सीएफएसआई की फीचर फ़िल्म *त्रियात्री* का प्रदर्शन किया। बीओसी के आरओबीएस/एफओबीएस ने 'राष्ट्रीय युवा दिवस' विषय पर 19 आईसीओपीएस, 14 वेबिनार और 10 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए। एनएसडीः आकाशवाणी ने 12 जनवरी, 2022 को परिक्रमा में *स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं* पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना

माननीय प्रधानमंत्री ने **भारत-बांग्लादेश संबंधों की 50वीं वर्षगांठ** के अवसर पर मार्च, 2021 में बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा की और बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री के साथ 'मैत्रीसेतु' का आभासी रूप से उद्घाटन किया। इस यात्रा को डीडी ने व्यापक रूप से कवर किया।

बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री की 8 अप्रैल, 2017 की यात्रा के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दोनों देश **'बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों' पर एक फ़िल्म का निर्माण** करने पर सहमत हुए हैं। इस फ़िल्म का निर्माण एनएफडीसी और फ़िल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन, बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। **''1971 में बांग्लादेश की मुक्ति''** विषय पर एक वृत्तचित्र फ़िल्म का सक्रिय रूप से निर्माण करने पर भी सहमति बनी।

दुबई एक्सपो में भागीदारीः दुबई एक्सपो में भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन सप्ताह का उद्घाटन अभिनेता आर. माधवन ने किया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल भारत से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परियोजना तेजस (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स) का शुभारंभ किया। माननीय मंत्री ने भारतीय मंडप में *भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की वैश्विक* पहुंच विषय पर बातचीत की।

ओलंपिक 2020

ओलंपिक खेलों की भावना को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित करने के साथ-साथ पिछले सात वर्षों के दौरान इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सक्रिय अभियान चलाया गया।

टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालम्पिक्स 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत और पदक विजेताओं को उनकी बधाई को **'विक्ट्री पंच कैम्पेन'** और ***#चीयर4इंडिया*** के माध्यम से डीडी न्यूज और एनएसडीः एआईआर द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। **ओलंपिक में मिली सफलताओं की सुगम और लाइव** कवरेज का डीडी स्पोर्ट्स और एआईआर स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। प्रसार भारती ने **14 सांकेतिक भाषा कलाकारों** की सेवाएं लीं, जिन्होंने 240 घंटे की ओलंपिक लाइव कवरेज को सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया और विभिन्न ओलंपिक आयोजनों के लिए आकाशवाणी के 16 कमेंटेटरों की सेवाएं ली गईं। भारत की शीर्ष खेल हस्तियों, जीवनियों आदि पर एक विशेष **वर्चुअल कॉन्क्लेव** का आयोजन किया गया।

उद्घाटन और समापन समारोहों का सीधा प्रसारण किया गया और **दैनिक विशेष कार्यक्रमों** अर्थात 'काउंटडाउन टू टोक्यो', 'टोक्यो 2020ः द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स', इंडिया@ टोक्यो, #चीयर4इंडिया, ओलंपिक हाइलाइट्स, 'सुपर सेवन ऑफ इंडिया' आदि का डीडी चैनलों पर प्रसारण किया गया। एनएसडीः एआईआर द्वारा विशेष ओलंपिक शृंखलाएं, ओलंपिक क्विज, कर्टन रेज़र, चीयर4इंडिया अभियान, विशेष साक्षात्कार, विशेष चर्चा कार्यक्रम 'सुखियों में', 'स्पॉटलाइट' आदि प्रसारित किए गए।

माननीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री द्वारा *'सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियाज गोल्ड क्वेस्ट'* शीर्षक से लिखा गया एक **विशेष लेख** पीआईबी द्वारा अधिकृत किया गया और देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। एनएमडब्ल्यू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **#चीयर4इंडिया के लिए ग्राफिक्स और वीडियो** तैयार और पोस्ट किए।

न्यू इंडिया समाचार का जुलाई 2021 का पाक्षिक संस्करण **'खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया'** थीम पर प्रकाशित किया गया। बीओसी ने गीतों, नारों, प्रश्नोत्तरी, वीडियो आदि के माध्यम से सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए एक **व्यापक मीडिया अभियान** चलाया। आरओबी/एफओबी ने प्रमुख स्थानों पर **सेल्फी बूथ फॉर #चीयर4इंडिया** स्थापित किए। एनएफडीसी ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अधिकृत ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले **41 खिलाड़ियों/टीमों पर लघु फ़िल्मों का निर्माण** किया।

आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को दिनांक 25.02.2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया। शिकायत निवारण तंत्र के भाग के रूप में, मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कन्टेंट के प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए **चार स्तरीय द्वितीय स्व-नियामक निकाय पंजीकृत** किये हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दल से बातचीत की।

मंत्रालय ने प्रमुख हितधारकों के बीच **जागरूकता बढ़ाने और इन नियमों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने के लिए** कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने ब्रीफिंग्स के माध्यम से त्वरित कदम उठाकर इन नियमों के प्रबंधन से संबंधित गलतफहमियों को दूर किया है।

उक्त नियमों में प्रावधान है कि समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक और ऑनलाइन क्यूरेटेड कन्टेंट के प्रकाशक मंत्रालय को सूचना प्रदान करें। मंत्रालय ने दिनांक 26 मई, 2021 के सार्वजनिक नोटिस पर, नियम 18 के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करने वाले डिजिटल मीडिया के **1,800 से अधिक प्रकाशकों** को पावतियां भेजी हैं। इन नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब तक लगभग **दस राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वेबिनार** आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें **2,200 से अधिक हितधारकों** की प्रत्यक्ष भागीदारी रही है। इन वेबिनारों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी और सीख के बारे में 'अवेयरनेस इनिशिएटिव्स एंड वेबिनार्स ऑन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड' शीर्षक से एक **पुस्तिका** प्रकाशित की गई है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

संविधान दिवस

कॉन्स्टीट्यूशन डे, जिसे *'संविधान दिवस'* के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने (26 नवंबर, 1949) की याद में और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

डीडी न्यूज द्वारा एक विशेष कार्यक्रम **'भारत का संविधान'** और **'इन फोकस'** और **'डीडी दस्तावेज़'** शो के विशेष एपिसोड का प्रसारण किया गया। 19 से 26 नवंबर, 2021 तक एनएसडीः एआईआर द्वारा अपने सभी प्राइम टाइम बुलेटिनों में **'नो योर कॉन्स्टीट्यूशन'** नामक एक विशेष श्रृंखला के तहत थीम आधारित रिपोर्ट/कैप्सूल प्रसारित किए गए। फ़िल्म प्रभाग ने 26 नवंबर, 2021 को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर **भारत के संविधान पर फ़िल्मों की स्क्रीनिंग** का आयोजन किया। **सीएफएसआई** ने शिक्षा और समानता के अधिकार पर जोर देने वाली बाल फ़िल्म 'बंडू बॉक्सर' के **26 शो की स्क्रीनिंग** कई स्थानों पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/

संगठनों के सहयोग से की। एनएमडब्ल्यू द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक समर्पित हैशटैगः **#कॉन्स्टीट्यूशनडे** का उपयोग कर लगभग **4 वीडियो, 21 ग्राफिक्स और प्रति 25 पोस्ट** किए गए। बीओसी ने इस विषय **पर 34 आईसीओपी** और **10 वेबिनार** भी आयोजित किए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस अवसर पर महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न **प्रतियोगिताओं** (निबंध लेखन, पोस्टर बनाना, नारा लेखन और एमसीक्यू) का आयोजन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी, फ़िल्मों की स्क्रीनिंग, वेबिनार, कार्यशाला, सेमिनार, वार्ता आदि जैसे **विशेष कार्यक्रम आयोजित** किए।

प्रसार भारती ने महिलाओं पर केंद्रित मुद्दों को रेखांकित करने के लिए अनेक विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया। डीडी न्यूज द्वारा *'वीमेन विल–गूगल फॉर इंडिया इवेंट'* का सीधा प्रसारण किया गया, जहां माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने वेबिनार को संबोधित किया। डीडी न्यूज और एनएसडीः एआईआर द्वारा महिला युद्ध सेनानियों के साथ **विशेष साक्षात्कार शृंखला,** महिला सेना अधिकारियों पर विशेष कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं पर आधारित **ग्राउंड रिपोर्ट्स** और **सफलता की कहानियां**, नियमित कार्यक्रमों के विशेष संस्करण आदि प्रसारित किए गए। फ़िल्म प्रभाग द्वारा तीन दिवसीय **ऑनलाइन फ़िल्म समारोह** का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 3,537 दर्ज की गई। एनएमडब्ल्यू ने कामयाब भारतीय महिलाओं की सफलता का जश्न मनाने के लिए **वीडियो और ग्राफिक्स** की एक शृंखला निर्मित की और उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया।

डीपीडी द्वारा प्रकाशित 'आजकल' ने मार्च 2022 का अंक 'स्त्री–लेखन की दिशा और चुनौतियां' विषय पर विशेषांक

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 07 सितम्बर, 2021 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद से मुलाकात के दौरान उनका अभिनदंन करते हुए।

के रूप में प्रकाशित किया। पाक्षिक *न्यू इंडिया समाचार* (एनआईएस) के मार्च 2022 संस्करणों में से एक की कवर स्टोरी 'वीमेन पावर बीइंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन' थी।

7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध पर और योग की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर, 2014 को, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) घोषित किया। पिछले छह वर्षों में, आईडीवाई स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक विश्वव्यापी मुहिम का रूप ले चुका है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम और प्रबंधन में योग द्वारा प्रदान किए जाने वाले विविध समाधानों के मद्देनजर, वर्तमान में जारी स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए 2021 में आईडीवाई मनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा।

आईडीवाई पर **माननीय उपराष्ट्रपति की शुभकामनाओं और माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन** और **एमयोग ऐप की घोषणा** का मंत्रालय के सभी प्लेटफार्मों पर सीधा प्रसारण किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए योग सत्र/प्रदर्शन/कक्षाएं और अन्य उपयुक्त गतिविधियां आयोजित की गईं।

डीडी न्यूज ने भारत और दुनिया भर के **75 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों से योगाभ्यास** की लाइव फुटेज प्रसारित की। डीडी न्यूज ने विशेष योग प्रशिक्षण कैप्सूल **योग सूत्र, योग मंत्र, योग संवाद**, योग से संबंधित स्थानों से विशेष रिपोर्ट **योग यात्रा** (01) कार्यक्रम **योग सत्र** (02) का निर्माण और प्रसारण किया गया। इसके अलावा योग पर **टोटल हेल्थ** कार्यक्रम के एक एपिसोड और माननीय आयुष राज्य मंत्री के **विशेष साक्षात्कार** का प्रसारण किया। आईडीवाई 2021 के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 22 फेसबुक लिंक, 46 यूट्यूब वीडियो और 175 ट्विटर संदेश पोस्ट किए गए।

डीडी इंडिया ने 12-21 जून, 2021 तक **कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के विभिन्न पहलुओं पर 10-एपिसोड की एक विशेष शृंखला** का प्रसारण किया। प्रसार भारती ने श्री शंकर महादेवन द्वारा रचित विशेष गीत ***'योगारम्भ हो'*** का निर्माण किया है, जिसे डीडी नेशनल और इसके यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के अपना रेडियो ने योग पर **कार्यक्रमों की शृंखला** का प्रसारण किया।

न्यू इंडिया समाचार का जून 2021 का पाक्षिक संस्करण **'योग का वैश्वीकरण'** विषय पर प्रकाशित किया गया। प्रकाशन विभाग ने सुप्रसिद्ध योग विशेषज्ञ श्री धर्मवीर सिंह महिदा द्वारा रचित ***'योग सचित्र'*** के संशोधित संस्करण का पुनःप्रकाशन किया।

फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 'योगा फॉर वेलबीइंग' के संदेश को रेखांकित करते हुए लघु फ़िल्मों ***'सेलिब्रिटीज़ स्पीक...'*** का प्रसारण किया। बीओसी के आरओबी/एफओबी द्वारा सीवाईपी पर **75 वेबिनार** आयोजित किए गए और प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षकों की देखरेख में **25 लाइव योग प्रदर्शन** आयोजित किए गए।

एनएमडब्ल्यू द्वारा विभिन्न योगासनों पर **जीआईएफ की एक शृंखला**, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो कन्टेंट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किए गए। पीआईबी ने माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय आयुष राज्य मंत्री द्वारा लिखे गए **दो विशेष लेखों को देश भर में लगभग 129 प्रकाशनों में** अधिकृत किया।

अन्य आकर्षण

- मंत्रालय ने 20.12.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत में सूचना स्थान को सुरक्षित करने के लिए इंटरनेट पर **भारत विरोधी प्रचार और फेक न्यूज फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों और दो समाचार वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया।** ये चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित थे और भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे थे। उन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खातों को ब्लॉक कर दिया।
- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक **'कोर्ट्स ऑफ इंडिया' (हिंदी)** का जबलपुर उच्च न्यायालय में विमोचन किया गया, जहां माननीय राष्ट्रपति को पुस्तक की पहली प्रति भेंट की गई।
- माननीय उपराष्ट्रपति ने 25 अक्टूबर, 2021 को **67वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2019 प्रदान** किए। ये पुरस्कार गैर-फीचर फ़िल्म खंड में 22 श्रेणियों में तथा फीचर

फ़िल्म खंड में 47 श्रेणियों में प्रदान किए गए। प्रतिष्ठित **दादासाहेब फाल्के पुरस्कार** लोकप्रिय अभिनेता श्री रजनीकांत को प्रदान किया गया।

- **न्यू इंडिया समाचार** के सितंबर 2021 के पाक्षिक संस्करण **'सबका प्रयास बिकम्स द रिज़ॉल्व ऑफ न्यू इंडिया'** और **'डॉन ऑफ अ न्यू इरा - इंडियाज़ अमृत यात्रा ऑफ डेवलपमेंट'** और अक्टूबर 2021 के पाक्षिक संस्करण **'अमृत यात्रा ऑफ इकॉनोमी'** और **'द वैक्सीन बिकम्स द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द नेशन'** विषय पर प्रकाशित हो चुके हैं।

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने **शारजाह, यूएई के एक्सपो सेंटर** में 3 से 13 नवंबर, 2021 तक **आयोजित मेगा बुक फेयर में** अपने प्रकाशन प्रस्तुत किए। दुबई में 03.11.2021 को 40वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले (एसआईबीएफ 2021) में भारत के महावाणिज्य दूत, डॉ अमन पुरी ने वाणिज्य दूत (प्रेस, सूचना, संस्कृति और श्रम) श्रीमती तादु मामू के साथ डीपीडी के मंडप का उद्घाटन किया। डीपीडी ने पाठकों और पुस्तक प्रेमियों के लिए **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों पर 150 से अधिक पुस्तकें** प्रस्तुत की।

- माननीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चौथे वर्ष की गतिविधियों पर डीपीडी द्वारा प्रकाशित पुस्तक ***'रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रीकनेक्टिंग'*** की पहली प्रति 27.08.2021 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को भेंट की गई।

- **कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ** के अवसर पर डीडी न्यूज ने चर्चा पर आधारित आधे घंटे के कार्यक्रम *'दो टूक'* के तहत विशेष कार्यक्रम *'जय जवानः कारगिल विजय दिवस पर जवानों को नमन'* और प्राइम टाइम कार्यक्रम *'कारगिल के रक्षक'* का प्रसारण किया।

- डीडी न्यूज ने 13.12.2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **श्री काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन** और अन्य मुख्य कार्यक्रमों का सीधा और विशेष प्रसारण किया। विशेष **न्यूज नाइट** और **दो टूक** कार्यक्रम का काशी से सीधा प्रसारण किए जाने के अलावा मल्टी कैमरा सेटअप और लाइव कमेंट्री के साथ एक विशेष कार्यक्रम **'काशी - एक नई पहचान'** का प्रसारण किया गया। विशेष कार्यक्रम **'सुबह-ए-बनारस'**, **'बनारस का नया सवेरा'** और **'ब्रेकफास्ट विद् बनारस'** का भी प्रसारण किया गया। पीआईबी ने भी माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा **'काशी विश्वनाथ धाम - ट्रिब्यूट टू ऑवर लिविंग हेरिटेज'** शीर्षक से लिखित एक **विशेष लेख** अधिकृत किया जो राष्ट्रव्यापी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

- **सुशासन दिवस और सप्ताहः** डीडी न्यूज ने माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चेन्नई में दी गई श्रद्धांजलि, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **सदैव अटल** में अर्पित की गई **पुष्पांजलि** और विज्ञान भवन में सुशासन दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। आधे घंटे के विशेष कार्यक्रम **'सुशासन का मंत्र'** और **'सुशासन के केंद्र में अब गांव'**, **'मेरा हक शो'** के विशेष एपिसोड, **'सुशासन सप्ताहः प्रशासन गांव की ओर'** पर **'मोदी सरकार का सुशासन मॉडलः लोक कल्याण का लक्ष्य'** पर **न्यूज नाइट** और अटल बिहारी वाजपेयी पर **डीडी दस्तावेज़ शो** का डीडी न्यूज द्वारा प्रसारण किया गया।

- **2021 में प्रसार भारती के डिजिटल/टीवी दर्शकों की संख्याः** देश भर के डीडी चैनलों ने 6 बिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की और 680 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंच कायम की। डीडी और एआईआर के 185 यूट्यूब चैनलों ने 190 से अधिक देशों में 94 मिलियन घंटे के वॉच टाइम के साथ एक बिलियन से अधिक व्यू दर्ज किए। न्यूजऑनएआईआर ऐप पर 2021 में 190 से अधिक देशों में 214 मिलियन से अधिक श्रोताओं की संख्या दर्ज हुई।

- माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 01.10.2021 को **एक महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम** का प्रयागराज से शुभारंभ किया। इसे युवाओं को शिक्षित और लक्षित करने के लिए एनएमडब्ल्यू द्वारा तैयार और पोस्ट किए गए मीम के माध्यम से सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से कवर किया गया। उन्होंने 14.10.2021 को **माईपार्किंग्स ऐप** भी लॉन्च किया।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए **स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2021** अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 09.09.2021 को बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), फ़िल्म प्रभाग और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) को आभासी रूप से प्रदान किए गए।

- डीडी और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो कार्यक्रमों को हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित **एबीयू-यूनेस्को पीस मीडिया अवाड्र्स 2021** में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन के कार्यक्रम *'डीईएफ़िनिटली लीडिंग द वे'* ने *'लिविंग वेल विद सुपर डायवर्सिटी'* श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता, जबकि एक और पुरस्कार ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम *'लिविंग ऑन द एज-द कोस्टल लाइफ'* ने *'एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर'* की श्रेणी में जीता।

- सामरिक महत्व के स्थानों के लगभग 50 एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटरों के अलावा, प्रसार भारती ने 31 मार्च, 2022 तक शेष अप्रचलित एनालॉग ट्रांसमीटरों को सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में समाप्त कर दिया, क्योंकि यह बिजली की फिजूलखर्ची कम करने के अलावा 5जी के रूप में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराता है।

- बीओसी ने मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश में **मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनियों** की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसके अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ स्वतंत्रता के बाद के विकास पर आधारित सामग्री प्रदर्शित की गई। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 15.03. 2022 को हमीरपुर के निकट सुजानपुर में पहली प्रदर्शनी का उद्‌घाटन किया। धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला प्रदर्शनियों का आयोजन **'भारत की यात्राः स्वराज से विकास तक'** शीर्षक से किया गया। जोधपुर, राजस्थान में एक विशाल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे।

- **भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) को जनता के लिए फिर से खोलने** के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 मार्च, 2022 को फ़िल्म प्रभाग कॉम्प्लेक्स में स्थित एनएमआईसी परिसर में 75 विंटेज कारों और बाइकों की एक सुंदर प्रदर्शनी आयोजित की गई। अभिनेता श्री अक्षय कुमार और सुश्री कृति सैनन ने प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाई। संग्रहालय परिसर में सेल्फी प्वाइंट 'लव सिनेमा' का भी उद्‌घाटन किया गया।

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने फरवरी 2022 में कई पुस्तकें, जैसे **इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 एंड स्टैटिस्टिकल अपेन्डिक्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सरदार पटेल - अ पेट्रिऑटिक बायोग्राफी, बिलीफ इन बैलेट (वॉल्यूम 2)** प्रकाशित की और जागरूकता फैलाई तथा 22-28 फरवरी, 2022 तक सप्ताह भर के **'विज्ञान सर्वत्र पूज्यते'** समारोह में भागीदारी के माध्यम से अपनी पुस्तकों को रेखांकित किया। इस समारोह का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान प्रसार द्वारा डीपीडी और नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) के साथ मिलकर देश भर के दस स्थानों यानी नई दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, पटना, हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद में किया गया था।

- कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में डीपीडी और एफटीआईआई ने एक विशेष पुस्तक ***बैलेंसिंग द विज्डम ट्री*** **- एंथोलॉजी ऑफ एफटीआईआईज़ वूमन अलम्नाई** का विमोचन किया।

- एनएमडब्ल्यू द्वारा दो नई वीडियो श्रृंखलाएं : प्रसार भारती की अभिलेखीय सामग्री पर केंद्रित **#मोमेंट्सफ्रॉमहिस्ट्री** और पद्म पुरस्कार विजेताओं के योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए **#पीपल्सपद्‌मा** शुरू की गईं।

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के एक भाग के रूप में "संविधान का निर्माण" और फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी "चित्रांजलि@75" पर वर्चुअल (आभासी) फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर।

3 नई पहल

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मार्च 2022 से **मन की बात बुकलेट** प्रकाशित करनी शुरू कर दी है। हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित बुकलेट में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में किए गए विशेष उल्लेखों पर स्टोरी और विवरण होते हैं, और साथ ही इनमें, मीडिया में प्रसारित मंत्रियों एवं विशेषज्ञों के साक्षात्कार एवं लेख और संबोधन पर प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित होती हैं। ई-संपर्क के माध्यम से देश भर में 6 करोड़ नागरिकों को यह बुकलेट वितरित की जाती है और साथ ही इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, माईगव, पीएम इंडिया और मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाता है। सांसदों, विधानसभा सदस्यों और भारत सरकार के अधिकारियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों तथा पीआईबी-प्रमाणित पत्रकारों को इनका प्रकाशित स्वरूप भेजा जाता है।

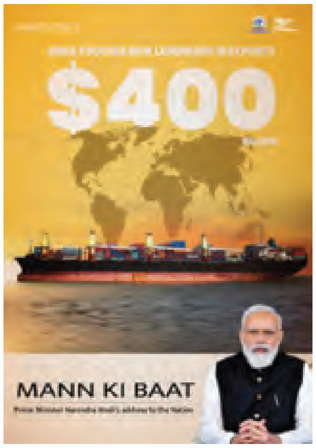

- **पीआईबी रिसर्च यूनिट** अक्तूबर 2021 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी पहल पर आधारित सत्य-आधारित कंटेंट तैयार करना ताकि साक्ष्य आधारित तथ्यों से झूठे तथ्यों का सामना किया जा सके और सकारात्मक कहानियों के लिए मीडिया कंटेंट का आकलन हो सके। यह रिसर्च यूनिट संबंधित विषय के लिए समग्र अंतर्दृष्टि हेतु क्षेत्र-विशेष के बैकग्राउंडर्स/एक्सप्लेनर्स, फैक्टशीट्स, विषय आधारित दस्तावेज और आम सवालों को एकत्र करती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 23.08.2021 से 29.08.2021 तक चलने वाले **आइकॉनिक वीक** समारोह में ***आज़ादी का अमृत महोत्सव*** अभियान के अंतर्गत अनेक नवीन कार्यक्रम चलाने की पहल की है। जन-भागीदारी की भावना से आयोजित इन कार्यक्रमों को टेलीविजन, डिजिटल, सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया। देश भर में आम पहुंच कार्यक्रमों के अंतर्गत दूरदर्शन पर प्रसारित भारतीय आज़ादी पर आधारित वृत्तचित्रों/फ़िल्मों, ऑल इंडिया रेडियो पर नई साप्ताहिक शृंखला तथा फ़िल्म प्रभाग एवं राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा ऑनलाइन फ़िल्म महोत्सवों के माध्यम से प्रसारित किया गया। सप्ताह के दौरान, प्रकाशन विभाग ने *जश्न-ए-आज़ादी* नाम से एक पॉडकास्ट सीरीज़ का भी शुभारंभ किया जिसमें विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों की समीक्षाएं और उन पर विमर्श शामिल था।

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24.09.2021 को 24 से 28 सितंबर, 2021 तक चलने वाले लेह, लद्दाख के **पहले हिमालयन फ़िल्मोत्सव** का उद्घाटन किया। महोत्सव में स्थानीय फ़िल्मकारों ने शिरकत की और 12 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। फ़िल्मोत्सव के साथ-साथ, माननीय मंत्री ने हिमालयी राज्यों के **स्वतंत्रता सेनानियों और हिमालयी क्षेत्र के श्रेष्ठ सिनेमा को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी** का भी उद्घाटन किया था।

- गोवा में, 20 से 28 नवंबर, 2021 तक भारत का **52वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह** (आईएफएफआई) मनाया गया। इस दौरान आईएफएफआई में **'75 क्रिएटिव यंग माइंड्स ऑफ टुमॉरो'** के अंतर्गत सिनेमा की अगली पीढ़ी के प्रतिनिधियों के लिए 75 युवा आकांक्षी फ़िल्मकारों (35 से कम आयुवर्ग) को चुना गया। 'इंडिया@75' के अंतर्गत देश भर से 18 चुनिंदा फ़िल्में प्रदर्शित की गईं। आईएफएफआई में **पहली बार फोकस कंट्री और ब्रिक्स राष्ट्रों** (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) **से सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित की गई थीं।** विशिष्ट मास्टरक्लास, कंटेंट लॉन्च/प्रीव्यू एवं क्यूरेटेड फ़िल्म स्क्रीनिंग्स के माध्यम से **आईएफएफआई**

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 27 अगस्त, 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के अवसर पर वर्चुअल फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी ''चित्रांजलि@75'' का शुभारंभ किया। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, संसदीय मामलों एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश मामलों एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 दिसंबर, 2021 को काशी फ़िल्म महोत्सव के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए।

में पहली बार नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनीलिव और ज़ी5 जैसे ओटीटी प्लेयर्स ने भी शिरकत की थी।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक लघु वीडियो *श्रृंखला **आज़ादी की अमृत कहानियां*** का शुभारंभ किया। इसमें सात महिला पद्म-पुरस्कार विजेताओं की कहानियां हैं, जिनमें श्रीमती बसंती देवी और सुश्री अंशु जम्सेन्पा; भारत की पहली महिला अग्निशमन कार्यकर्ता सुश्री हर्षिनी कान्हेकर; उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मीलों पैदल चलकर सभी का टीकाकरण करने वाली सुश्री पूनम नौटियाल; भारत के एक मिसाइल प्रोजेक्ट की अगुवाई करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक, डॉ. टेसी थॉमस; भारत की पहली प्रतिस्पर्धी पैडल बोर्डर महिला, सुश्री तन्वी जगदीश; और अकेले लाइट-स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में प्रशांत महासागर और अंटलाटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, सुश्री आरोही पंडित शामिल हैं।

- भारत के फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यट (एफटीआईआई) ने अक्तूबर 2021 में मेघालय (1 कोर्स), लद्दाख (02 कोर्स) और त्रिपुरा (1 कोर्स) अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी तरह का पहला **अमृत महोत्सव कोर्स** का संचालन किया।

फ़िल्में

- उत्तर प्रदेश के फ़िल्म बंधु ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ) के सहयोग से वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 दिसंबर, 2021 को **पहले 'काशी फ़िल्मोत्सव' का आयोजन** किया गया। महोत्सव में माननीय केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी, अभिनेता एवं सांसद श्री रवि किशन और अभिनेत्री एवं सांसद श्रीमती हेमा मालिनी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री अपूर्व चंद्र भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसे **#MagnificentKashiFilmFestival** एवं **#KashiFilmMahotsav** से व्यापक कवरेज मिली।

- फ़िल्म महोत्सव निदेशालय ने **सत्यजित रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (एसआरएलटीए) की स्थापना** की है। पहली बार, विश्व सिनेमा के दो दिग्गज फ़िल्मकारों को विश्व सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए एसआरएलटीए से पुरस्कृत किया गया। ये फ़िल्मकार हैं, हंगरी के श्री इस्तेवान ज़ाबो और अमेरिका के श्री मार्टिन स्कॉर्सिस।

- **फिल्म उद्योग में व्यवसाय करने में सरलता** के अंश के तौर पर, माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 08 अक्तूबर, 2021 को चेन्नई में दक्षिण भारत फ़िल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री को विभिन्न फ़िल्म व्यापार संघों से फ़िल्म उद्योग के संबंध में अनुरोध और मांग ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्होंने शिकायतें दूर करने के लिए प्रत्येक प्रयास करने को सुनिश्चित किया।

- व्यावसायिक प्रस्तावों हेतु भारत की सुगमता नामक **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) के पोर्टल 'माध्यम' को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है।** यह आरंभ भारत में व्यवसाय करने की आसानी की सरकारी पहल के साथ कारगर बनाने की दिशा में की गई है। एकीकरण से एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर फ़िल्मांकन की मंजूरी के लिए अनुमति मांगने वाले अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मकारों की एफएफओ ऑनलाइन आवेदन तक पहुंच हो सकेगी।

- रेलवे में फ़िल्मांकन की आसानी और इसके लिए अनुमति प्राप्ति के लिए, (एफएफओ), सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय में एकल खिड़की फ़िल्मांकन प्रणाली को स्थापित किया गया है। एफएफओ का पोर्टल www.ffo.gov.in अब रेलवे की ओर से फीचर फ़िल्मों, टीवी/वेब शो और श्रृंखलाओं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करेगा है।

- **राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) के मौखिक इतिहास परियोजना** के लिए इसकी वेबसाइट पर गत वर्षों के फ़िल्म कलाकारों के 8,000 मिनट लंबे इंटरव्यू अपलोड किए गए हैं। इसमें पांच भाषाओं में 53 साक्षात्कार शामिल हैं जिनमें एसडी सुब्बुलक्ष्मी, अक्किनेनी नागेश्वर राव और विजय भट्ट जैसे अग्रणी फ़िल्म कलाकार अपने जीवन, कहानियां और किस्से साझा करते दिख रहे हैं। ये साक्षात्कार 1980 के

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, 20 नवंबर, 2021 को गोवा के पणजी में आयोजित 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई-2021) के उद्घाटन समारोह के दौरान क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो के 75 विजेताओं के साथ। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी साथ हैं।

दशक में रिकॉर्ड किए गए थे। प्रादेशिक भाषाओं के सभी अपलोड्स का एनएफएआई ने अंग्रेजी अनुवाद भी कराया है।

प्रोग्रामिंग

- ऑल इंडिया रेडियो ने नए मौलिक कार्यक्रम **#AIRNxt** का शुभारंभ किया है जिसमें भारत भर में 167 एआईआर स्टेशनों पर 1,000 शिक्षा संस्थानों के 20,000 युवाओं की आवाज़ को उठाता है। एक अभूतपूर्व प्रयास के तहत, एआईआर ने स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं के लिए अपने स्टूडियो के दरवाजे खोले हैं ताकि वे युवा-केंद्रित शो तैयार करें और आज़ादी के 75 वर्षों के दौरान देश की उपलब्धियों पर बात कर सकें। यह शुरुआत 28 नवंबर, 2021 से की गई।
- प्रसार भारती ऑडियन्स रिसर्च ने 11.06.2021 को **न्यूज़ऑनएआईआर रेडियो लाइवस्ट्रीम रैंकिंग्स** का शुभारंभ किया था, जिसे अपडेट कर प्रति सप्ताह प्रसारित किया जा रहा है। न्यूज़ऑनएआईआर ऐप पर 90 देशों के श्रोताओं के लिए ऑल इंडिया रेडियो की 240 रेडियो सेवाएं लाइवस्ट्रीम हो रही हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां और पहल बताने के लिए डीडी न्यूज ने डीडी न्यूज संगोष्ठी **'देश की बात, डीडी न्यूज के साथ'** का संयोजन और प्रसारण किया। नीति आयोग के सीईओ के साथ पहली ऐसी संगोष्ठी 'ईज़ ऑफ लिविंग' का प्रसारण 28 सितंबर, 2021 को किया गया था। अक्तूबर 2021 के दौरान *इमैजिनेटिव जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आउटरीच,*

रीइमैजिनिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, युवाशक्ति, सोशल इम्पावरमेंट, कोऑपरेटिव एंड कम्पेटेटिव फेडरलिज़्म और 'इंडिया फर्स्ट' फॉरेन पॉलिसी – द मेकिंग ऑफ ए विश्वगुरु' का प्रसारण किया गया जिनमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों/ले. गवर्नरों और विषय विशेषज्ञों के संबोधन थे।

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने लद्दाख के **हमबोटिंग ला में 25.09.2021 को डीडी/एआइआरट्रांसमीटर का शुभारंभ किया** जो दूर-दराज और सीमांत क्षेत्रों को कवर करने वाला प्रसार भारती का सबसे ऊँचाई पर स्थित ट्रांसमीटर है।

नियमन एवं समझौते

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, 1994 में संशोधन** के लिए 17 जून, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा कंटेंट ब्रॉडकास्ट के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अधीन शिकायत करने हेतु एक निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2021 एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराता है- प्रसारकों द्वारा आत्म-नियमन, प्रसारकों की आत्म-नियमन इकाइयों द्वारा स्वःनियमन और केंद्र सरकार के स्तर पर अंतर-विभागीय समिति द्वारा निगरानी।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2021 को **शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के सदस्य देशों के बीच ''मास मीडिया क्षेत्र में सहयोग'' पर हस्ताक्षर और सत्यापन को कार्योत्तर मंजूरी** दी है। समझौते में मास मीडिया क्षेत्र में संस्थानों के बीच समान और आपसी तौर पर लाभकारी सहयोग किया जाएगा।

प्रशासन

- **ई-ऑफिस अपना कर प्रसार भारती 100% पेपरलैस हो गया है।** इसके जरिए, अगस्त 2019 और जून 2021 के बीच संस्थान का कागज़ पर 45% खर्च बचाया गया था। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के अलावा, कोविड महामारी के दिनों में पेपररहित कार्य, वर्क फ्रॉम होम आदि से संक्रमण के खतरे भी कम हुए थे।

- **हरित एआईआर:** केंद्र की हरित पहल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की परिकल्पना के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) ने यातायात की जरूरतों के लिए अपने सब वाहनों को बिजली चलित वाहनों में बदल दिया है।

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर को 08 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी), पत्र सूचना कार्यालय, श्री जयदीप भटनागर बधाई देते हुए।

4 सूचना क्षेत्र

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित लोगों की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराता है।

यह सरकार को मीड़िया की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों पर सलाह भी देता है।

पीआईबी विभिन्न माध्यमों जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि आलेख, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस टूर और सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। सूचना, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो पूरे देश के समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी में एक समाचार कक्ष/समाचार निगरानी प्रकोष्ठ है जो सूचना प्रसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए साल भर काम करता रहता है। पीआईबी मीडियाकर्मियों को मान्यता की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके।

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं। पीआईबी में 5 ज़ोन हैं जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 17 शाखा कार्यालय हैं, जिनमें एक सूचना केंद्र भी शामिल है, जो क्षेत्रीय मीडिया की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।

I. पीआईबी की सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क) मंत्रालय/विभागवार सूचना प्रसार:

पीआईबी अधिकारी किसी मंत्रालय/विभाग से जुड़े होते हैं और उसी के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वह मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचनाओं का प्रसार करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, स्पष्टीकरण या प्रतिवाद प्रदान करते हैं। पीआईबी अधिकारी मीडिया में संपादकीय, लेखों और टिप्पणियों में परिलक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय/विभाग को जनता की राय से अवगत कराते हैं और मंत्रालय/विभाग को उसकी मीडिया और सूचना शिक्षा संचार रणनीति पर सलाह देते हैं।

ख) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पीआईबी अधिकारी, मुख्यालय से दी जाने वाली सूचनाओं के प्रसार के अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय निरंतर आधार पर सूचना प्रसार पर केंद्रित प्रचार के लिए केंद्र सरकार के उन निर्णयों को भी लेते हैं जो एक क्षेत्र विशेष के लिए विशेष महत्व के हो सकते हैं। पीआईबी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के किसी क्षेत्र/राज्य के आधिकारिक दौरे पर मीडिया कवरेज को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

पीआईबी द्वारा सूचना प्रसार पीआईबी ऐप - एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा, ऐप के माध्यम से पीआईबी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए डाउनलोड और उपयोग किया जा रहा है।

पीएमओ को हिंदी और अंग्रेजी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से फीडबैक; प्रत्येक मंत्रालय को उनके

संबंधित अधिकारियों द्वारा दैनिक मीडिया फीडबैक; महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक।

मीडिया गतिविधियां/सेवा/वाहन	**संख्या (1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2021 के दौरान)**
प्रेस विज्ञप्ति	60,841
तस्वीरें/रेखांकन/इन्फोग्राफिक्स	6,971
मीडिया आमंत्रण	248
औपचारिक संवाददाता सम्मेलन	86
राष्ट्रव्यापी मीडिया प्रतिक्रिया	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट्स	दैनिक/साप्ताहिक
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
प्रेस मान्यता कार्ड जारी किए गए	125

ग) पीआईबी फैक्ट चैक इकाई

पीआईबी फैक्ट चैक इकाई का गठन (दिसंबर 2019 में प्रायोगिक आधार पर) विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से न्यूज़ मीडिया के विविध माध्यमों ओर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तथ्यात्मक रूप से गलत/मनगढ़ंत खबरों और सूचना के प्रचार एवं प्रसार पर नज़र रखने और उन पर रोक लगाने के लिए किया गया था। पीआईबी फैक्ट चैक इकाई का उद्देश्य विविध मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही किसी भी खबर के आधिकारिक/प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराते हुए जनसामान्य को तथ्यात्मक रूप से सही सूचना उपलब्ध कराना है।

यह इकाई स्वयं संज्ञान लेते हुए या अपने विभिन्न स्रोतों-विशेष ई-मेल आईडी, वैबसाइट पोर्टल तथा व्हाट्सऐप नंबर पर शिकायतों, टेलीविजन पर प्रसारित की जाने वाली भ्रामक खबरों के बारे में ईएमएमसी द्वारा दी जाने वाली जानकारी, पीआईबी द्वारा स्वयं या इसकी इकाईयों द्वारा एकत्र की गई अखबारों तथा वैब पोर्टल पर दी जाने वाली झूठी जानकारी की पहचान करती है।

जानकारी की प्रमाणिकता की पुष्टि के स्रोत के रूप में फैक्ट चैक इकाई की लोकप्रियता का इस बात से पता चलता है कि ट्विटर हैंडल पर इसके फालोअर्स की संख्या 2.49 लाख है। यह इकाई प्रमाणिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है जिसका इस्तेमाल निजी मीडिया भी करता है, इससे भी इसका प्रभाव बढ़ गया है। समय के साथ-साथ इसका विकास हुआ है, विशेषकर देश भर के विभिन्न राजधानी शहरों में पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय फैक्ट चैक इकाईयों की गतिविधियां बढ़ी हैं।

कोविड से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और महामारी के बारे में लोगों को प्रमाणिक जानकारी देने के लिए इसमें विशेष कोविड प्रकोष्ठ 31 मार्च, 2020 को बनाया गया था।

एफसीयू को 11 जुलाई 2022 तक 1,02,846 प्रश्न प्राप्त हुए और इनमें से कार्रवाई योग्य 34,125 प्रश्नों (कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों सहित) का जवाब दिया गया। 875 पोस्ट किए गए और जिनके लिए जरूरत थी उनके लिए इकाई ने स्पष्टीकरण जारी किया।

घ) प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई

पत्र सूचना कार्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार और मीडिया सहायता के लिए समर्पित इकाई दी है। यह इकाई वर्ष के सभी दिनों में कार्य करती है। यह इकाई भारत के माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के प्रचार से भी संबंधित है।

ङ) पीआईबी अनुसंधान इकाई

पीआईबी में अनुसंधान इकाई की स्थापना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें और सशक्त बनाना है। अनुसंधान इकाई की स्थापना का लक्ष्य सकारात्मक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सबूत आधारित सामग्री और मीडिया कन्टेंट विश्लेषण के जरिए, झूठी जानकारियों का प्रतिकार करते हुए, सरकार की पहलों पर तथ्य आधारित सामग्री प्रस्तुत करना है। इसने अक्तूबर 2021 में काम करना शुरू किया था।

अनुसंधान इकाई की मुख्य भूमिका पीआईबी और भारत सरकार के अन्य आधिकारिक माध्यमों द्वारा सूचना प्रसार को मज़बूत करना है। यह इकाई बदलते परिदृश्य और आवश्यकताओं पर आधारित राष्ट्रीय महत्व और प्रासंगिकता के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तृत अनुसंधान पर आधारित दस्तावेज़ तैयार कर प्रभावी संचार और लोगों तक इनकी पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

15 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की गतिविधियां:-

क्र.म. सं.	दस्तावेज़ों की प्रकृति	दस्तावेज़ों की सं.
1	पृष्ठभूमि / व्याख्याता	71
2	फैक्टशीट	83
3	एफएक्यू	21
4	हिंदी अनुवाद	07
	कुल	**182**

इकाई द्वारा बनाए गए दस्तावेज़ पीआईबी की वैबसाइट पर पृष्ठभूमि, फैक्टशीट और एफएक्यू खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। मीडिया (प्रिंट मीडिया और वैब पोर्टल) इन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल सकारात्मक सामग्री विकसित करने के लिए व्यापक रूप से करता है। सोशल मीडिया पर देने के लिए इन्फोग्राफिक्स और वीडियो, न्यू मीडिया विंग और पीआईबी (सोशल मीडिया) द्वारा इन दस्तावेज़ों से ली गई सामग्री का इस्तेमाल कर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन (डीडी शॉर्टस) और आकाशवाणी (परिक्रमा) के कार्यक्रम भी इस अनुसंधान इकाई द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ों पर आधारित होते हैं।

क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा रचित कुछ सामग्री का क्षेत्रीय पीआईबी द्वारा स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और स्थानीय मीडिया में प्रसारित किया जाता है।

च) सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

i) पीआईबी इंडिया और पीआईबी हिंदी

- **पीआईबी इंडिया ट्विटर** – पत्र सूचना कार्यालय, दिल्ली (@PIB_India) का अंग्रेजी ट्विटर हैंडल 27 दिसंबर, 2010 को बनाया गया था। तब से कुल फॉलोअर की संख्या बढ़कर 2.5 मिलियन हो गई है, जिसमें एक महीने में 30 हज़ार से अधिक फॉलोअर की औसत वृद्धि हुई है। मासिक आधार पर भेजे गए ट्वीट्स की औसत संख्या लगभग 25 मिलियन इंप्रेशन जेनरेट कर रही है।

- **पीआईबी हिंदी ट्विटर** – पीआईबी हिंदी दिल्ली (@PIBHindi) का ट्विटर हैंडल जनवरी, 2015 में शुरू किया गया था। फिलहाल पीआईबी हिंदी के 304.5 हज़ार फॉलोअर हैं, जिसमें एक महीने में 8,000 हज़ार नए लोग जुड़ रहे हैं। हैंडल से प्रतिमाह औसतन 950 ट्वीट किए जा रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार हर महीने हिंदी हैंडल पर 3.5 मिलियन इंप्रेशन जेनरेट किए जा रहे हैं।

ii) फेसबुक – वर्तमान वर्ष में फेसबुक पर पीआईबी के प्रशंसक आधार में लगभग 597 हज़ार फॉलोअर के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। संचार और जुड़ाव के रचनात्मक साधनों को अपनाने से इसे बढ़ावा मिला है।

iii) इंस्टाग्राम – पीआईबी इंस्टाग्राम के 917 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स थे।

iv) यूट्यूब- पीआईबी यूट्यूब मई 2011 को बनाया गया था। तब से, इसपर लाइव इवेंट सहित 6,374 वीडियो अपलोड किए गए हैं। पीआईबी के यूट्यूब चैनल के कुल 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।

v) पीआईबी फैक्ट चेक

- **ट्विटर:** पीआईबी फैक्ट चेक (@PIBFactCheck) का ट्विटर हैंडल नवंबर, 2019 में बनाया गया था। तब से, प्रति माह औसतन 9 हजार फॉलोअर्स की वृद्धि के साथ इनकी कुल संख्या बढ़कर 241.4 हज़ार हो गई है। पीआईबी फैक्ट चेक नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए नए प्रकार की सामग्री और प्रस्तुति को अपना रहा है, जैसे कि जीआईएफ, पोल्स, जागरूकता पोस्ट, मोमेंट मार्केटिंग और अभियान जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह औसतन 3.8 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त होते हैं।

- **फेसबुक:** पीआईबी फैक्ट चेक के फेसबुक पर 40,847 लाइक्स हैं।

- **इंस्टाग्राम:** पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम के 65 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स थे।

- **हॉटलाइन नंबर:** पीआईबी फैक्ट चेक, नोवेल कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर व्हाट्सऐप में शामिल हो गया, ताकि बढ़ती फर्जी खबरों के खतरे पर अंकुश लगाया जा सके जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्लिकेशन पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लोग अपने प्रश्न यूनिट को +918799711259 पर भेज सकते हैं। यूनिट को **86,935** से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर **29,154 से अधिक कार्रवाई योग्य प्रश्नों** का जवाब दिया गया है।

- **जीमेल और पोर्टल:** सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, दो खाते, socialmedia@pib.gov.in और pibfactcheck@gmail.com, कोविड-19 संबंधित फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए थे। कोविड-19 पर किसी भी समाचार का आधिकारिक संस्करण इन ईमेल से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। एफसीयू ने जीमेल और पोर्टल पर 12,881 से अधिक प्रश्न प्राप्त किए हैं और उनका जवाब दिया है।

छ) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज

विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार, मंत्रालय की डीसीआईडी योजना में किया जाता है। इसे विकास कार्यक्रम के मीडिया के माध्यम से संभावित लाभार्थियों को सूचित तथा सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है ताकि वे इन योजनाओं में भाग लेने और लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। यह क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंचता है जो लक्षित आबादी के साथ अधिक सीधे संपर्क में है।

(i) ***लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)/ केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी):*** सीबीसी द्वारा कार्यान्वित किए गए, एकीकृत संचार घटक के माध्यम से लोगों के सशक्तीकरण का उद्देश्य, लोगों का कल्याण, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसे विषय आधारित एकीकृत विकास संचार अभियान के ज़रिए चलाया जाता है। उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रभावी तथा लक्षित पहुंच के वास्ते अभियान में प्रिंट, श्रव्य तथा दृष्य आउटडोर मीडिया; जानकारी युक्त ब्रॉशर/फ्लायर का वितरण; मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों, मास आउटरीच कार्यक्रमों; लाइव सांस्कृतिक आयोजनों और नए मीडिया वाहनों को शामिल किया जाता है।

(ii) ***पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी):*** विशेष आयोजन घटक के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार का उद्देश्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों और पहलों का प्रसार, क्षेत्रीय भाषाओं में वार्तालाप, संवाददाता सम्मेलनों, प्रेस दौरों, प्रेस नोट, प्रधानमंत्री के भाषणों के माध्यम से किया जाता हैं। पीआईबी अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रचार की ज़िम्मेदारी उठाता है। यह जानकारी केंद्र सरकार के उन फैसलों के बारे में होती है जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण होती है। पीआईबी ने आर्थिक संपादकों के सम्मेलन तथा स्वास्थ्य संपादकों के सम्मेलनों के साथ-साथ क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन का आयोजन भी शुरू किया है ताकि क्षेत्रीय मीडिया के साथ संपर्क बढ़ाया जा सके और छोटे तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले पत्रकारों के साथ संवाद की सुविधा मिल सके।

(iii) ***न्यू मीडिया विंग:*** सोशल मीडिया प्लेटफार्म घटक का कार्यान्वयन न्यू मीडिया विंग द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य सरकारी की नीतियों/कार्यक्रमों/पहल का प्रभावी रूप से सोशल मीडिया पर प्रचार करना है। यह विंग प्रयास करती है कि सरकार की उपस्थिति और उन नागरिकों के साथ सभी प्रमुख भाषाओं में सीधा संवाद हो सके जो सोशल मीडिया माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के निरूपण और सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/पहलों के बारे में जानकारी सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के साथ प्रभावी संवाद के लिए ग्राफिक प्लेट्स, इन्फोग्राफिक्स, जीआईएफ, वीडियो जैसे सोशल मीडिया अनुकूल प्रारूपों के माध्यम से प्रचारित की जाती है।

वर्ष 2021-2022 के दौरान इस योजना के तहत कुल 211.21 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 992.94 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डीसीआईडी की सूचना निम्नवत है–

(करोड़ रु. में)

घटक का नाम	लागूकर्ता मीडिया इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	जोड़
समन्वित संचार के माध्यम से जनशक्तीकरण	केन्द्रीय संचार ब्यूरो	174.19	176.81	179	184	188	**902**
विशेष आयोजनों पर मीडिया आउटरीच और पब्लिसिटी कार्यक्रम	पत्र सूचना कार्यालय	6.13	9.6	10.1	10.18	10.68	**49.69**
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म	न्यू मीडिया विंग	7.68	7.94	8.21	8.66	8.76	**41.25**
	कुल जोड़	**188**	**194.35**	**197.31**	**202.84**	**207.44**	**992.94**

ज) चुनाव के दौरान सूचना प्रसार

पीआईबी भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और मीडियाकर्मियों के बीच प्रभावी इंटरफेस प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर जानकारी प्रदान करने के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जाती है। विधानसभा चुनावों, उपचुनावों, आम चुनावों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए बैकग्राउंडर, फैक्टशीट, ट्विटर पोस्ट ग्राफिक्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा, मीडियाकर्मियों के प्रश्नों के उत्तर वास्तविक समय के आधार पर दिए जाते हैं और विशिष्ट साक्षात्कार, लेखों का भी नियमित आधार पर समन्वय किया जाता है। लोकसभा के आम चुनावों और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना प्रक्रिया की कवरेज की सुविधा के लिए, पीआईबी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडियाकर्मियों को निर्वाचन आयोग की ओर से प्राधिकरण पत्र जारी करता है। मतगणना दिवस पर रुझान/परिणाम वास्तविक समय के आधार पर वेबसाइट और ट्विटर के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग की साइट और डेटा ऐप से गणना डेटा का पालन करके साझा किए जाते हैं। त्वरित डेटा साझाकरण को प्राथमिकता के आधार पर दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार कक्षों के साथ समन्वित किया जाता है और डिजिटल डिस्प्ले पैनल के लिए भी फीड के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

II. फीडबैक यूनिट

यह इकाई दैनिक क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट तथा प्रेस कतरनों, मीडिया डाइजेस्ट तथा विशेष आयोजनों पर प्रेस कतरनों और दैनिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया सहित विभिन्न फीडबैक को प्रदान करके सरकार की विभिन्न पहलों, नीतियों और कार्यक्रमों पर दैनिक आधार पर जनता की धारणा से सरकार को अवगत कराती है। देश भर के 35 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से फीडबैक लेकर, 19 भाषाओं के लगभग 400 अखबारों की स्क्रीनिंग करके रीजनल मीडिया डाइजेस्ट तैयार किया जाता है। 1 अप्रैल से 20 दिसंबर 2021 तक, पीएमओ, विभिन्न मंत्रालयों के मीडिया प्रबंधन के प्रभारी अधिकारियों को 1,860 एसएमएस अलर्ट/मेल और लगभग 142 मीडिया डाइजेस्ट तथा 30 से अधिक स्पेशल डाइजेस्ट भेजे गए।

III. प्रत्यायन प्रणाली

दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले पत्रकारों को 01/04/2021 से 30/11/2021 तक 125 नए मान्यता

कार्ड जारी किए गए हैं (जिनमें से 94 को नई मान्यता दी गई है और 31 संगठन परिवर्तन के हैं)।

पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस)

पत्रकारों को गंभीर बीमारियों और पत्रकार की मृत्यु के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना पीआईबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपये तक की यह सहायता राशि मृतक पत्रकार के परिवार को या उसे उसकी स्थायी विकलांगता के मामले में दी जाती है। कैंसर, गुर्दे का काम करना बंद करने, हृदय रोग आदि जैसी बड़ी बीमारियों के मामले में पत्रकारों को 3.00 लाख रुपये तक की सहायता और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली दुर्घटनाओं के मामले में 2.00 लाख तक दिए जाते हैं। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को पीआईबी द्वारा संसाधित किया जाता है और उन्हें विचार के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के समक्ष रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1 अप्रैल, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि तक, इस योजना के तहत 87 पत्रकारों/परिवारों को 4,28,00,858 रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा, 2,19,62,590 रुपये की सहायता राशि की मांग करने वाले 48 आवेदन जेडब्ल्यूएस समिति द्वारा अनुमोदित भुगतान के लिए प्रक्रियाधीन हैं। कोविड-19 के कारण और वित्तीय 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया और 6.15 करोड़ रुपये 123 मृत पत्रकारों के परिवारों के लिए जारी किए गए।

IV. आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष

पीआईबी में एक समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो किसी भी घटना से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष भर हर दिन चालू रहता है। देश भर में पीआईबी केंद्रों के माध्यम से शॉर्ट नोटिस और एक साथ वेबकास्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की व्यवस्था भी किसी भी अचानक हुए घटनाक्रम और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तत्परता की स्थिति में रखी जाती है। नियंत्रण कक्ष आपात स्थिति और संकट के समय में चौबीसों घंटे काम करता है। समय पर मीडिया के कार्यकलापों के लिए महत्वपूर्ण समाचार चैनलों की निगरानी की जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों को नवीनतम घटनाओं, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग आदि से अवगत कराया जाता है।

V. 2021-22 के दौरान पीआईबी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां

क) कोविड-19:

कोविड-19 से संबंधित सूचना प्रसार वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, गृह, वित्त, रेलवे, शिक्षा, रक्षा, नागरिक उड्डयन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और उद्योग आदि के समन्वय से पीआईबी द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है।

i. केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट का विवरण आगे के प्रसार के लिए पीआईबी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार साझा किया जाता है। सूचना को पीआईबी की वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

ii. पीआईबी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने 21 जून 2021 को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण शुरू करने के संबंध में जानकारी का प्रसार विभिन्न ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से किया। सबके लिए निःशुल्क वैक्सीन पर नए डिस्प्ले क्रिएटिव का गुजराती, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, उर्दू, तमिल, बांग्ला, मलयालम, मणिपुरी में पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवाद किया गया है। मुख्यालय में पीआईबी अधिकारियों ने अपने संबंधित मंत्रालयों और इसके विभिन्न संगठनों के साथ क्रिएटिव साझा किए।

iii. पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों और एजेंसियों को नए क्रिएटिव का सक्रिय रूप से प्रसार किया।

iv. केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन,

पूर्व कृषि तथा किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने विभिन्न लेख लिखे।

v. पीआईबी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे मीडिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी पर जागरूकता पैदा करने के विभिन्न पहलुओं पर वेबिनार आयोजित किए।

vi. सरकार द्वारा विशेष रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति, दवाओं और उपकरणों के आयात पर की गई सकारात्मक कार्रवाई का मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। इसी तरह, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की गई गतिविधियों का सफलतापूर्वक प्रचार-प्रसार किया गया है।

vii. पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालयों ने मोबाइल वैन, नुक्कड़ नाटक, कॉलेज के छात्रों के साथ प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिताएं और गीत एवं नाटक प्रभाग के निजी पंजीकृत मंडलों की कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करके आरओबी और एफओबी के साथ मिलकर काम किया है।

ख) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अक्टूबर, 2021 को 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' का शुभारंभ किया। पीआईबी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गईं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लिखित लेख, जिसका शीर्षक है 'पीएम आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य अवसंरचना मिशनः भविष्य की महामारी कार्रवाई में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी छलांग' देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

ग) संविधान दिवस

संविधान दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर 'जनभागीदारी' के साथ किया गया था। संविधान दिवस से पहले, संसदीय कार्य मंत्रालय ने पीआईबी के साथ भागीदारी में **एक समर्पित सोशल मीडिया अभियान** चलाया।

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों ने 56 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। संविधान दिवस के संबंध में एक लेख लिखा गया था। 'भारत का संविधानः हमारे लोकतंत्र की आधारशिला' विषय पर लेख माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरलाजी द्वारा लिखा गया था। पीआईबी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम की तस्वीरें/वीडियो पोस्ट करने के लिए मंत्रालयों और उनके संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया।

घ) 75वां स्वतंत्रता दिवस

प्रधानमंत्री के संबोधन का ट्रांसक्रिप्शन और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसे पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। विशेष ग्राफिक्स बनाए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग पीआईबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एफबी और वाईटी) पर की गई थी, इसके अलावा पूर्व-प्रचार के लिए प्रोमो वीडियो, पिक्चर्स के लाइव ट्वीट और वीडियो बाइट के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के वीडियो बाइट भी शामिल थे।

ङ) एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)

कोविड की शुरुआत के बावजूद, पीआईबी ने फ्लैगशिप अभियान 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की गति को बनाए रखा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर 2021 में पूरे वर्ष विशेष केंद्रित सोशल मीडिया अभियान जारी रहा। पीआईबी मुख्यालय और पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उत्साहपूर्वक अभियान में भाग ले रहे हैं। इससे पूरे देश में कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने में काफी मदद मिली है। पीआईबी, मुख्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में मंत्रालयों की ईबीएसबी गतिविधियों की कवरेज की व्यवस्था कर रहा है। प्रेस विज्ञप्तियां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की गई हैं। क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वेबिनार भी आयोजित किए गए। इन वेबिनार को विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में अच्छा मीडिया कवरेज मिला। उन्होंने संस्कृति, व्यंजन, पर्यटन स्थलों, पोशाकों, रीति-रिवाजों, परंपराओं सहित युग्मित राज्यों के विभिन्न पहलुओं को छुआ है।

नवीनतम पहल: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की नई रणनीति: अभियान पर अधिक ध्यान देने के लिए, पीआईबी ने अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक एक नई रणनीति अपनाई है। पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' प्रारूप के अनुसार जोड़े में व्यवस्थित किया गया है। राज्यों की प्रत्येक जोड़ी को एक गहन केंद्रित अभियान चलाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है, जिसमें अभियान के लिए लेखों के प्रकाशन, सोशल मीडिया गतिविधियों, वेबिनार, प्रेस टूर या युग्मित राज्य के संबंध में कोई अन्य गतिविधि जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। ***पहली जोड़ी अक्टूबर माह के दौरान गुजरात और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालयों की थी। दोनों क्षेत्रों ने प्रेस टूर, लेखों के प्रकाशन, वेबिनार, सोशल मीडिया गतिविधियों, प्रेस विज्ञप्तियों, डीडी और आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रमों सहित महीने के दौरान सफलतापूर्वक 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को अंजाम दिया।***

च) सेवा समर्पण अभियान

17 सितंबर 2021 से पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने सेवा समर्पण अभियान का व्यापक प्रचार किया है। महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। पीआईबी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

i.) **इक्कीस (21) लेख प्रकाशित, 1,056 कतरनें प्राप्त:** पीआईबी ने सेवा समर्पण अभियान का प्रचार करने के अपने प्रयास में, मुख्यालय से लगभग 21 लेखों का प्रकाशन सुनिश्चित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 1,000 से अधिक प्रकाशन हुए हैं। लेख 18 सितंबर से 13 अक्टूबर 2021 के बीच प्रकाशित किए गए थे और शिक्षा, जीवन सुगमता, कृषि आदि विषयों पर केंद्रीय मंत्रियों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए थे।

ii.) **व्यापक सोशल मीडिया सामग्री का प्रसार:** क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के साथ मुख्यालय के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेवा समर्पण 2021 को व्यापक दृश्यता प्रदान की है।

पीआईबी सोशल मीडिया ने सेवा समर्पण पर 360 डिग्री सोशल मीडिया आउटरीच अभियान का आयोजन किया। सभी सामग्री पीआईबी सोशल मीडिया द्वारा दिन-वार पोस्ट की जा रही है। पीआईबी सोशल मीडिया ने केंद्र सरकार के विभिन्न क्षेत्रों, योजनाओं और कार्यक्रमों/अभियानों की ऐतिहासिक उपलब्धियों और प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर इन्फोग्राफिक्स, जीआईएफ और वीडियो आदि सहित रचनात्मक सोशल मीडिया सामग्री की एक श्रृंखला तैयार की। समर्पित हैशटैग: **#सेवासमर्पण, #अमृतमहोत्सव, #आज़ादीकाअमृत महोत्सव और #इंडियाऐट75** के साथ।

क.	**पीआईबी मुख्यालय द्वारा पोस्ट किए गए कुल इन्फोग्राफिक्स**	:	169
ख.	**पीआईबी मुख्यालय द्वारा पोस्ट किए गए कुल वीडियो**	:	197
ग.	**आरबी कार्यालयों द्वारा किए गए कुल ट्वीट**	:	537
घ.	**आरबी कार्यालयों द्वारा किए गए कुल रीट्वीट**	:	491

छ) आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) आइकॉनिक वीक सूचना और प्रसारण मंत्रालय (23 से 29 अगस्त 2021)

1. अगस्त 2021 के महीने में, पीआईबी ने आइकॉनिक वीक (23-29 अगस्त) से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के ट्विटर हैंडल के साथ-साथ मुख्यालय डीपीओ ने आइकॉनिक वीक के साथ-साथ *आज़ादी का अमृत महोत्सव* से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के लिए **ट्वीट, फेसबुक पोस्ट** आदि के माध्यम से सामग्री का प्रसार किया है।

क) ट्वीट्स में **#आज़ादीकाअमृतमहोत्सव** और **#अमृतमहोत्सव** का इस्तेमाल किया गया।

ख) 23 से 29 अगस्त 2021 तक, पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालयों के ट्विटर हैंडल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित **2,300 से अधिक मूल ट्वीट** पोस्ट किए और **3,300 से अधिक रीट्वीट** किए, **9,70,000 से अधिक इंप्रेशन** जनरेट हुए। इसके अलावा, इन हैंडल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सूचना और प्रसारण हैंडल से पोस्ट को रीट्वीट किया।

ग) पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालय फेसबुक ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर **880 पोस्ट,** पोस्ट किए।

घ) पीआईबी मुख्यालय डीपीओ के ट्विटर हैंडल से 23 से 29 अगस्त, 2021 के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित **160 से अधिक मूल ट्वीट** और **लगभग 760 रीट्वीट** किए गए और **4,40,000 से अधिक इंप्रेशन जनरेट** हुए। इसके अलावा, इन हैंडल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के हैंडल से पोस्ट को रीट्वीट किया।

च) पीआईबी मुख्यालय डीपीओ ने इंस्टाग्राम पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर **लगभग 28 पोस्ट** और फेसबुक पर **23 पोस्ट,** पोस्ट किए।

छ) इसी अवधि के दौरान, पीआईबी मुख्यालय के ट्विटर हैंडल (@PIB_India और @PIBHindi) ने आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित **75 मूल ट्वीट** किए और **90 से अधिक रीट्वीट** किए और 7,00,000 से अधिक इंप्रेशन जनरेट हुए।

2. पीआईबी मुख्यालय डीपीओ द्वारा लगभग 36 प्रेस विज्ञप्तियां और 54 तस्वीरें जारी की गईं। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित 330 विज्ञप्तियां जारी कीं और 800 से अधिक कतरनों की रिपोर्ट दी।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आइकॉनिक वीक के दौरान, पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालयों (एफओबी के साथ) ने *आज़ादी का अमृत महोत्सव* पर लगभग **37 वेबिनार** आयोजित किए और **3,800 से अधिक प्रतिभागियों** ने वेबिनार में भाग लिया।

4. पीआईबी ने इस वर्ष के दौरान वेबिनार आयोजित करने की अपनी क्षमता विकसित की है क्योंकि वेबिनार, कोविड-19 के दौरान एक शक्तिशाली संचार उपकरण के रूप में उभरा है। पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अप्रैल से 31 दिसंबर, 2021 तक कोविड-19 से लेकर *आज़ादी का अमृत महोत्सव* और अन्य विषयों पर 700 से अधिक वेबिनार का आयोजन किया था।

ज) भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया। पीआईबी द्वारा फ़िल्म समारोह का व्यापक प्रसार किया गया।

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव-आईएफएफआई को व्यापक दृश्यता प्रदान की है।

सूचना प्रसार के लिए पीआईबी के ट्वीट और पोस्ट को कई व्यक्तियों और संगठनों द्वारा साझा किया गया था। पीआईबी सोशल मीडिया ने भी सभी मंत्रियों और मंत्रालयों की सभी प्रासंगिक जानकारी को रीट्वीट और साझा किया। #IFFI52, #IFFIAwards, #IFFILOID और #IFFI कुछ ऐसे हैशटैग हैं जिनका उपयोग सोशल मीडिया पर भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव- IFFI52 पर पोस्ट पर किया जाता है।

झ) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

पीआईबी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग और कोविड के समय में इसके महत्व के बारे में प्रासंगिक जानकारी का व्यापक प्रसार किया है। पीआईबी ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य के लिए योग का संदेश देश के कोने-कोने तक पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कई प्रेस विज्ञप्तियां पीआईबी मुख्यालय द्वारा जारी की जाती हैं, जिनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, और देश भर में अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों दोनों द्वारा मीडिया के साथ साझा किया जाता है।

पीआईबी मुख्यालय द्वारा अधिकृत लेख:

पीआईबी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लिखे गए दो लेखों को अधिकृत किया। ये लेख देश भर के लगभग 129 प्रकाशनों में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं।

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक दृश्यता प्रदान की है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फोग्राफिक्स का प्रकाशन; विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों की सामग्री साझा करना; ट्विटर तथा फेसबुक पर लाइव वीडियो

बाइट्स का प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रेस विज्ञप्तियों का प्रकाशन।

सूचना प्रसार के लिए पीआईबी के ट्वीट और पोस्ट को कई व्यक्तियों और संगठनों द्वारा साझा किया गया था। पीआईबी सोशल मीडिया ने भी सभी मंत्रियों और मंत्रालयों की सभी प्रासंगिक जानकारी को रीट्वीट और साझा किया। #InternationalDayOfYoga, #YogaForWellness, #YogaDay, #IDY2021 और #Yoga सोशल मीडिया पर *आज़ादी का अमृत महोत्सव* 2021 की पोस्ट पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ हैशटैग हैं।

ञ) 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व किया। दो मंत्रियों ने इस विषय पर लेख लिखे थे। माननीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन, द्वारा लिखे गए लेख का शीर्षक था– 'भारत का गौरवः भगवान् बिरसा मुंडा' और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा लिखित लेख का शीर्षक था– 'जनजातीय गौरव दिवसः राष्ट्र आदिवासी गौरव के लिए खड़ा है'।

VI. योजना निष्पादन 2021-2022

वर्ष 2021-22 के दौरान 08 क्षेत्रीय कार्यालयों 05 एडीजी क्षेत्रों फोटो डिवीजन और पीआईबी मुख्यालय को निधि आवंटित की गई है।

'स्वच्छता कार्य योजना' का कार्यान्वयन

वर्ष 2021-22 के दौरान 'स्वच्छता कार्य योजना' के कार्यान्वयन के लिए समग्र रूप से पीआईबी को **संशो. अनु.- 2021-22** में 45.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:-

क) कार्यालय उपकरणों की सफाई और रखरखाव।

ख) पानी के डिस्पेंसर और अन्य वस्तुओं को बदलना।

ग) पीआईबी मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों दोनों में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालयों में बदलाव।

घ) कोविड-19 की रोकथाम के लिए वस्तुओं जैसे मास्क/ सैनिटाइजर आदि की खरीद।

च) उचित वेंटिलेशन के लिए निकास पंखे।

छ) धूल साफ करने वाले उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर/वैक्यूम क्लीनर आदि।

पीआईबी मुख्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रगतिशील उपयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के तहत राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित विभिन्न आदेशों और निर्देशों के पालन और कार्यान्वयन के लिए पत्र सूचना कार्यालय में हर संभव प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) ब्यूरो कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करती है। समिति की त्रैमासिक बैठकें प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी) की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे हिंदी प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, हिंदी के उपयोग के संबंध में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के निरीक्षण आदि पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, पीआईबी मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का दौरा किया जाता है ताकि उन्हें राजभाषा नीति और नियमों से अवगत कराया जा सके और इन कार्यालयों में इसके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जा सके। पीआईबी की वेबसाइट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति द्वारा समय-समय पर कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 01 से 15 सितंबर, 2021 तक पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में *हिंदी पखवाड़ा* का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, अनुवाद, नोटिंग एवं प्रारूपण, सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी टंकण एवं प्रारूपण जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एमटीएस के लिए हिंदी आशुलिपि और हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई।

शिकायत निवारण तंत्र

पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक (एमएंडसी), श्री एस. एन. चौधरी, को कर्मचारी/लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसके संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाया गया है।

महिला कल्याण गतिविधियां

यौन उत्पीड़न के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार महिला स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए पीआईबी (मुख्यालय)/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। कार्यस्थलों पर उत्पीड़न को नियम-3सी के तहत सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में शामिल किया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार हैः-

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफोन
1.	सुश्री कंचन प्रसाद मंडलौस, अपर महानिदेशक	अध्यक्ष	दूरभाषः 23488021
2.	सुश्री नाविका गुप्ता, संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव	दूरभाषः 23385893/ 23488140
3.	श्री प्रतीक जैन, सहायक निदेशक	पुरुष सदस्य	दूरभाषः 23488115
4.	श्रीमती मुक्ता अग्रवाल, उप. निदेशक (राजभाषा)	सदस्य	दूरभाषः 23382145
5.	श्रीमती रचना, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	दूरभाषः 23385388
6.	रिक्त (नामांकन शीघ्र प्राप्त होगा)	बाहरी सदस्य	

सतर्कता प्रकोष्ठ

पीआईबी का सतर्कता तंत्र प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है, जिसे सतर्कता अधिकारी (एडीजी सतर्कता के स्तर पर), उप निदेशक (सतर्कता), अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सतर्कता मामलों के संबंध में प्राधिकार और जिम्मेदारियां क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख को भी प्रदान की गई हैं। ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के संबंध में सतर्कता मामलों से निपटने में क्षेत्रीय प्रमुखों की सहायता के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद है। क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

अवधि के दौरान निगरानी और पता लगाने की गतिविधियां:

ब्यूरो के सामान्य, प्रेस रिलेशन सेक्शन, एनएमसी सेल और ऑफिस ऑटोमेशन सेक्शन नाम के अनुभाग को निगरानी के लिए रखा गया है। इन अनुभागों में काम करने वाले स्टाफ को संवेदनशील माना जाता है। इन अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर बदल-बदल कर नियुक्त किया जाता है।

दंडात्मक गतिविधियां:

i. अविधि के दौरान 03 शिकायतें संदर्भ में प्राप्त हुए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संबंधित मामले

पीआईबी (मुख्यालय) में आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए पीआईबी के प्रशासन-I अनुभाग को नोडल अनुभाग के रूप में नामित किया गया है। सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों को, डीओपी एंड टी के निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए नामित किया गया है।

पीआईबी मुख्यालय पहले ही धारा 4(ख)(i) और 4(ii) के तहत दायित्वों को पूरा कर चुका है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई सभी सूचनाओं के स्व-प्रेरणा से प्रकटीकरण और इसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने से संबंधित है। प्राप्त, अस्वीकृत, स्थानांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़े देते हुए त्रैमासिक रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमित रूप से सीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

हिंदी और उर्दू इकाइयों की गतिविधियां

हिंदी और उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंडअप की तैयारी शामिल है जिसमें हेडलाइंस और हिंदी/उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद, प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति,

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषण का हिंदी/उर्दू अनुवाद और मैनुअल तथा बुकलेट आदि का अनुवाद तथा पुनरीक्षण शामिल है। हिंदी और उर्दू दोनों इकाइयों ने 1 अप्रैल, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि के लिए हिंदी और उर्दू में 16,654 प्रेस विज्ञप्तियां, पृष्ठभूमि और लेख जारी किए हैं।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का, 2013 में नाम बदलकर न्यू मीडिया विंग कर दिया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा और प्रसार इकाई के रूप में कार्य करता है। न्यू मीडिया विंग के कामकाज के दो प्राथमिक क्षेत्र- सामान्यतः भारत सरकार और विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच कार्य; और मीडिया में प्रसारित-प्रचारित विचारों तथा राय का फीडबैक और विश्लेषण हैं।

न्यू मीडिया विंग को सरकार के कार्यक्रमों और अभियानों के अलावा उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच कार्यों में शामिल हैं।

- वीडियो, ग्राफिक के रूप में रचनात्मक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं और सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव कवरेज कर प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया संचार।
- आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम सेनानियों, जाने-माने विद्वानों, सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारकों और अन्य विख्यात हस्तियों के बारे में सोशल मीडिया कवरेज और प्रचार।
- कार्यक्रम- आधारित सोशल मीडिया अभियानः

क. दुनिया के सबसे बड़े कोविडरोधी टीकाकरण अभियान, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड संबंधी दुष्प्रचार के प्रतिकार पर ज़ोर देने के साथ कोविड-19 से निपटने में सरकार के प्रयासों की समर्पित ट्विटर हैंडल #इंडियाफाइटकोरोना के ज़रिए 360 डिग्री सोशल मीडिया कवरेज।

ख. 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सव, काशी फ़िल्मोत्सव, हिमालयी फ़िल्म समारोह और कान्स फ़िल्म समारोह-2022 और पद्म पुरस्कार आदि जैसे पुरस्कार वितरण समारोहों और फ़िल्मोत्सवों का आयोजन।

ग. यूक्रेन संकट के दौरान आपरेशन गंगा; सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के सरकार के प्रयासों के बारे में निरंतर/वास्तविक समय जानकारी का प्रसार किया।

पहल और उपलब्धियां

न्यू मीडिया विंग ने नागरिक केंद्रित और संवेदनशील तरीके से सोशल मीडिया के सभी उपयोगकर्ताओं तक जानकारी का प्रसार कर एक आदर्श उदाहरण पेश किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत न्यू मीडिया विंग ने संसद और प्रसार भारती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डा. बीआर अम्बेडकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के अभिलेखकीय श्रव्य भाषणों का इस्तेमाल करते हुए उनके चित्रों को फेशियल मूवमेंट देने के लिए कृत्रिम मेधा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया।

जानकारी को, पूरी सक्रियता से और ज़िम्मेदारी के साथ मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अति-स्थानीय संचरण के साथ देश भर में निचले स्तर तक के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पब्लिक एप जैसे नए प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।

न्यू मीडिया विंग ने विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान आदतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए रील और मीम जैसे प्रभावकारी और आकर्शक संदेशवाहक तरीकों का इस्तेमाल किया। लोकप्रिय फ़िल्म पुष्पा पर आधारित एक मीम इतना अधिक वायरल हुआ कि सोशल मीडिया के अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर संचरण के लिए रांची (झारखंड) में स्थानीय मीडिया वैन पर इसका बैनर लगाया गया।

न्यू मीडिया विंग ने मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जो बड़े अभियान चलाए उनमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और कोविड-19 से संबंधित अभियन शामिल हैं। अभियान की शुरुआत के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम नेताओं और भारत के स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में 3,000 से अधिक रचनात्मक सामग्रियों (वीडियो तथा ग्राफिक सहित) को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। अप्रैल 2020 के बाद से कोविडरोधी टीकाकरण, कोविड नमूनों की जांच, निवारण दिशानिर्देश, मिथक तथा तथ्य और कोविड उपयुक्त व्यवहार आदि सें संबंधित आंकड़ों के बारे में 20,000 से अधिक पोस्ट विशेष ट्विटर हैंडल @covidNewsByMIB(#IndiaFightsCorona) से किए गए।

फोटो प्रभाग

परिचय

फोटो डिवीजन को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्य सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। अक्टूबर 1959 में स्थापित, यह देश का शायद एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास स्वतंत्रता-पूर्व युग से लेकर आज तक डिजिटल प्रारूप में संरक्षित लगभग 10 लाख निगेटिव/ट्रांसपेरेंसी का समृद्ध भंडार है। फोटो प्रभाग एक वर्ष में लगभग 4,500-5,000 समाचारों और फीचर को कवर करता हैं। फोटोग्राफ स्वीकृत दरों के अनुसार आम जनता को बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं।

- मीडिया में आगे प्रसार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को दृश्य (स्टिल्स) प्रदान करता है।
    - ***पत्र सूचना कार्यालय का प्रेस फोटो प्रचार पूरी तरह से फोटो प्रभाग द्वारा समर्थित है।***
    - ***बीओसी की प्रदर्शनी विंग को बड़े आकार के प्रिंट और फोटो संबंधी अन्य आवश्यकताओं की तैयारी में फोटो डिवीजन से सहायता प्रदान की जाती है।***
- माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों के और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों के लिए फोटो कवरेज प्रदान करना और उनका प्रलेखन करना।
- दौरा करने वाले देशों/सरकारों के प्रमुखों की व्यापक कवरेज के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग को सहायता प्रदान करता है। प्रभाग द्वारा अतिथि गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीरों वाला एक विशेष एल्बम उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।
- गैर-प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को मूल्य निर्धारण योजना के अनुसार भुगतान के आधार पर तस्वीरों की आपूर्ति करता है।

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल

फोटो प्रभाग बदलते समय के साथ सहयोगी मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं में सहायक बना है। प्रभाग का समाचार फोटो नेटवर्क, पत्र सूचना कार्यालय और संबंधित हितधारकों को फोटो भेजने में देरी से बचने के लिए पूर्ण डिजिटल तरीके से कार्य कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वीवीआईपी के दौरों की कवरेज के लिए डिजिटल कैमरा उपकरण का उपयोग वी-डेटा कार्ड के साथ किया जा रहा है ताकि छवियों को जहां लिया जाए उसी स्थान से ही डिजिटल रूप से प्रसारित किया जा सके। यह प्रभाग अपने द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए बीओसी द्वारा लाइफ साइज़ डिजिटल इंकजेट छवियों की आवश्यकता को पूरा करता है और प्रकाशन विभाग को दृश्य सहायता भी प्रदान करता है।

निष्पादित कार्यों के आंकड़े

कवर किए गए कार्यों की संख्या, प्राप्त किए गए चित्र, अपलोड किए गए प्रिंट, तैयार किए गए एलबम निम्नानुसार हैं:

1.	कवर किए गए समाचार और फीचर असाइनमेंट	1,202
2.	पीआईबी वेबसाइट में भेजी/अपलोड की गई छवियां	4,864/4,275
3	फोटो डिवीजन की वेबसाइट में अपलोड की गई छवियां	4,320
4.	इन-हाउस प्राप्त डिजिटल चित्र	2,32,107
5.	बनाए/आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	699

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) की स्थापना 8 दिसंबर, 2017 को तत्कालीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को एकीकृत करके की गई। इस ब्यूरो का उद्देश्य **मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360° यानी हर प्रकार के संचार समाधान उपलब्ध कराना है। यह ब्यूरो सरकार को मीडिया नीति पर परामर्श देने वाले निकाय के रूप** में कार्य करता है। 23 क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) और 148 क्षेत्र लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) के माध्यम से बीओसी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देकर विकास गतिविधियों में उनका सहयोग जुटाता है। ब्यूरो संचार के विभिन्न माध्यमों-प्रिंट मीडिया, श्रव्य-दृश्य मीडिया, विज्ञापन एवं श्रव्य-दृश्य अभियान तथा प्रदर्शनियों, आउटडोर अभियानों और न्यू मीडिया आदि के माध्यम से इसे सुनिश्चित करता है।

जन-सशक्तीकरण के प्रमुख सुविधाप्रदाता के रूप में सरकार की ब्रांडिंग तथा तथा उसे साकार करने के लिए विविध मीडिया माध्यमों के जरिए संदेशों को सही दिशा देना बीओसी का कार्य है। बीओसी का **विज्ञापन एवं दृश्य संचार प्रभाग** सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, पीएसयू तथा स्वायत्त निकायों की विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए ब्यूरो का नोडल डिविजन है। यह ग्रामीण और शहरी लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचार के उपलब्ध माध्यमों-प्रिंट, श्रव्य-दृश्य, आउटडोर, डिजिटल और न्यू मीडिया के जरिये अभियान चलाकर/विज्ञापन जारी करके अभियान चलाता है।

बीओसी का **लोक संचार प्रभाग,** नाटक नृत्य-नाटक, संयुक्त-कार्यक्रम, कठपुतली-खेल, बैले, ओपेरा, लोक और पारपरिक गायन, पौराणिक गायन प्रस्तुत तथा अन्य स्थानीय लोक एवं पारंपरिक शैलियों जैसी प्रदर्शनकारी कलाओं की व्यापक शृंखला का उपयोग करके सजीव मीडिया के माध्यम से अंतर-वैयक्तिक संवाद करता है।

क्षेत्र लोक संपर्क प्रभाग, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अंतर-वैयक्तिक संचार कार्यक्रम संचालित करता है। इस प्रकार से आरओबी तथा एफओबी सूचना के जरिए लोगों को सशक्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम बनाया जा सके। यह जमीनी सक्रियता और लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्रभाग ग्राउंड एक्टिवेशन और समन्वित लोक संपर्क कार्यक्रम चलाता है। विभिन्न हितार्थियों के सहयोग से समन्वित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी) चलाए जाते हैं।

पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी तथा एसएंडडीडी का एकीकरण होने से विशेष लोक संपर्क तथा लोक घटकों के साथ एकीकृत रूप में अधिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन एकीकृत संचार और लोक संपर्क कार्यक्रमों (आईसीओपी) का उद्देश्य एक ऐसा प्रभावशाली असर छोड़ना है, जो व्यवहार परिवर्तन और विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

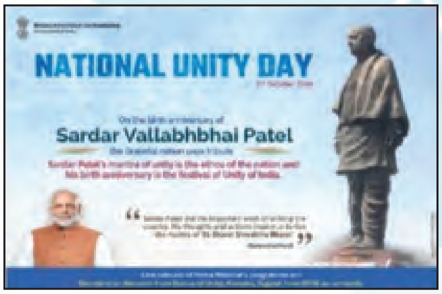

महत्वपूर्ण गतिविधियां:

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार ने प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तथा देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवपूर्ण इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से *आज़ादी का अमृत महोत्सव* अभियान शुरू किया है। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो अपने क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालयों और क्षेत्र लोक संपर्क कार्यालयों के माध्यम से देशव्यापी अभियान आयोजित कर रहा है। इस महोत्सव को 'जनआंदोलन' का रूप देने के उद्देश्य से अनेकानेक आईसीओपी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सोशल मीडिया कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। बीओसी द्वारा चलाए जा रहे *आज़ादी का अमृत महोत्सव* कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं:

आइकॉनिक सप्ताह

- *'आज़ादी का अमृत महोत्सव'* आयोजनों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 23 से 29 अगस्त, 2021 तक 'आइकॉनिक सप्ताह' मनाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपे गए इस 'आइकॉनिक सप्ताह' के दौरान बीओसी ने 'संविधान के निर्माण' पर ई-फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका शुभारंभ केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में किया।

- इस सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) और क्षेत्र लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) ने विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं जिनमें शामिल हैं:

  - *देश भर में 88 आईसीओपी*
  - *लोक संचार प्रभाग के निजी पंजीकृत दलों की ओर से 1,016 सांस्कृतिक कार्यक्रम*

आज़ादी का अमृत महोत्सव पर इंफोग्राफिक श्रृंखला

- *'आज़ादी का अमृत महोत्सव'* आयोजनों के ही भाग के रूप में बीओसी ने स्वाधीनता संग्राम के भूले-बिसरे सेनानियों के सम्मान में व्हाट्सअप ग्रुपों पर उनकी स्मृति में इंफोग्राफिक सीरीज़ शुरू की।

- इन इंफोग्राफिक्स, ट्विटर ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट्स के माध्यम से इन भूले-बिसरे नायकों को याद किया गया।

- देश भर में कुल 385 व्हाट्सअप ग्रुपों में शामिल समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, एफएम केंद्रों, आउटडोर मीडिया एजेंसियों, मल्टीमीडिया एजेंसियों और शिक्षण संस्थानों के ओपीनियन लीडरों, स्थानीय प्रशासन, स्वैच्छिक संगठनों के क़रीब 8,11,177 लोग रोज़ाना संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं।

- स्वाधीनता संग्राम के अनेक भूले बिसरे नायकों/कम प्रचारित घटनाओं के बारे में 124 इंफोग्राफिक्स 12-01-2022 तक लोगों तक पहुंचाए गए।

- व्यापक वितरण के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी।

आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आईसीओपी, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम

- *आज़ादी का अमृत महोत्सव* मनाते हुए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और क्षेत्र लोक संपर्क ब्यूरो ने 418 समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी), 52 फोटो प्रदर्शनियां, 1,412 सांस्कृतिक कार्यक्रम और 245 अन्य कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित किए।

100 करोड़ टीकाकरण

- 100 वर्षों की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से निपटने के उद्देश्य से देश में 21 अक्तूबर, 2021 को 100 करोड़ टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की।

- इस अवसर पर बीओसी ने इस उपलब्धि के बारे में व्यापक अभियान शुरू किया। बीओसी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय ब्यूरो तथा क्षेत्र ब्यूरो ने देश भर में होर्डिंग, बैनर और स्टैंडीज लगाए।

- बीओसी ने इस संदेश के व्यापक प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों (पीएसयू) के सहयोग से नेटवर्किंग की और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 50,000 से ज्यादा होर्डिंग/बैनर डिस्प्ले किए।

- बीओसी के आरओबी और एफओबी ने ''लक्ष्य विशाल उपलब्धि बेमिसाल – भारत द्वारा 100 करोड़ टीकाकरण का सफर'' विषय पर 09 समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

"सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण" अभियान

- **प्रिंट विज्ञापन:** बीओसी ने ''सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण'' अभियान के बारे में देश भर में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आधे पृष्ठ का वर्टिकल (खड़ा) रंगीन विज्ञापन जारी किया। इस प्रिंट अभियान के तहत 15 भाषाओं के करीब 300 प्रमुख समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिए गए।
- **आउटडोर (बाहरी) अभियान :** भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रति अधिकतम लोगों तक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर के 6,100 विशेष स्थानों पर आउटडोर डिस्प्ले किए।
- **''सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण'' अभियान के पोस्टरों की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग अभियान :** कोविड-19 के मुफ्त टीकाकरण अभियान से जुड़ी जानकारी और पक्की करने तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से पोस्टर डिज़ाइन और प्रिंट करके सरकारी कार्यालयों के परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए।

''हेल्पलाइन नंबरों'' पर अभियान

- **चार राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों** – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर, बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और मनोवैज्ञानिक सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मई, 2021 में समाचार पत्रों के माध्यम से (स्ट्रिप ऐड) अभियान शुरू किया गया।
- **हेल्पलाइनों पर बल्क (बड़ी संख्या में) एसएमएस अभियान :** जून, 2021 में दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स (उपभोक्ताओं) को बल्क एसएमएस भेजे गए।
- **समाचार पत्रों में विज्ञापन :** कोविड-19 के बारे में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों पर भी दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों में स्ट्रिप विज्ञापन (रंगीन) जून, 2021 में जारी किया गया था।

सफ़ाई-दवाई और कड़ाई : जीतेंगे कोरोना से लड़ाई

- बीओसी ने अप्रैल, 2021 माह के दौरान एक और अभियान *''सफ़ाई-दवाई और कड़ाई : जीतेंगे कोरोना से लड़ाई''* भी शुरू किया।
- दिल्ली के सभी भागों और देश के अन्य हिस्सों में और विशेषकर सरकारी कार्यालयों तथा आवासीय क्षेत्रों में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, स्टैंडीज़ लगाए गए।

पीएम-किसान सम्मान निधि पर प्रिंट अभियान

- कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में पीएम-किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि ट्रांसफर करके भेजे जाने के बारे में बीओसी ने आधे पृष्ठ का अखिल भारत प्रिंट विज्ञापन जारी किया।
- प्री-वायब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2021 – ''राष्ट्रीय कृषि-राष्ट्रीय सम्मेलन'' के 15 दिसम्बर, 2021 को हुए आयोजन के बारे में बीओसी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरे पृष्ठ का अखिल भारतीय विज्ञापन (रंगीन) जारी किया गया।
- बीओसी ने सिखों के साथ विशेष संबंधों पर आधे पृष्ठ का अखिल भारतीय विज्ञापन जारी किया।

गांधी जयंती समारोह

- इस अवसर पर बीओसी ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों और चुनिंदा पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापन (रंगीन) जारी किया।
- 2 अक्तूबर, 2021 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन आरओबी/एफओबी ने 22 आईसीओपी जारी किए।

जनजातीय गौरव दिवस

- 15 नवंबर को भगवान् बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बारे में देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ का (रंगीन) प्रिंट विज्ञापन जारी किया गया।

- बीओसी ने भगवान् बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर, 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और क्षेत्र लोक संपर्क ब्यूरो ने इस अवसर पर 09 आईसीओपी तथा 08 वेबिनार आयोजित किए।

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

- राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भी बीओसी ने देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों और चुनिंदा पत्रिकाओं में रंगीन प्रिंट विज्ञापन जारी किया था।

- राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 52 आईसीओपी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में एकता की कड़ी को मज़बूत बनाने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में एकजुटता कायम रखने पर बल दिया गया।

स्वतंत्रता दिवस प्रिंट अभियान

- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीओसी ने देश भर के 1,700 समाचार पत्रों और चुनिंदा पत्रिकाओं में आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया। देश के करीब 4,000 अख़बारों और मैगज़ीनों में भी आधे पृष्ठ का सादा विज्ञापन दिया गया था।

- पहली बार स्वतंत्रता दिवस के प्रिंट विज्ञापन में क्यूआर कोड के माध्यम से वीडियो जोड़ा गया था। पारंपरिक मीडिया को डिजिटल मीडिया से जोड़ने का यह कार्य बीओसी ने किया था और इस प्रकार सरकारी संचार व्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो गई।

- बीओसी ने स्वयं का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। अगस्त के महीने में बीओसी ट्विटर हैंडल ने 5 लाख इंप्रेशन रिकॉर्ड किए।

टोक्यो ओलंपिक्स

- टोक्यो ओलंपिक, 2020 के पदक विजेताओं को बधाई देने के लिए बीओसी ने होर्डिंग्स डिजाइन करके खास-खास स्थानों पर लगाए थे।

- भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को उजागर करने के उद्देश्य से ओलंपिक खेलों की भावना को दर्शाने के लिए आरओबी और एफओबी ने सोशल मीडिया के माध्यम से गाने, नारे, वीडियो, क्विज़ (पहेलियां) आदि को साझा करके टोक्यो ओलंपिक्स के संदेश का ज़ोर-शोर से प्रचार किया।

भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी

- डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े नवाचार अपनाने के लिए भारत सरकार के फैसले के अनुरूप बीओसी ने इस वर्ष (2022) भी भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप तैयार किया जो किफायती, कुशल और प्रभावी है।

- इस ऐप में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, आयोजनों और प्रकाशनों के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध है। डिजिटल कैलेंडर से सरकारी अवकाश के दिनों और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी जानी जा सकती है।

- यह ऐप हिन्दी और अंग्रेजी के साथ ही भारत की 11 प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध है।

न्यू इंडिया समाचार

- भारत सरकार की पहलों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी का प्रसार करने के लिए बीओसी ने अगस्त, 2020 में पाक्षिक पत्रिका "न्यू इंडिया समाचार" शुरू की थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 2021-22 में भी चल रहा है।

- यह पाक्षिक पत्रिका 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है और सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, ज़िला परिषदों, संसद और राज्यों की विधानसभाओं, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सचिवों, शिक्षण संस्थानों तथा राज्य सरकारों के बड़े अधिकारियों आदि को इसकी कुल 4 लाख प्रतियां भेजी जाती हैं।

- न्यू इंडिया समाचार की ई-प्रतियां सभी 13 भाषाओं में फ्लिप बुक और पीडीएफ प्रारूप में MyGovIndia के ई-संपर्क प्लेटफॉर्मों के जरिए 6.50 करोड़ से ज़्यादा पाठकों को भेजी जाती हैं।

➢ न्यू इंडिया समाचार के बैनर को सभी 13 भाषाओं में निर्मित ई-मैगज़ीन के साथ मंत्रालयों, विभागों और सरकारी वेबसाइटों के होमपेज़ यानी मुखपृष्ठ पर होस्ट किया गया है।

आरओबी/एफओबी की अन्य जागरूकता गतिविधियां

सोशल मीडिया गतिविधियां

i) कोविड-19 पर जागरूकता अभियान और अन्य महत्वपूर्ण/प्रमुख कार्यक्रमः

अप्रैल 2021 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बाहरी गतिविधियों पर रोक लग जाने के बाद बीओसी के 23 आरओबी और 148 एफबीओ ने *टेलीफोन कॉल, एसएमएस, फेसबुक पोस्ट, ट्वीट और री-ट्वीट, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज और पोस्टर भेजने तथा वेबिनार* जैसे सोशल मीडिया की मदद से जागरूकता अभियान चलाया और कोविड-19 के प्रभाव को रोकने या कम करने, टीकाकरण की आवश्यकता लोगों को समझाने, भ्रांतियों को दूर करने, फेक न्यूज़ (अफवाहों) के प्रति सचेत करने, कोविड-19 से संबद्ध मुद्दों पर विशेषज्ञों की सलाह पहुंचाने, टीकाकरण के तहत 100 करोड़ खुराक देने की उपलब्धि लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सरकार के फैसलों और पहलों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।

ii) वेबिनारः

अप्रैल से दिसंबर, 2021 की अवधि में आरओबी ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार आचरण, वैक्सीनेशन रोल आउट, टीकाकरण के महत्व, होम आइसोलेशन (घर में सबसे अलग होकर रहना) और एहतियाती उपचार लेने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाने, काले फंगस पर विचार, महामारी के दौरान स्वच्छता, कोविड-19 से जुड़ी भ्रांतियां और तथ्य, सामान्य योग क्रियाएं, पर्यावरण-योग और कोविड रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य आदि विविध विषयों पर 920 वेबिनार आयोजित किए ताकि सुनिश्चित हो सके कि लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं और टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित हों।

iii) ऑनलाइन प्रतियोगिताएंः

आरओबी ने ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं जिनमें स्थानीय निकायों, स्कूलों, कॉलेजों, स्वैच्छिक संगठनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा तथा केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के साथ तालमेल रखकर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, टीकाकरण और भारत सरकार के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में योग वीडियो प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला और क्विज़ यानी पहली प्रतियोगिता इत्यादि शामिल थीं।

सोशल मीडिया गतिविधियों का विवरण

टेलीफोन कॉल्स की कुल संख्या	भेजे गए एसएमएस की कुल संख्या	फेसबुक पोस्टों की कुल संख्या	ट्वीट्स और री-ट्वीट्स की कुल संख्या	व्हाटसऐप पर जारी किए पोस्टरों/संदेशों/वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्टों की संख्या	इंप्रेशंस	वेबिनार
1,35,643	1,16,831	1,64,565	5,48,681	7,61,469	56,224	72,77,651	920

समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी)

लॉकडाउन के बाद के दौर में बीओसी ने आरओबी और एफओबी के माध्यम से 760 आईसीओपी आयोजित किए और भारत सरकार की कल्याण योजनाओं तथा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) और टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आईसीओपी में जनसभाएं, सार्वजनिक घोषणाएं, पब्लिक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट-प्ले और लोकनृत्य आदि), प्रदर्शनियां, खेल/पेंटिंग/कविता/रंगोली/क्विज़ (पहेली) प्रतियोगिता, चर्चा/गोष्ठी आदि तथा पैम्फलेट वितरण जैसे कार्यक्रम शामिल थे।

जागृति रथ अभियान (मोबाइन वैन):

देश भर के कुछ आरबीओ ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और उपयुक्त व्यवहार तथा टीकाकरण अभियान, सरकार की अन्य योजनाओं और नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कोविड जागृति रथ अभियान चलाए जिनमें मोबाइल वैन/ई-रिक्शा/ट्राई साइकिल आदि की मदद ली गई।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी):

एफओबी/आरओबी ने फिर भी विशेष रूप से युवा वर्ग और विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों से ईबीएसबी के बारे में क्विज़, वाद-विवाद, पेंटिंग्स, देशभक्ति के गीत और निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। उन्होंने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर ईबीएसबी के बारे में 32 वेबिनार भी आयोजित किए।

लॉकडाउन के बाद जुलाई, 2021 से बीओसी के सभी आरओबी और एफओबी ने कोविड उपयुक्त व्यवहार और नियमों-सावधानियों का पालन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पर 20 आईसीओपी और 15 अन्य क्षेत्र कार्यक्रमों का आयोजन किया।

पोषण माह

अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 के दौरान एफओबी/आरओबी ने 'पोषण सप्ताह और पोषण माह' से जुड़े विषयों पर कुल 41 वेबिनार आयोजित किए। लॉकडाउन के बाद की अवधि में जुलाई, 2021 से बीओसी के सभी आरओबी और एफओबी ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र कार्यक्रम शुरू कर दिए और पोषण अभियान अर्थात् पोषण सप्ताह और पोषण माह के दौरान 127 समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी) आयोजित किए।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां :-

टेलीफोन कॉल्स की कुल संख्या	भेजे गए एसएमएस की कुल संख्या	फेसबुक पोस्ट की संख्या	ट्वीट्स और री-ट्वीट्स की संख्या (इंप्रेशन सहित)	व्हाटसऐप पर भेजे पोस्टर/ मैसेज/ वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या	आयोजित वेबिनार की कुल संख्या	आयोजित आईसीओपी की कुल संख्या
49,554	64,265	32,665	1,55,312	2,15,664	10,56,179	174	48

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां :-

आरओबी से किए गए कुल फोन कॉल	आरओबी से भेजे गए कुल एसएमएस	फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्वीट्स और री-ट्वीट्स की संख्या (इंप्रेशन सहित)	व्हाटसऐप पर भेजे पोस्टर/ मैसेज/ वीडियो	कुल इंस्टाग्राम पोस्ट	आयोजित वेबिनार की कुल संख्या
10,420	4,955	15,109	24,563	20,923	2,582	88

सूचना रथों की संख्या	एसओपी की कुल संख्या	आईसीओपी की कुल संख्या	सांस्कृतिक कार्यक्रम
3	31	47	152

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

जून के महीने में सभी आरओबी/एफओबी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2021) को सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मनाया। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को आरओबी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रचारित किया गया।

आरओबी ने योग दिवस पर ऑनलाइन वर्चुअल योग सत्र भी आयोजित किए और आम लोगों में योग अपनाने की प्रेरणा जगाने के लिए आयोजित लाइव योगाभ्यास में जाने-माने विशेषज्ञों, योग संगठनों और पत्रकारों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आरओबी ने ''वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में योग की प्रासंगिकता'' और ''योग तथा मानसिक स्वास्थ्य'' जैसे विषयों पर सामान्य योग प्रक्रियाओं के बारे में 75 वेबिनार आयोजित किए। आरओबी ने राज्यों के आयुष मिशन के सहयोग से लोगों को स्वस्थ और फिट रखने में योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से जाने-माने योग प्रशिक्षकों की देखरेख में 25 लाइव योग प्रदर्शन आयोजित किए।

संविधान दिवस

आरओबी/एफओबी ने संविधान दिवस पर 34 आईसीओपी आयोजित किए। ''भारत के संविधान'' और ''नागरिकों के मूल दायित्वों'' से जुड़े विषयों पर आरओबी ने 10 वेबिनार आयोजित किए। उन्होंने इन कार्यक्रमों में क्विज़, वाद-विवाद, पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी कराई ताकि लोगों को और विशेषकर युवा पीढ़ी को अधिक जागरूक बनाने में मदद मिले।

सांख्यिकीय आंकड़े (अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 की उपलब्धियां)

1.	आईसीओपी की कुल संख्या	760
2.	मोबाइल वैन/जागृति रथ अभियान के कुल दिनों की संख्या	5,300
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुल संख्या	1,230
4.	अन्य कार्यक्रमों की कुल संख्या	270
5.	वेबिनार्स की कुल संख्या	920

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय आरएनआई की स्थापना 1956 में प्रथम प्रेस आयोग की 1953 की सिफारिश के आधार पर प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 में संशोधन करके की गई थी। आरएनआई सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और यह विधायी तथा ग़ैर-विधायी दायित्वों का निर्वहन करता है।

आरएनआई के कार्य

आरएनआई देश भर में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों और प्रकाशनों का रजिस्टर रखता है, **समाचारपत्रों और प्रकाशनों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करता है,** नए समाचारपत्रों के शीर्षक की स्वीकृति के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जानकारी देता है तथा समाचारपत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। आरएनआई देश में प्रिंट मीडिया की स्थिति के बारे में ''प्रेस इन इंडिया'' शीर्षक से हर वर्ष 31 दिसंबर को वार्षिक रिपोर्ट भेजता है।

अपने गैर-सांविधिक कार्यों के अंतर्गत **यह कार्यालय आरएनआई से पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अख़बारी काग़ज के आयात के लिए स्वघोषणा प्रमाणपत्र को प्रमाणित करता है।** यह कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोध या सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पीआईबी के निर्दिष्ट अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत प्रकाशनों के प्रसार का सत्यापन भी करता है।

शीर्षक सत्यापन

अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2021 की अवधि में आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन के 7,519 आवेदनों की जांच की जिनमें से 3,809 शीर्षकों को स्वीकृति दी गई। इन सभी स्वीकृत शीर्षकों की सूची आरएनआई की वेबसाइट - www.rni.nic.in

पर उपलब्ध है। शीर्षक सत्यापन स्थिति पत्र भी आरएनआई की वेबसाइट पर है जिसे आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं।

शीर्षकों पर से रोक हटाई गई

अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 के बीच 276 शीर्षकों पर से रोक हटा ली गई और आवेदक चाहें तो स्वयं पुष्टि कर सकते हैं।

पंजीकरण

31 मार्च, 2021 को कुल पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1,44,250 थी जिनमें 20,512 दैनिक समाचारपत्र और 1,24,008 अन्य पत्रिकाएं हैं। 1 अप्रैल, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि में 844 (नए और संशोधित) प्रकाशन पंजीकृत किए गए हैं। आरएनआई के रजिस्टर में भी इस आशय की प्रविष्ट की जाती है। सभी पंजीकृत समाचारपत्रों और प्रकाशनों का विवरण भी आरएनआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19डी के अनुसार प्रकाशक को अपना वार्षिक विवरण हर वर्ष 31 मई को या उससे पहले प्रेस पंजीयक को समाचारपत्र पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 में निर्दिष्ट फॉर्म 2 में भरकर सौंपना अनिवार्य है। प्रकाशकों को हर वर्ष फरवरी के अंतिम दिन के बाद वाले पहले प्रकाशन में फॉर्म IV में अपने प्रकाशन के स्वामित्व के बारे में पूरा विवरण छापना होगा। 2020-21 के लिए 32,938 प्रकाशनों की ओर से वार्षिक विवरण भरा गया है।

2013-14 में शुरू की गई वार्षिक विवरण ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

ऑटोमेशन

वर्तमान में शीर्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्यूटर चालित है और सभी सत्यापित/स्वीकृत शीर्षक आरएनआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। यह सुविधा शुरू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति या प्रकाशक बनने का इच्छुक व्यक्ति शीर्षकों के मौजूदा डाटाबेस को देख सकता है जो राज्यवार/भाषावार उपलब्ध रहता है। डिजिटीकरण के दूसरे चरण में पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया सहित कार्यालय संबंधी विभिन्न प्रक्रियाएं भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएंगी।

'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अनुसार, प्रेस पंजीयक केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें भारत में समाचारपत्रों के बारे में पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं का सारांश शामिल होता है। 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट हर साल दिसंबर में सौंपी जाती है। 2013-14 से 'प्रेस इन इंडिया' डिजिटल प्रारूप में भी लाई जा रही है और यह आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रसार सत्यापन

प्रकाशनों की नियमित प्रसार जांच/सत्यापन किया जाता है, ताकि प्रकाशनों द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट में जमा किए गए प्रसार डाटा/आंकड़ों की पुनर्पुष्टि हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार 1 अगस्त, 2020 से 25 हजार से ऊपर के प्रसार का दावा करने वाले प्रकाशनों के लिए आरएनआई/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) द्वारा प्रसार सत्यापन अनिवार्य बना दिया है।

अख़बारी कागज़

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात-निर्यात नीति के अनुसार अख़बारी कागज़ के आयात के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त पर आरएनआई और पीआईबी के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय आरएनआई में पंजीकृत प्रकाशनों के स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करते हैं। **आरएनआई ई-संचित के माध्यम से अख़बारी कागज़ के आयात के लिए अब क्रेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय में काम कर रहा है।**

राजभाषा

आरएनआई के कार्यालय ने सितंबर, 2021 में *हिंदी पखवाड़ा* का आयोजन किया, जिसमें कार्यालयी कामकाज में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्याक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

शिकायतें और सूचना का अधिकार (आरटीआई)

इस कार्यालय में जन शिकायत कक्ष भी है। प्रकाशक अपनी शंका या प्रश्न pqrc-rni@nic.in पर सीधे ई-मेल करके या आरएनआई की वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं।

उप प्रेस पंजीयक स्तर के एक अधिकारी इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण केंद्र के प्रमुख हैं। अप्रैल से नवंबर, 2021 के बीच आरटीआई के तहत प्राप्त 376 आवदेनों का जवाब दिया गया था।

सिटीजन चार्टर

सिटीजन चार्टर बनाया गया है और उसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर डाला गया है।

प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले प्रकाशन विभाग (डीपीडी) की स्थापना 1941 में की गई थी। यह सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित विभाग के रूप में उभरकर सामने आया है जो भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और इतिहास, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों तथा संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और साहित्य आदि क्षेत्रों की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की विरासत को प्रदर्शित और संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान संपदा को समृद्ध बना रहा है। प्रकाशन विभाग भारतीय समाज और पठनीयता पर विशेष ध्यान रखने के साथ राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों, समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। इनके अतिरिक्त, विभाग कथात्मक और ग़ैर-कथात्मक बाल साहित्य भी प्रकाशित करता है। डीपीडी *''इंडिया''* और *''भारत''* संदर्भ ग्रंथों का नियमित और अनिवार्य रूप से प्रकाशन कर रहा है।

प्रकाशन विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खण्डों में अंग्रेजी में ***कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी)*** शामिल है। इसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का ई-संस्करण (ई-सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है। सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में यह उपलब्ध है, इसमें विषयों को आसानी से खोजा जा सकता है। यह

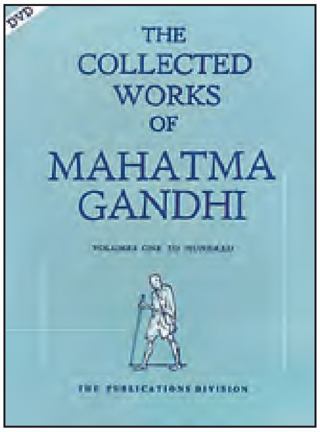

गांधी हैरिटेज पोर्टल पर भी उपलब्ध है। डीपीडी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहयोग से महात्मा गांधी के बारे में व्यापक ई-संग्रह ''गांधी फॉर डिजिटल इरा'' को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं- *योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती* और *आजकल* तथा साप्ताहिक पत्र *रोज़गार समाचार* प्रकाशित करता है। इन पत्रिकाओं में आर्थिक विकास, संस्कृति, बाल साहित्य और रोज़गार तथा कैरियर से जुड़े अवसरों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

विशेषताएं और उपलब्धियां

- प्रकाशन विभाग ने माननीय राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर उनके **चुने हुए भाषणों** के संकलन, एक अंग्रेजी में और एक हिन्दी में प्रकाशित किए। इन संकलनों के शीर्षक हैं *रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम IV और लोकतंत्र के स्वर खंड 4* जिनमें कुल 38 भाषण शामिल हैं जिन्हें न्याय के आदर्श, समानता, भाईचारा, अहिंसा, विश्व बंधुत्व (वसुधैव कुटुम्बकम), जैसे आदर्शों समग्र विकास, आधुनिक दिशाएं और नीतिगत विकास तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की विशेष समस्याएं जैसे विषयों के आधार पर 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- भारत के **माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडु के अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर** *रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रीकनेक्टिंग* शीर्षक से **एक कॉफी टेबल बुक** प्रकाशन विभाग की ओर से प्रकाशित की गई। कोविड-19 प्रोटोकोल (नियमों) के कारण इस पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित नहीं किया गया। यह पुस्तक नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2021

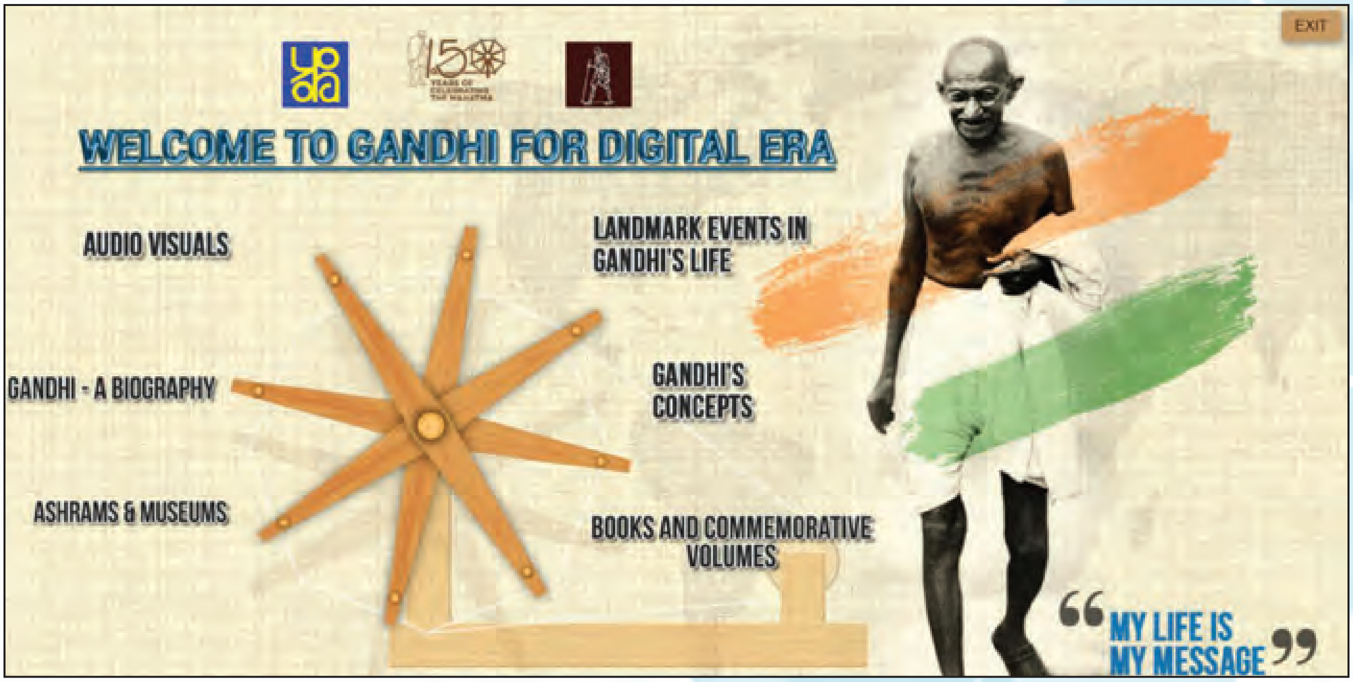

को माननीय उपराष्ट्रपति को भेंट की गई। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्र और संयुक्त सचिव (पीएंडडी) श्री विक्रम सहाय इस आयोजन में उपस्थित थे। 183 पृष्ठों की इस पुस्तक में माननीय उपराष्ट्रपति की देश में यात्राओं सहित उनकी विविध गतिविधियों को शब्दों और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

- प्रकाशन विभाग ने **2021 के लिए पुस्तक में उत्कृष्टता के लिए दस पुरस्कार** प्राप्त किए। ये पुरस्कार नई दिल्ली में 17 सितंबर, 2021 को आयोजित समारोह में भारतीय प्रकाशक परिसंघ ने प्रदान किए।

*केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु को नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2021 को **रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रीकनेक्टिंग** शीर्षक पुस्तक की पहली प्रति भेंट करने के अवसर पर। उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ आई वी सुब्बा राव, सूचना और प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्र तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।*

- नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत सभी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित और संस्थागत बनाया जा रहा है। प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) (दिव्यांगजन) के साथ मिलकर **दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल पुस्तकें, कम दृष्टि (विज़न) वाले लोगों के लिए बड़े फोंट वाली और श्रव्यता बाधितों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में ऑडियो पुस्तकों** को निकालने (निर्माण करने) की प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह एक नई पहल है और अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। डीपीडी मांग होने पर ऐसी पुस्तकों का उत्पादन करना चाहता है और एनआईईपीवीडी के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है।

- प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली के सूचना भवन में 7 सितंबर, 2021 को आयोजित समारोह में शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक एवं शिक्षाशास्त्री कस्तूरी पाइगुडे की लिखी पुस्तक **''पंडित भीमसेन जोशी : सेलिब्रेटिंग हिज़ सेंटेनरी''** का विमोचन जानेमाने ध्रुपद गायक पद्मश्री उस्ताद वसिफुद्दीन डागर और युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और साहित्य प्रोत्साहन सोसायटी (स्पिक मैके) के संस्थापक डॉ. किरण सेठ की उपस्थिति में किया।

- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तमिल साहित्य के महानतम कवियों में शामिल महाकवि सुब्रमण्य भारती को तमिलनाडु के थूतुकुडी ज़िले में उनके जन्मस्थान एट्यपुरम में आयोजित समारोह में उनके बारे में डीपीडी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया।

- प्रकाशन विभाग ने 23 से 29 अगस्त, 2021 तक **'आज़ादी का अमृत महोत्सव'** पर आइकॉनिक सप्ताह मनाया। इस सप्ताह में डीपीडी ने पोडकास्ट सीरीज़ ***''जश्न-ए-आज़ादी''*** शुरू की जिसमें डीपीडी द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों की समीक्षा और उन पर चर्चा शामिल है। ये ऐपिसोड स्पॉटिफाई और अमेज़न प्राइम म्यूज़िक जैसे प्रमुख पोडकॉस्टिंग प्लेटफॉर्मों और डीपीडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध है।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तक प्रकाशन

प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल 160 पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनमें से 43 अंग्रेजी में, 99 हिन्दी में और 18 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की गईं। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं : भारत के राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में दिए चुने हुए भाषण- *रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम IV (अंग्रेजी)* और *लोकतंत्र के स्वर खंड 4 (हिन्दी में), कॉफी टेबल बुकः रिफ्लेक्टिंग, रीकलेक्टिंग, रीकनेक्टिंग* जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चौथे वर्ष में दिए गए उनके भाषण हैं; गुजराती और तमिल में प्रकाशित पुस्तक *भारत के न्यायालय- अतीत से वर्तमान तक*। डीपीडी से प्रकाशित अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं- *वॉरियर डेमौक्रेटः श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी-ए लाइफ इन पिक्चर्स, भीमसेन जोशी-सेलेब्रेटिंग हिज़ सेंटेनरी, बीइंग एफटीआईआई;* और *बैलेसिंग द विज़डम ट्री- एंथोलॉजी ऑफ विमेन एल्यूमनी*। भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की ये दोनों पुस्तकें इस प्रमुख संस्थान के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में प्रकाशित की गई थीं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रकाशन विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। इस श्रृंखला के तहत दिसंबर, 2021 तक विभाग ने छः पुस्तकें- अंग्रेजी में *''द स्टोरी ऑफ*

पार्टिशन'' तथा *''द स्टोरी ऑफ रिहेबिलिटेशन''* और हिन्दी में भारत विभाजन की कहानी, *ज़ब्तशुदा गीत* और *ज़ब्तशुदा तराने* प्रकाशित की थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रृंखला की 10 से 12 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं।

डीपीडी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में नई दिल्ली के सूचना भवन स्थित पुस्तक दीर्घा में तथा कोलकाता, मुंबई, तेलंगाना और बिहार में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित कीं जिनमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माताओं, आदि के बारे में पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं। इन पुस्तक प्रदर्शनियों में वर्चुअल प्रदर्शनी भी शामिल है।

योजना, कुरुक्षेत्र, बालभारती और *आजकल* ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़ी गतिविधियों के बारे में अनेक विशेष लेख, सचित्र कोलॉज और अभिलेख आधारित चित्र प्रकाशित किए। रोज़गार समाचार ने भी स्वतंत्रता के भूले बिसरे सेनानियों और नायकों के बारे में एक श्रृंखला शुरू की।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

वर्तमान में चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विचार-विमर्श और आपसी सूझबूझ को बढ़ावा देना है। इसके तहत आपसी संबंधों को और मज़बूत बनाने के वास्ते भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन खेलकूद और श्रेष्ठ रीति रिवाज़ों को समझने-अपनाने के लिए सतत् सांस्कृतिक संपर्क को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रकाशन विभाग भी इस श्रृंखला के अंतर्गत पुस्तकें/अपनी पत्रिकाओं के विशेषांक निकाल रहा है। युवाओं के लिए प्रेरक सामग्री वाली और देश की सांस्कृतिक विविधता को महत्व देने वाली 15 पुस्तकें देश की 15 भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए चुनी गई हैं। दिसंबर, 2021 तक 160 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इनके अलावा, कई पुस्तकों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है जिनमें *गांधी कथा, दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार और सन् सत्तावन के भूले-बिसरे शहीद* शामिल हैं। इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जिनमें योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भाषाओं में), *कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी और हिन्दी में), *आजकल* (हिन्दी और उर्दू में) और *बाल भारती* (हिन्दी में) शामिल हैं और इनके अलावा *एंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार साप्ताहिक पत्रिका* है जो अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होती है। इन पत्रिकाओं ने वर्षभर अपने निर्धारित विषयों पर लेखों के साथ ही अमृत महोत्सव तथा गांधीजी के जीवन, आदर्शों और विचारों पर लगातार लेख प्रकाशित किए।

➢ ***योजना* (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)**

1957 से प्रकाशित योजना आर्थिक विकास के प्रति समर्पित पत्रिका है और इसका प्रकाशन 13 भाषाओं- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में होता है।

देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस वर्ष योजना के विभिन्न अंकों में इस विषय पर नियमित रूप से लेख शामिल किए गए। जनवरी, 2022 में तो आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित किया गया था जिसमें विज्ञान, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, विकास और लोगों तथा समाज के क्षेत्रों में विकास को उजागर किया गया था। इस संग्रहणीय अंक में ''इंडिया ऐज़ ए स्पेस पॉवर (भारत अंतरिक्ष शक्ति के रूप में), ''इकॉनोमिक ट्रांसफोर्मेशन'' (आर्थिक क्रांति), ''स्वदेशी आंत्रप्रेन्योरशिप'' (स्वदेशी उद्यमिता), और ''रोल ऑफ मीडिया'' (मीडिया की भूमिका) जैसे लेख प्रकाशित किए गए जिनके लेखकों में इसरो के पूर्व प्रमुख के. सिवन, आईआईटीएफ के वाइस चांसलर मनोज पंत और आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं। पत्रिका के अन्य विशेषांक *जल जीवन मिशन, पंचायती राज और बजट* विषयों पर प्रकाशित किए गए। इनके अतिरिक्त, *आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लोक प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण तथा नारी शक्ति* आदि विषयों पर भी पत्रिका के अंकों में लेख प्रकाशित हुए। ***योजना*** हिन्दी और ***योजना*** अंग्रेजी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें युवा पाठकों से लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव और योगदान लिखने को कहा गया था।

➢ ***कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी और हिन्दी)**

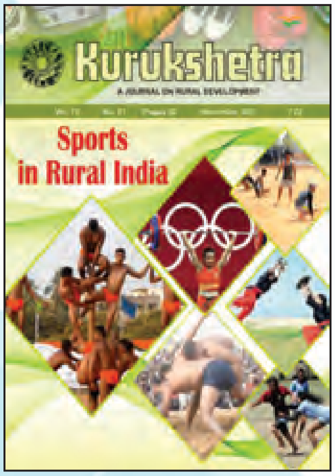

कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन विभाग प्रकाशित करता है। 1952 से प्रकाशित हो रही यह पत्रिका विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक लेखों के माध्यम से ग्रामीण विकास का संदेश सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा रही है।

अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि में *कुरुक्षेत्र* ने विशेषांक निकालने के साथ ही सरकार की पहलों और कार्यक्रमों पर विशेष सामग्री प्रकाशित की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लेख इसमें शामिल किए गए। लेखों और इंफोग्राफिक्स के जरिए कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक बनाने पर विशेष बल दिया गया। पत्रिका के लेखों में ग्रामीण विकास, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, साफ-सफ़ाई, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यापक जानकारी दी जाती है। विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग और जानेमाने विशेषज्ञ पत्रिका के लेखकों में मुख्य रूप से शामिल रहते हैं।

➢ ***आजकल* (हिन्दी और उर्दू)**

हिन्दी में 75 वर्ष से भी अधिक समय से प्रकाशित हो रही *'आजकल'* साहित्य और संस्कृति की प्रारंभिक पत्रिकाओं में से है। हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद युग के बाद के क्रांतिकारी उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती पर अप्रैल, 2021 में पत्रिका ने विशेषांक निकाला। पत्रिका के एक अंक में बाल साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर सामग्री शामिल की गई थी। विगत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी कविताओं, कहानियों, पुस्तक समीक्षा आदि के माध्यम से हिन्दी साहित्य को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। पत्रिका के लेखकों में कई दशकों से कवि, पत्रकार और अनेक पत्रिकाओं के संपादक रहे मंगलेश डबराल, सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित जानेमाने मराठी कवि और साहित्य आलोचक शरणकुमार निंबाले और बांग्ला कवि तथा समालोचक शंख घोष जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं।

➢ ***बालभारती* (हिन्दी)**

बाल भारती, बच्चों पर केंद्रित एक विशेष पत्रिका, 1948 से लगातार प्रकाशित हो रही है। मासिक रूप से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, सूचनात्मक लेखों, साक्षात्कारों, लघु कथाओं, कविताओं, प्रश्नोत्तरी और चित्रात्मक शृंखला के माध्यम से बच्चों में सामाजिक मूल्यों को प्रदान करने में मदद करती है। बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव और कोविड-19 के प्रति जागरूकता तथा सावधानियों पर विशेष ज़ोर दिया गया। जुलाई 2021 में कोविड-19 विशेषांक प्रकाशित किया गया था। बाघा जतिन, बिरसा मुंडा और ज़ीनत महल जैसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर अंक में शृंखलाबद्ध चित्रकथाएं और विशेष लेख प्रकाशित किए गए।

➢ ***एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार* (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू)**

1976 में शुरु किया गया *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार* सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख रोज़गार साप्ताहिक पत्र है, जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में रोज़गार की सूचना प्रदान करने वाली सिंगल विंडो (एकल खिड़की) के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचनाओं, परीक्षा सूचनाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) तथा अन्य सामान्य भर्ती संस्थाओं के परिणामों का भी प्रकाशन

करता है।

पुस्तक मेलों/आयोजनों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

मुख्यालय की व्यापार शाखा और उसके क्षेत्रीय कार्यालय अंतरराष्ट्रीय आयोजनों सहित विभिन्न स्तरों पर निरंतर पुस्तक मेले आयोजित करते रहते है और इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेते रहते हैं।

(क) ***वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला 2021:*** डीपीडी ने 3 सितंबर, 2021 से 5 सितंबर, 2021 तक आयोजित वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेले के दूसरे संस्करण में भाग लिया। इसका आयोजन भारतीय प्रकाशक परिसंघ ने किया था। मेले के वर्चुअल मंडपों के जरिए डीपीडी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव में अपने प्रकाशनों को प्रदर्शित किया और उनकी बिक्री भी की।

(ख) ***शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला:*** प्रकाशन विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के एक्सपो सेंटर में 3 नवंबर से 31 नवंबर, 2021 तक आयोजित 40वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। इस अंतरराष्ट्रीय मेगा पुस्तक मेले में डीपीडी के मंडप (स्टॉल) का उद्घाटन दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. अमन पुरी और वाणिज्यदूत (प्रेस, सूचना, संस्कृति और श्रम) श्रीमती ताडू मामू ने मिलकर किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोहों को जारी रखते हुए प्रकाशन विभाग ने पाठकों और पुस्तक प्रेमियों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में 150 से ज्यादा पुस्तकें प्रस्तुत कीं। पाठकों को कला और साहित्य, भारत के इतिहास, विशिष्ट व्यक्तियों, भाषा और साहित्य, गांधीवादी साहित्य, धर्म और दर्शन, तथा बाल साहित्य के बारे में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकें और पत्रिकाएं देखने का अवसर मिला तथा राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष संकलन भी उन्हें देखने को मिला जिसे प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया था।

(ग) ***आज़ादी का अमृत महोत्सव :*** अप्रैल से नवंबर, 2021 की अवधि में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विषय पर विभिन्न स्थलों पर 11 प्रदर्शनियां आयोजित की थीं, 8 का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय परिसरों के बाहर किया गया था और एक चर्चा कार्यक्रम के रूप में थी, जिनमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और स्वाधीनता संग्राम के गौरवपूर्ण संघर्ष को दर्शाया गया था। इन प्रदर्शनियों में डीपीडी मुख्यालय और उसके देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों पर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पुस्तकें प्रदर्शित की गईं तथा इन पुस्तकों की बिक्री की गई।

भारतीय जन संचार संस्थान
(आईआईएमसी)

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त 1965 को अस्तित्व में आया, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 के XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसे मीडिया और जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों के बुनियादी उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया। गत 56 वर्षों में संस्थान ने अपनी स्थापना के मूल लक्ष्य "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना तथा प्रचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शोध और प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने" के अनुरूप आधुनिक युग में तेज़ी से विस्तृत होते हुए और बदलते हुए

मीडिया उद्योग की विविध और चुनौतीपूर्ण ज़रूरतें पूरी करने के उद्देश्य से कई विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और उनका सफल प्रबंधन किया है।

आईआईएमसी को 2021 में एक बार फिर ''इंडिया टुडे ग्रुप'', ''आउटलुक आई-केयर'' और ''द् वीक'' पत्रिका ने भारत में जन संचार क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में प्रथम स्थान दिया। सत्यापित फेसबुक पेज, सक्रिय ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल सहित सोशल मीडिया पर संस्थान की सक्रिय मौजूदगी है। संस्थान की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भेजी और प्रचारित की जाती हैं। संस्थान के आधिकारिक इंस्टाग्राम अक़ाउंट का सत्यापन/प्रमाणीकरण हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर संस्थान की मौज़दूगी और अधिक प्रभावी हो गई है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

आईआईएमसी प्रिंट पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिन्दी, ओड़िया, उर्दू, मराठी और मलयालम भाषा में), रेडियो और टीवी पत्रकारिता तथा विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। कोविड-19 महामारी फैलने के कारण संस्थान ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 के अधिकांश समय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन संचालित किया तथा कोविड-19 ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए यदि स्वीकृति मिल गई तो जनवरी, 2022 में ऑफ लाइन कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, आईआईएमसी द्वारा आयोजित 5 दिन के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 25 शहरों के 33 केंद्रों पर 29.08.2021 को आयोजित प्रवेश परीक्षा में संस्थान के सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कुल 5,345 प्रत्याशी बैठे थे जिनमें से 418 प्रत्याशियों को प्रवेश दिया गया।

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) ने शिक्षण सत्र 2021-22 के सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए 25 अक्तूबर से 29 अक्तूबर तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। प्रमुख नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के विद्वानों ने ओरिएंटेशन लेक्चर दिए और उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया।

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

आईआईएमसी 1965 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस), जो उस समय केंद्रीय सूचना सेवा (सीआईएस) थी, की प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य कर रहा है। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण देता है। संस्थान पत्रकारिता के पूर्व अनुभव के आधार पर भर्ती किए गए आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों को भी बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

वर्ष 2021–22 में आईआईएस ग्रुप 'ए' (2019 और 2020 बैच) के 16 प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) जनवरी, 2021 में शुरू किया गया जो नवंबर, 2021 में पूरा हुआ। इस बीच, 2018 बैच के 15 प्रशिक्षु अधिकारियों ने जुलाई, 2021 में और 2019 बैच के 03 प्रशिक्षु अधिकारियों ने जनवरी, 2022 में अपनी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पूरी कर ली और 2 वर्ष की प्रोबेशन/ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें नियमित पोस्टिंग मिल गई।

मार्च, 2022 में 2021 बैच के 20 प्रशिक्षु अधिकारियों और 2020 बैच के कुछ प्रशिक्षु अधिकारियों के नए बैच की इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू की गई।

विकास पत्रकारिता

आईआईएमसी का विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम अनुभव, विशेषज्ञता और नवाचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से विशेषकर विकासशील देशों के बीच सहयोग और आपसी सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास है। यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीसीई)/अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) और कोलम्बो योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

2020 में हुए 72वें विकास पत्रकारिता डिप्लोमा कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रतिबंधों, खासकर कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा और वीज़ा प्रतिबंधों की वजह से भारतीय जन संचार संस्थान ने विकास पत्रकारिता का कोई पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

संचार अनुसंधान और लोक संपर्क गतिविधियां

आईआईएमसी एशिया का ऐसा पहला संस्थान है जिसमें एक समर्पित संचार अनुसंधान विभाग है जो विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लिए अनुसंधान विश्लेषण और प्रभाव का आकलन करता है। अनुसंधान मुख्य रूप से सरकारी अभियानों पर केंद्रित रहता है और मंत्रालयों को उनके अभियानों की और संचार कार्यक्रमों की नीति तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले इनपुट उपलब्ध कराता है। इस विभाग ने गत 56 वर्षों में जनस्वास्थ्य से ग्रामीण विकास और मीडिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक शोध अध्ययन करके संचार-अध्ययन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई है।

विभाग द्वारा जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि में चलाई गई और चल रही प्रमुख शोध और प्रशिक्षण गतिविधियां नीचे दी जा रही हैः

i) स्वास्थ्य साक्षरता के बारे में टीवी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव : लोकसभा टीवी के *हेल्दी इंडिया* कार्यक्रम (भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रचालित) के प्रभाव का आकलन;

ii) प्रभाव आकलन *''डाकघरों के माध्यम से जागो ग्राहक जागो अभियान''* (भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित);

iii) मेघालय के मूल निवासी समुदायों में व्यवहार परिवर्तन की संचार नीति विकसित करना (मेघालय बेसिन प्रबंधन एजेंसी-एमबीएमए, मेघालय सरकार, भारत द्वारा संचालित और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित)।

सामुदायिक रेडियो

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 2015 से ही ''अपना रेडियो 96.9'' नाम से अपना सामुदायिक रेडियो चला रहा है। इस रेडियो ने वर्ष 2021 में लोगों तक मनोरंजन और जानकारी पहुंचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई।

कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके बाद लगे लॉकडाउन के दौरान *अपना रेडियो* को बड़ा समर्थन मिला और यह लोगों तक जानकारी पहुंचाने का विश्वस्त माध्यम बना रहा। इसने लोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जिनसे समुदाय के लोगों में भरोसा, उम्मीद और विकास जगाने में मदद मिली। इन कार्यक्रमों में उपचार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पोषाहार, कोविड के बाद की देखभाल, योग, रोग-प्रतिरोधक क्षमता और टीकाकरण, स्थानीय समाचार और सूचनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

संचार पत्रिकाएं, मैगज़ीन और पाठ्य पुस्तकें

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का प्रकाशन विभाग दो समीक्षागत शोध जर्नल-'कम्युनिकेटर' (अंग्रेजी त्रैमासिक) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी छमाही) का प्रकाशन करता है। ये भारत में प्रकाशित होने वाले सबसे पुराने संचार जर्नल हैं। इन प्रमुख जर्नलों में संचार से संबंधित मूल शोध प्रकाशित किए जाते हैं और विद्वानों, पेशेवर लोगों और नीति निर्माताओं के अधिकाधिक लाभ की दृष्टि से संचार और अन्य संबद्ध शाखाओं का सर्वोत्तम साहित्य इसमें प्रकाशित करने का प्रयास किया जाता है।

आईआईएमसी के विभिन्न प्रकाशन

पंडित युगल किशोर शुक्ला पुस्तकालय और ज्ञान शोध केंद्र

वर्ष 2021 में भारतीय जन संचार के पुस्तकालय का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ला पुस्कालय और ज्ञान शोध केंद्र रखा गया। संस्थान का यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा जन संचार पुस्तकालय है। इसमें जन संचार के विभिन्न पहलुओं तथा प्रिंट मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार शोध, जनसंपर्क, रेडियो और टेलीविजन, फ़िल्म, सूचना टेक्नोलॉजी और पंरपरागत मीडिया जैसे संबद्ध विषयों पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की करीब 37,608 पुस्तकें और सजिल्द जर्नल संग्रहित हैं।

योजना स्कीम और ढांचागत सुविधाओं का विकास

11वीं पंचवर्षीय योजना में 'आईआईएमसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उन्नयन करने की योजना को शामिल किया गया था और कुल 62.0 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में आईआईएमसी का उन्नयन, यानी आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण, साथ ही महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और जम्मू में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय परिसरों की शुरुआत शामिल है। जनवरी, 2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली में आईआईएमसी की नई अतिरिक्त इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति दे दी है पर इसके लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की शर्तों का पालन करना होगा। इस योजना स्कीम के साथ ही, आईआईएमसी को नई *"दे नोवो"* श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बदलने का प्रस्ताव भी 2017 से विचाराधीन है और प्रस्ताव आगे बढ़ने पर कई ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना होगा।

शिक्षण उपकरण/सुविधाएं

संस्थान अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त और उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है ताकि विद्यार्थी इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बन सकें। इन सुविधाओं का लगातार उन्नयन किया जा रहा है और वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण कक्षाएं ऑनलाइन चलाई गईं। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारियों को जुलाई, 2020 से **गूगल मीट, जी-सूट, वेबेक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्ट्रीमयार्ड** और **गो टू वेबिनार** जैसे विविध ऑनलाइन शिक्षण सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया।

नागरिक घोषणापत्र और शिकायत निवारण कक्ष

नया नागरिक घोषणापत्र आईआईएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। संस्थान के एक अधिकारी को लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और मिलने वाली शिकायतों की संस्थान द्वारा जांच की जाती है तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इनका तुरंत निपटारा किया जाता है।

एससी/एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु दिल्ली परिसर और क्षेत्रीय परिसरों में अलग-अलग एससी/एसटी प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

1. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के महानिदेशक को पुणे के फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की नवगठित सोसायटी का सदस्य मनोनीत किया गया है।

2. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) ने बिहार के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय एमजीसीयू के साथ शैक्षिक सहयोग बढ़ाने और आपसी हितों में समन्वयन के उद्देश्य से 02 मार्च, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसी दिन, आईआईएमसी के महानिदेशक और एमजीसीयू के कुलपति ने आईआईएमसी के उर्दू पत्रकारिता विभाग द्वारा विकसित और संपादित इन-हाउस उर्दू पत्रिका *''आईना''* का विमोचन किया।

3. आईआईएमसी ने पत्रकारिता के 175 वर्ष पूरे होने के अवसर पर असम में 15 मार्च, 2021 को गोष्ठी (सेमीनार) का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह थे।

4. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) ने वर्धा, महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ''मीडिया शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति'' क्रियान्वित करने के बारे में 22 मार्च, 2021 को परामर्श बैठक आयोजित की।

5. डॉ. भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को ''भारतीय संविधान के निर्माण में बाबासाहेब अंबेडकर की भूमिका'' विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया।

6. आईआईएमसी ने विश्व पत्रकारिता शिक्षा परिषद (डब्ल्यूजेईसी) और यूनेस्को के सहयोग से 10 और 11 अगस्त, 2021 को ''भारत में पत्रकारिता शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियां'' विषय पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विख्यात अतिथियों और जानेमाने वार्ताकारों ने अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए।

7. आईआईएमसी ने 17 अगस्त, 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। हिन्दुस्तान के एडिटर-इन-चीफ (प्रभारी संपादक) श्री शशि शेखर ने ''मीडिया शिक्षाः आगे का मार्ग'' विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान दिया।

8. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन 25 सितंबर, 2021 को जानेमाने विचारक, विद्वान, भविष्यदृष्टा और समन्वित मानवता दर्शन के प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर आईआईएमसी आए थे।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के 25 सितंबर, 2021 को आईआईएमसी आगमन पर उनका स्वागत करते हुए आईआईएमसी महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी

9. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक, शिक्षकों और स्टाफ के सदस्यों ने 26 अक्तूबर, 2021 को ''इंडिपेंडेंट इंडिया@75ः आत्मनिर्भर और एकजुट'' विषय पर निष्ठा की शपथ ली।

10. हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आईआईएमसी में 23 नवंबर, 2021 को ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली 3) की बैठक आयोजित की गई।

इसमें भारत सरकार के 64 से अधिक सदस्य कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना देश में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों का स्तर बनाए रखकर उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से संसद में पारित प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक अर्द्ध-न्यायिक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में 1979 में की गई थी।

संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित होने के कारण परिषद को अपने कोष का एक भाग संसद में विनियोग के बाद केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और समाचारपत्रों से लिए जाने वाले श्रेणीवार शुल्क और अन्य प्राप्तियों से भी परिषद को कोष मिलता है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परिषद का कुल स्वीकृत बजट दिया जा रहा है:

i) **बजट अनुमान:- 2021-22 : 2,000 लाख**

ii) **संशोधित अनुमान:- 2021-22 : 1,570 लाख**

परिषद के समक्ष शिकायतें

समीक्ष्य वर्ष में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक परिषद के पास **1174** शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस दौरान इनमें से **672** मामलों (पिछले वर्ष के लंबित मामलों सहित) का निपटारा किया गया।

स्वतः संज्ञान

परिषद् ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता के खतरे से जुड़े **17** मामलों में स्वतः संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021

राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर नई दिल्ली के कॉंस्टिट्यूशन क्लब में "मीडिया से कौन नहीं डरता?" विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया था। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिए गए।

राजभाषा

देश भर में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 सितंबर "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। परिषद के सचिवालय में 14.09.2021 से 28.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। परिषद सचिवालय में राजभाषा हिन्दी के बारे में पोस्टर लगाए गए।

नारा लेखन प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रेस परिषद के कर्मचारियों के साथ ही हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सराहनीय और बहुमूल्य योगदान देने के लिए *नोटिंग, ड्राफ्टिंग और टाइपिंग* जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

सतर्कता

भारतीय प्रेस परिषद का सचिव, कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। परिषद के सतर्कता ढांचे में उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) होते हैं, जो परिषद के सचिव (सीवीओ) और अध्यक्ष की सीधी निगरानी में काम करते हैं। इन्होंने सचिवालय में भ्रष्टाचार को रोकने/निपटने के लिए औचक और नियमित रूप से जांच की।

■■■

16 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन की अध्यक्षता करे माननीय न्यायाधीश श्री सी.के. प्रसाद।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में 14 अक्टूबर, 2021 को माईपार्किंग्स ऐप के लॉन्च के सिलसिले दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के बीच पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर।

5 प्रसारण क्षेत्र

एक अवलोकन

प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- 'सामग्री' और 'कैरिज सेवाएं'। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीति दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री, मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सेवाओं में मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ)/लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ), डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस/अनुमति देता है।

बीपी एंड एल अनुभाग के संबंध में प्रसारण क्षेत्र के तहत गतिविधियां और मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य

1. डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

डीटीएच एक एड्रेसेबल सिस्टम है और समूचे देश को कवर करता है। डीटीएच सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल केयू बैंड में बहुत उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से डिजिटली कम्प्रेस्ड, इन्क्रिप्टेड और बीम्ड होते हैं। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटिना स्थापित करके सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में पांच निजी डीटीएच ऑपरेटर हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवाएं फ्री टू एयर आधार पर भी प्रदान कर रहा है।

2. हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस)

हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) सेवा, उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रण है। एचआईटीएस ऑपरेटर टीवी प्रसारण को एक उपग्रह से अपलिंक करता है, जो एमएसओ/एलसीओ द्वारा डाउन-लिंक किया जाता है और एक केबल नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर में वितरित किया जाता है। इस प्रकार एचआईटीएस ऑपरेटर ग्राहकों को केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल की आपूर्ति करते हैं। वर्तमान में केवल एक एचआईटीएस ऑपरेटर है, जिसे इस मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश के माध्यम से ''भारत में मौजूदा हेडएंड-इन-द-स्काई प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए दिनांक 26.11.2009 के दिशानिर्देशों'' में संशोधन किया है। ये संशोधन हेडएंड-इन-द-स्काई ऑपरेटर को मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/हेडएंड-इन-द-स्काई ऑपरेटर के साथ हेडएंड-इन-द-स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देते हैं।

3. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा केबल ऑपरेटरों के अलावा पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क पर अनुमत उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण का एक अन्य तरीका है। आईपीटीवी प्रदाताओं को परिभाषित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक स्व-घोषणा करनी होगी।

4. खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 को भारत या विदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में सबसे बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों को फ्री-टू-एयर आधार पर पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

5. प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत नई प्रमुख गतिविधियां

क. मंत्रालय ने 15.02.2021 को सभी डीटीएच ऑपरेटरों को एक आदेश जारी किया जिसमें उन्हें उनके द्वारा लगाए गए सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

ख. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गजट अधिसूचना सं. एस.ओ. 3792 (ई) दिनांक 15.09.2021 के माध्यम से

मूल अधिसूचना एसओ. 2693 (ई) दिनांक 05.09.2013 में संशोधन किया है। इसके अनुसार लोकसभा टेलीविजन चैनल और राज्यसभा टेलीविजन चैनल का नाम बदलकर ''संसद टीवी-एसडी'' और ''संसद टीवी-एचडी'' कर दिया गया है।

ग. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गजट अधिसूचना सं. एस.ओ 4796 (ई) दिनांक 22.11.2021 के ज़रिए मूल अधिसूचना एस.ओ. 2693 (ई) दिनांक 05.09.2013 में संशोधन किया है। इसके अनुसार, 'संसद टीवी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारण अनिवार्य कर दिया है।

भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनल

भारत में पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को वर्ष 2000 में भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वृद्धि के साथ, भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई जिससे 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक हो गया। इन दिशानिर्देशों को दिसंबर 2011 में फिर से संशोधित किया गया। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

टेलीविजन चैनलों का विकास

मंत्रालय ने **31.03.2022 तक भारत में 898 चैनलों की अनुमति दी है।** मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों की केवल दो श्रेणियों अर्थात 'समाचार तथा समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' और 'गैर-समाचार तथा समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' को संचालित करने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त कुल चैनलों में से, **384 समाचार और 514 गैर-समाचार चैनल** हैं।

प्रसारण सेवा पोर्टल

प्रसारण सेवा पोर्टल शुरू में मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अंतर्गत प्रसारण विंग योजना के स्वचालन के तहत 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कंप्यूटरीकृत वेब आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन विकसित करना था ताकि विभिन्न प्रसारण लाइसेंसों/अनुमतियों/पंजीकरण आदि के लिए आवेदनों की तेज़ी से प्रोसेसिंग की जा सके। पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को शामिल किया गया था:

- निजी सैटेलाइट टीवी चैनल
- टेलीपोर्ट ऑपरेटर
- बहु-सेवा ऑपरेटर (केबल ऑपरेटर)
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)
- निजी एफएम चैनल

मंत्रालय द्वारा अनुमत टेलीविजन चैनलों की संख्या

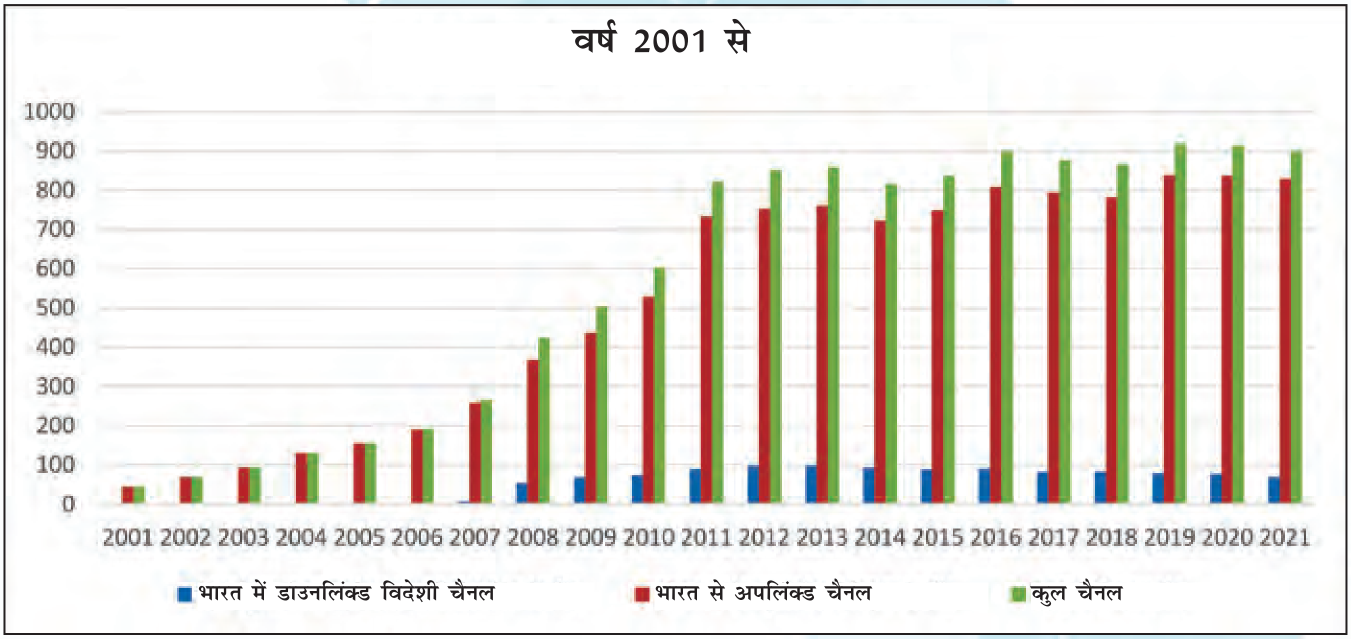

श्रेणीवार अनुमत चैनल

अनुमति प्राप्त समाचार व गैर-समाचार टीवी चैनल

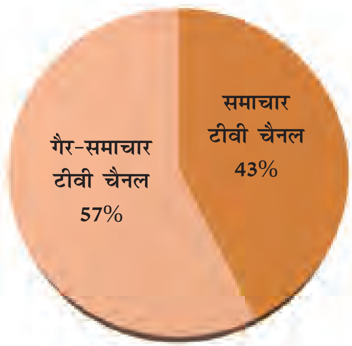

अब, प्रसारण सेवा पोर्टल को, अधिक सुविधाओं को शामिल करने तथा एजेंसियों के साथ सहज इंटरफेस की अनुमति देने के लिए मंत्रालय द्वारा नया रूप दिया गया है।

प्रसारण सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. नई अनुमति, नवीनीकरण, नाम/लोगो/टेलीपोर्ट/सैटेलाइट आदि में परिवर्तन के लिए आवेदनों की एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग सक्षम करना।

ii. भुगतान प्रणाली (भारत कोष), ई-ऑफिस, अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकरण।

iii. विश्लेषिकी, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

iv. एकीकृत हेल्पडेस्क, डाटा सेंटर

v. डीटीएच ऑपरेटरों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और डिजिटल मीडिया के लिए विस्तार

vi. उपयोगकर्ता पंजीकरण और उन्नयन

vii. शुल्क गणना तथा भुगतान, आवेदन पत्र और स्थिति ट्रैकिंग, पत्र/आदेश डाउनलोड करना, हितधारकों को अलर्ट (एसएमएस/ई-मेल)

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब वेबपोर्टल: **https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/** पर दाखिल ऑनलाइन आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/स्थिति देख सकती हैं। कंपनी से सूचना मांगने और कंपनी के प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। तदनुसार, अनुमोदन देने की समयावधि कम कर दी गई है।

टीवी चैनलों की सामग्री का विनियमन

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमों तथा 1994 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। वर्ष 2021 के दौरान, जहां कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन स्थापित किया गया था, मंत्रालय द्वारा सलाह, चेतावनी, अपोलॉजी स्क्रॉल के आदेश, ऑफ-एयर आदेश और डाउनलिंकिंग अनुमति को रद्द करने के आदेश के माध्यम से उचित कार्रवाई की गई थी।

केबल टीवी डिजिटीकरण की स्थिति

वर्तमान में प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए किसी भी चैनल (चैनलों) के कार्यक्रमों को केवल एक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से इन्क्रिप्टेड रूप में प्रेषित या पुनः प्रेषित करना अनिवार्य है। नवंबर 2021 तक मंत्रालय ने 1,749 एमएसओ पंजीकरण प्रदान किए हैं।

टीवी चैनलों को जारी की गई सामान्य सलाहः

क्रमांक	विषय	परामर्श की तिथि
1.	सांकेतिक भाषा में व्याख्या के साथ गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का प्रसारण।	25.01.2021
2.	चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(जे) तथा विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) का पालन करें और टीवी चैनलों पर अंधविश्वास तथा मिथ्या भय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण न करें और स्वयंभू प्रचारकों आदि द्वारा सभी समस्याओं के चमत्कारी समाधान की पेशकश करने वाले विज्ञापनों का प्रसारण न करें।	04.02.2021
3.	जांच/निरीक्षण आदि के तहत मामलों पर मीडिया कवरेज - जनहित याचिका (एसटी) संख्या 92252, 2020, आदि के मामले में बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2021 का अनुपालन।	05.03.2021
4.	देश के नागरिकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कोविड से बचाव के नियमों के पालन और पात्र आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए संदेशों का प्रसार।	06.04.2021
5.	मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए, कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड के उचित व्यवहार और टीकाकरण आदि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल हेल्पलाइन नंबर, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर और निमहंस हेल्पलाइन नंबर) के बारे में जागरूकता बढ़ाना	30.05.2021
6.	मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए, कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड से बचाव के नियमों के पालन और टीकाकरण आदि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल हेल्पलाइन नंबर, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर और निमहंस हेल्पलाइन नंबर- मनोवैज्ञानिक सहायता, आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन और माईजीओवी व्हाट्सऐप हेल्पलाइन)	03.06.2021
7.	कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए संदेशों और अन्य सामग्री का प्रसारण।	23.10.2021
8.	मीडिया द्वारा "आज़ादी का अमृत महोत्सव" लोगो का प्रदर्शन	03.11.2021

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण संरचना

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र मौजूद था। तथापि, शिकायत निवारण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 416 (ई) दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के रूप में संशोधित किया गया है, इस तरह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया है।

इन नियमों में प्रावधान है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन और अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित शिकायत या परिवेदना, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए, एक तीन-स्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) निम्नानुसार होगी:

(i) स्तर I - प्रसारक द्वारा स्व-विनियमन;

(ii) स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन; और

(iii) स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसरण में दिनांक 14.07.2021 के आदेश द्वारा एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है। अंतर-विभागीय समिति के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपर सचिव हैं, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेषज्ञों सहित ऐसे अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि, जैसा कि केंद्र सरकार तय करे शामिल होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 2008 में स्थापित मीडिया संगठन है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता दोनों के उल्लंघन करने वाले देश के भीतर प्रसारित होने वाले समाचार चैनलों की निगरानी करता है।

ईएमएमसी के पास वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर 900 टीवी चैनलों की सामग्री को प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचा है।

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आयोजित चुनावों के दौरान, ईएमएमसी सामग्री की निगरानी भी करता है और आयोग के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट देता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ईएमएमसी विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधी समाचारों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की निगरानी की। साथ ही मतदान के दिन और इससे पहले प्रमुख घटनाओं पर व्हाट्सऐप अलर्ट आयोग को भी भेजा गया था।

मीडिया निगरानी का महत्व

टेलीविजन चैनलों की पहुंच बहुत विशाल और असाधारण है। वे संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविजन कार्यक्रम विभिन्न आयु, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं, और इसलिए इनमें विविध प्रकृति की सामग्री शामिल होती है। टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही अवांछनीय सामग्री से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख लोकतंत्रों द्वारा पालन किया जाने वाला एक आदर्श है।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां और गतिविधियां:

- ईएमएमसी ने पत्र सूचना कार्यालय के सहयोग से अपने कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए एक टीकाकरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- ईएमएमसी ने 2021-22 में योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा, संविधान दिवस समारोह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, महिला दिवस समारोह आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक संगोष्ठी भी कार्यालय में आयोजित की गई।

राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय निगरानी समितियां

राज्य/जिला स्तर पर केबल टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों की राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए केबल टीवी अधिनियम और नियमों को लागू करने के वास्ते मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को एक आदेश जारी किया। बाद में, मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2008 को जिला और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। तत्पश्चात, राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन के संबंध में, पूर्व के सभी आदेशों को शामिल करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, राज्य सूचना सचिवों और सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए। समितियों को निजी एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in. पर उपलब्ध हैं।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो, रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना की अनुमति देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी। विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए, 2006 में नीति दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था, जिसमें आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों आदि जैसे समुदाय-आधारित संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई थी। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2016, 2017 और 2018 में नीति दिशानिर्देशों में और संशोधन किया गया। सामुदायिक रेडियो के लिए नीति दिशानिर्देश और वर्तमान में चल रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइटः www.mib.gov.in. पर देखी जा सकती है।

सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाजों को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सामुदायिक रेडियो समाज के हाशिए के वर्गों के लिए उनकी चिंताओं को आवाज देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसके अलावा, चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत जुड़ जाते हैं। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय गीतों को भावी पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड और संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा समुदाय को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है।

सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए, भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है।

आज की तारीख में, देश में 351 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हैं, जिनमें से 182 गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हैं, 148 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और 21 केवीके द्वारा संचालित हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 28 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को चालू किया गया है। चालू सामुदायिक रेडियो स्टेशन के परिचालन का ग्राफ नीचे दिया गया हैः

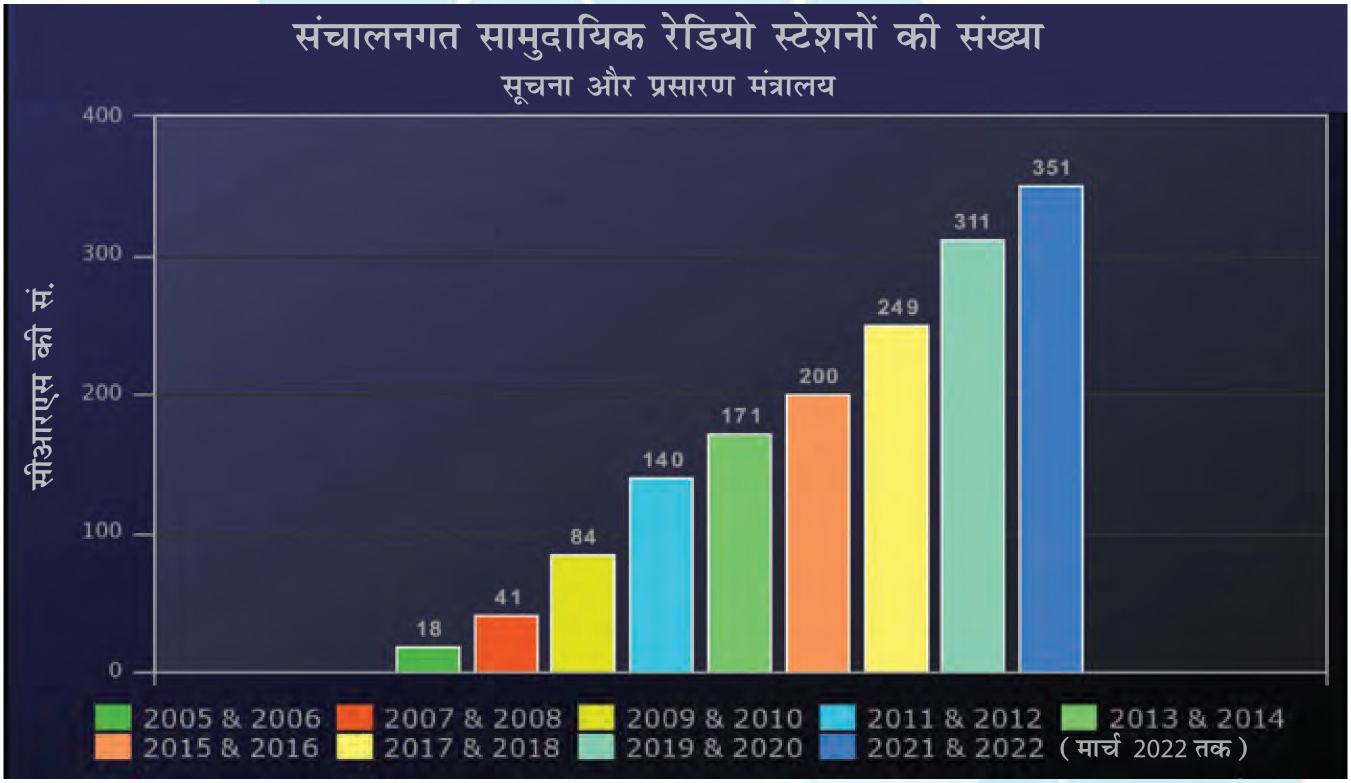

9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा:

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बीच नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की शुरुआत की थी जो हर साल सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रदान किए जाते थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए 4 श्रेणियों में 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की है, अर्थात् 1) विषयगत पुरस्कार; 2) सबसे अधिक अभिनव सामुदायिक कार्य पुरस्कार; 3) स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और 4) संधारणीयता मॉडल पुरस्कार।

एफएम रेडियो

एफएम रेडियो पूरे देश में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा पेश की जाने वाली विविधता का जनता स्वागत करती है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुंचने के लिए एक मंच के रूप में निजी एफएम रेडियो का उपयोग कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान निजी एफएम रेडियो स्टेशनों ने टीकाकरण और कोविड के उचित व्यवहार जैसे कि मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना और हाथों की स्वच्छता आदि के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। एफएम रेडियो पर उच्च जोखिम वाले जिलों में टीकाकरण को बढ़ावा देने वाले अभियान ने विशेष रूप से चिह्नित और आम जनता को संवेदनशील बनाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने में काफी मदद की है और इसके लिए वे हर तरफ से प्रशंसा के पात्र हैं।

निजी एफएम रेडियो चैनलों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह तथा कारगिल और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के भद्रवाह, कठुआ तथा पुंछ में संचालित किया गया है।

30.03.2022 तक, 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले देश भर के 113 शहरों में 386 एफएम रेडियो चैनल चालू थे।

सरकार को राजस्व उपार्जन

सरकार निजी प्रसारकों से गैर-वापसी के माध्यम से एक बार प्रवेशन शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क और टावर किराया तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार को कुल 144.78 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम

डीएएस डिवीजन को सौंपे गए कार्य:

- केबल टीवी क्षेत्र में डीएएस का कार्यान्वयन।
- केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को लागू करना।
- मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण और संबंधित मामले।
- केबल टीवी क्षेत्र, एमएसओ और एलसीओ से संबंधित विशिष्ट नीतिगत मुद्दे।
- केबल टीवी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के नियंत्रण, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रसार भारती और अधिकृत अधिकारियों के साथ समन्वय।

वर्ष 2021-2022 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

- वर्ष के दौरान 57 एमएसओ पंजीकृत किए गए। मार्च 2022 तक किए गए कुल 1,762 पंजीकरण हुए।
- केबल ऑपरेटरों द्वारा अधिसूचित अनिवार्य चैनलों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रसार भारती को देश भर में फैले अपने दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से केबल ऑपरेटरों की निगरानी का काम सौंपा गया है।
- एमएसओ द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इस बारे में दिशा-निर्देश डीएएस डिवीजन के आदेश दिनांक 29/12/2021 के जरिए जारी किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के इस तरह के बंटवारे से एमएसओ के लिए व्यवसाय स्थापित करने की लागत में काफी कमी आएगी, और इस तरह, यह कारोबार सुगमता पर सरकार के फोकस के साथ संरेखित होगा।
- डीएएस डिवीजन ने एमएसओ के पंजीकरण को संशोधित प्रसारण सेवा पोर्टल में स्थानांतरित कर दिया

है। तेजी से और पारदर्शी तरीके से आवेदनों पर काम करने के लिए पोर्टल और ई-ऑफिस के बीच सहज एकीकरण है। आवेदक, पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। आंतरिक रूप से, कमियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करके अधिकारियों के अपने विवेक के आधार पर निर्णय के अधिकार को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण बन सके।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश का लोक सेवा प्रसारक है। इसके दो घटक- आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन हैं। यह जनता को सूचित करने, शिक्षित करने तथा मनोरंजन और सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संचालित तथा व्यवस्थित करने एवं रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व के साथ 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया।

उद्देश्य

1. देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना।
2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
3. सूचना के निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह को प्रस्तुत करके नागरिकों को जनहित के सभी मामलों पर सूचित किए जाने के अधिकार की रक्षा करना।
4. शिक्षा और साक्षरता कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर विशेष ध्यान देना।
5. महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
6. विविध संस्कृतियों, खेलों और युवाओं से संबंधित मुद्दों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।
7. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मजदूर वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
8. अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकियों में विकास करना।

प्रसार भारती बोर्ड

यह निगम प्रसार भारती बोर्ड द्वारा शासित है। अध्यक्ष इस बोर्ड का प्रमुख होता है और इसमें तीन पूर्णकालिक सदस्य हैं – कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक)। बोर्ड में छह अंशकालिक सदस्य हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक इसके पदेन सदस्य हैं।

संगठनात्मक संरचना

प्रसार भारती बोर्ड शीर्ष स्तर पर कार्य करते हुए संगठन की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अनुसार जनादेश की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है। कार्यकारी सदस्य प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करता है। प्रसार भारती सचिवालय में कार्यरत विभिन्न विषयों से सम्बंधित अधिकारी कार्रवाई, संचालन, योजनाओं और नीति कार्यान्वयन के एकीकरण के साथ-साथ संगठन के बजट, लेखा और सामान्य वित्तीय मामलों की देखरेख में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) की सहायता करते हैं।

दो महानिदेशक आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख हैं। वे सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ मिलकर बोर्ड के नीति निर्देशों को कार्यान्वित करते हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक मामलों का प्रबंधन करते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में मुख्यतः चार अलग-अलग स्कंध हैं जिन पर विभिन्न गतिविधियों का दायित्व है। ये हैं : कार्यक्रम, अभियांत्रिकी, प्रशासन एवं वित्त और समाचार।

महत्वपूर्ण गतिविधियां और उपलब्धियां:

- **नए कोविड-19 जागरूकता बुलेटिन और कार्यक्रम:** अंग्रेजी और हिंदी में विशेष कोविड-19 बुलेटिन-30 मिनट प्रत्येक (सुबह, दोपहर और सायं) एनएसडी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जिसमे मुख्यालय के आकाशवाणी स्टूडियो में विशेषज्ञों और फील्ड में आरएनयू के समाचार संवाददाता शामिल हुए। हर घंटे प्रसारित होने वाले बुलेटिन की अवधि 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दी गई।
- **कोरोना जागरूकता शृंखला:** चिकित्सा विशेषज्ञों और आम जनता के बीच 50 मिनट की अवधि के 400 से अधिक लाइव फोन-इन का आयोजन कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मिथकों को दूर करने के लिए किया गया।
- **कोविड-19 टीकाकरण:** राष्ट्रीय कार्य बल के अध्यक्ष से कोविड-19 टीकाकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का चरण-2, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम - भारतीय नागरिकों को 'भारत में बने' टीके लगाया जाना।
- **इन्फो बाइट्स:** *'कोरोना- क्या कहते हैं विशेषज्ञ'*: सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञों के साउंड बाइट के साथ दैनिक इन्फोग्राफिक्स।
- **विशेष चर्चा कार्यक्रम:** जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 घंटे से अधिक अवधि के टॉक शो आयोजित किए गए।
- **विशेषज्ञ कहते हैं:** एम्स, दिल्ली के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन बुलेटिन में क्या करें और क्या न करें, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की आवश्यकता पर ऑडियो संदेश।
- **मिथकों का खंडन:** पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े कोविड-19 के मिथकों का शीर्ष चिकित्सकों के ऑडियो संदेशों द्वारा खंडन। समाचार वृत्तांत द्वारा गलत सूचना और फर्जी समाचारों का पर्दाफाश।
- **भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का कवरेज:** आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का व्यापक प्रचार किया। यह भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके नागरिकों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और कीर्तिगान के लिए है। आरएनयू अहमदाबाद ने अपने दैनिक बुलेटिनों में बड़े पैमाने पर दांडी मार्च पदयात्रा और संबंधित घटनाओं को कवर किया।

ग्लोबल आउटरीच

प्रसार भारती का ग्लोबल आउटरीच विंग अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां देखता है जैसे कि विदेश के लोक सेवा प्रसारकों/संगठनों के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर, विषय सामग्री लेन-देन के प्रसारण से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता आदि। यह प्रसार भारती के सभी कार्यक्षेत्रों में विदेशी प्रसारकों की आधिकारिक यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, विदेशी एमओयू भागीदारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संघों जैसे एबीयू, एआईबीडी आदि के लिए देश में/उप-क्षेत्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों का आयोजन करता है; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों में अपने अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

इस वर्ष के दौरान प्रसार भारती द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	देश	प्रसारक/संगठन	हस्ताक्षर करने की तिथि
1.	सेशेल्स	सेशेल्स ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एसबीसी)	17.08.2021
2.	जर्मनी (एमओयू)	डॉयचे वेले	09.11.2021

प्रसार भारती ने अपने ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर रूस, मालदीव, फिजी, मॉरीशस, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, फ्रांस, जापान, बांग्लादेश इत्यादि देशों के राजदूतों/प्रसारकों से अनेक मुलाकातें कीं।

अन्य उपलब्धियां

- श्री मयंक कुमार अग्रवाल, महानिदेशक, डीडी को अप्रैल 2021 में (एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग) डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- भारत (श्री रमन कुमार, निदेशक-जीओ) ने एआईबीडी (एशिया पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकॉस्टिंग) जनरल कांफ्रेंस ऐंड एसोसिएटेड मीटिंग 2021 के दौरान आयोजित

चुनाव में स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग टीम (एसपीटी) के उपाध्यक्ष का पद हासिल किया।

- श्री सुनील, अतिरिक्त महानिदेशक (ग्लोबल आउटरीच), दूरदर्शन, प्रसार भारती अतिरिक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अगुआई वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे जिन्होंने 28 सितंबर से – 3 अक्टूबर, 2021 तक चलने वाले ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव "पर्ल ऑफ द सिल्क रोड" में भाग लिया।

- **एबीयू रोबोकॉन 2021**

  एबीयू रोबोकॉन 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 18-08-2021 को आयोजित की गई जिसका आयोजन दूरदर्शन द्वारा आईआईटी दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का डीडी यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया।

  क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और भौतिक बैठकों से दूर रहने के लिए, एबीयू और एआईबीडी ने अप्रैल 2021 से कोविड-19 की अवधि के दौरान लगभग 50 ऑनलाइन वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया और प्रसार भारती ने इस अवसर का लाभ उठाया। लगभग 235 प्रतिभागियों ने विभिन्न वेबिनारों में उत्साहपूर्वक प्रसार भारती का प्रतिनिधित्व किया।

- दूरदर्शन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से 28.02.2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया-1 के प्रक्षेपण की लाइव फीड ब्राजील को प्रदान की।

- **एआईबीडी ने 2 और 3 जून, 2021 को लीडर्स वेब-शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जिसका विषय था** नए मानदंडों में मीडिया की भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करना जिसके लिए प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारीगणों को पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

- एबीयू ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन, 'एबीयू आरएआई डेज़' का 14 और 15 जून, 2021 को आयोजन किया। पूरे भारत से डीडीके/एआईआर स्टेशनों के 20 से अधिक अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

- एबीयू के एशिया विजन समाचार विभाग ने 9 जून, 2021 को एक ऑनलाइन प्रधान संपादक बैठक का आयोजन किया। श्री शशि शेखर वेम्पति, सीईओ, पीबी को 9 जून, 2021 को पहला सीईओ संवाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

- एबीयू की 29 और 30 जून, 2021 को आयोजित सबसे महत्वपूर्ण बैठक में से एक '111वीं प्रशासनिक परिषद बैठक (एसीएम)' में प्रसार भारती के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

- एमआईबी प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 जून, 2021 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड एक्सपो 2020 में "भारतीय मंडप के विषयगत और प्रदर्शनी स्थान के लिए क्यूरेटेड विषय सामग्री तैयार करने" पर एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रसार भारती के कई अधिकारियों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती ने नई दिल्ली में एबीयू के प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी करने का भी फैसला किया जैसे एबीयू रोबोकॉन 2022, एबीयू ग्लोबल न्यूज फोरम 2022, 59वीं एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022। इनके लिए आवश्यक अनुमोदन लेने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

प्रसारण विकास:

ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की "ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट" (बीआईएनडी) योजना प्रसार भारती को इसके प्रसारण बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन, विषय सामग्री विकास और सिविल कार्य से संबंधित खर्चों के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने का एकमात्र साधन है। बीआईएनडी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 316.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित कर 175.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बीआईएनडी योजना की मूल विशेषताएं/उद्देश्यों में हैं:

ट्रांसमीटरों, प्रसारण उपकरणों और स्टूडियो का आधुनिकीकरण (डिजिटलीकरण सहित) संवर्द्धन और प्रतिस्थापन, प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन। स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, एफएम विस्तार/प्रतिस्थापन, डीटीएच का विस्तार, संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को सशक्त करना, हाई डेफिनिशन टीवी

(एचडीटीवी), टीवी चैनलों का विस्तार, वैकल्पिक मंच पर प्रसारण, नागरिक बुनियादी अवसंरचना का विस्तार जिसमें कर्मचारियों के आवास और अन्य विविध कार्य शामिल हैं, ई-शासन, और विषय सामग्री विकास।

बीआईएनडी योजना सीमा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रसार भारती को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है:

(i) वामपंथी उग्रवाद और सामरिक महत्व के स्थानों के सीमावर्ती जिलों में एफएम स्टेशन।

(ii) दूरदर्शन डीटीएच सेट टॉप बॉक्सों (एसटीबी) का सामरिक महत्व के क्षेत्रों में वितरण: पहले चरण के तहत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,50,000 एसटीबी के वितरण को बीआईएनडी योजना 2017-21 के तहत अनुमोदित किया गया था। 2019-20 में 30,000 एसटीबी वितरित किए गए हैं। शेष 1.2 लाख एसटीबी की खरीद प्रक्रियाधीन है।

बीआईएनडी योजना की उपलब्धियां 2021-22:

दूरदर्शन:

I. भोपाल, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और अहमदाबाद में सभी उपकरणों के साथ अर्थ स्टेशनों को स्थापित, परीक्षित और क्रियान्वित किया गया और सेवाओं को नए सेटअप में स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही गोरखपुर में अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया।

II. हाई डेफिनिशन में स्टूडियो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए डीडी न्यूज और सीपीसी दिल्ली के मौजूदा 4 स्टूडियो का एचडी अपग्रेडेशन।

III. 112 एसडीटीवी चैनलों और 48 रेडियो चैनलों की क्षमता बढ़ाने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने और स्थापित करने का काम पूरा कर लिया गया है जिससे अब 128 एसडीटीवी चैनल (एमपीईजी-2 में 48 और एमपीईजी-4 में 80) और 48 रेडियो चैनल हो गए हैं।

IV. लद्दाख में कारगिल के हिमबोटिंग ला (डीडी कशीर) में 10 किलोवाट (1+1) डिजिटल रेडी एचपीटी चालू किया गया है।

V. 5 डीडी उत्पादन/ट्रांसमिशन केंद्रों का उन्नयन/एचडी में स्थानांतरण किया गया।

VI. 6 डीडी सैटेलाइट अपलिंक स्टेशनों का उन्नयन/जोड़ा गया।

ऑल इंडिया रेडियो:

I. 10 किलोवाट क्षमता के एफएम ट्रांसमीटर (रिले) इटावा, गडानिया, नानपारा और नरकटियागंज में कमीशन किए गए हैं।

II. अमोरा में 5 किलोवाट इएम ट्रांसमीटर (रिले) चालू किया गया है।

III. तामेंगलोंग, चांगलांग, खोंसा, कोलासिब, चंफाई, अल्मोड़ा और जुन्हेबोटो में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले) चालू किए गए हैं।

IV. गोड्डा में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले) चालू किया गया है।

V. 16 स्थानों पर आकाशवाणी स्टूडियो का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

VI. 30 स्थानों पर सर्वर और रेडियो स्टूडियो ऑटोमेशन का एसआईटीसी।

BECIL
बेसिल

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

1. बेसिल का संक्षिप्त इतिहास

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल), एक मिनी रत्न केंद्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है। इसे 24 मार्च, 1995 को कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्कालीन कंपनी अधिनियम, 1956) के तहत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव तथा

संयुक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में है। कंपनी को शुरू में परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी सोल्यूशन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग, प्रसारण सुविधाओं की स्थापना जैसे की सामग्री निर्माण सुविधाएं, टेरेस्ट्रियल, जैसे भारत तथा विदेशों में उपग्रह और केबल प्रसारण शामिल हैं। इसकी गतिविधियों में इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, संचालन तथा रखरखाव, जनशक्ति नियोजन, एएमसी और महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के लिए कुल टर्नकी परियोजना प्रदान करना शामिल हैं।

बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है।

प्रमुख परियोजनाएं/गतिविधियां

1. विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाना

विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को अपने काम से अधिक परिचित कराने के लिए बेसिल की सेवाएं ली हैं। बेसिल से ये सेवाएं लेने वाले प्रमुख संगठनों में शामिल हैं- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और सूचना तथा जन-संपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार)

2. निगरानी और विश्लेषण सेवाएं

बेसिल अपने ग्राहकों को निगरानी और विश्लेषण सेवाएं प्रदान करता है। बेसिल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना और सभी निजी एफएम ट्रांसमिशन साइट पर लॉगर सिस्टम की तैनाती के बाद टीवी कन्टेंट की निगरानी शुरू की। निगरानी सेवाएं शुरू करने के बाद बेसिल ने मूल्यवर्धन सेवा के रूप में मूल्यांकन और विश्लेषण सेवाओं में विस्तार किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मीडिया अभियानों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. सीसीटीवी निगरानी, पहुंच नियंत्रण प्रणालियां

बेसिल ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जैसी रणनीतिक परियोजनाओं के क्षेत्र में विस्तार किया है। बेसिल ने विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिए सीसीटीवी नियोजन और स्थापन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के लिए परिवहन भवन में हाई एण्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया है।

4. पेशेवर श्रव्य-दृश्य सेवाओं के लिए परामर्श सेवाएं

बेसिल विशिष्ट श्रव्य-दृश्य समाधानों के लिए प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और शुरुआत के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही बेसिल इन सेवाओं का संचालन और साइट पर व्यापक सालाना रख-रखाव सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है।

5. टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटरों के डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण विनियमों के अनुसार ऑडिट: बेसिल दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (ऐड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 के अंतर्गत अपेक्षित डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम का, प्रसारकों और डीपीओ की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित रूप से ऑडिट करता है।

माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्राइब्यूनल के विशिष्ट निर्देशों के अनुरूप ऑडिट: बेसिल, माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्राइब्यूनल के विशिष्ट निर्देशों के अनुरूप ऑडिट करता है।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया ईकाइयों के लिए कार्यान्वित परियोजनाएं

केबल टीवी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना: इसके कार्यक्षेत्र में शामिल हैं-केंद्रीय इकाई की स्थापना, ऑनलाइन केबल टीवी निगरानी प्रणाली का विकास, एसटीबी सीडिंग की निगरानी के लिए एमआईएस एप्लीकेशन का रखरखाव, केबल टीवी उद्योग के सभी हितधारकों को नवीनतम और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित वेबसाइट का रख-रखाव।

ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का पुनर्निर्माण: मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के उन्नयन और पुनर्निर्माण के लिए बेसिल की सेवाएं ली हैं।

मंत्रालय की वेबसाइट का उन्नयन: मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का उन्नयन किया जा रहा है।

आरएनआई का आटोमेशन: इस कार्यक्षेत्र में शामिल हैं- भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को वेब एनेबल्ड ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए कार्यबल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना। परियोजना के हिस्से के रूप में ऑनलाइन शीर्षक वेरिफिकेशन और ई-फाइलिंग ऐप्लीकेशन का विकास और कार्यान्वयन किया गया है।

डीपीडी के सीआईएम सिस्टम का वार्षिक रख-रखाव: बेसिल अपने स्वयं के कर्मियों की सहायता से प्रकाशन विभाग के कम्प्यूटरीकृत इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का रखरखाव कर रहा है।

52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का वर्चुअल आयोजन: 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया था। दर्शकों के लिए वर्चुअल प्लेटफार्म पर इसके आयोजन के लिए बेसिल ने फ़िल्म महोत्सव निदेशालय का सहयोग किया।

बीओसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और स्वचालन कार्य: बेसिल, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्युनिकेशन को दैनिक गतिविधियों के लिए कम्प्यूटर के इस्तेमाल में परिपक्व बनाकर उसकी कामकाज प्रक्रिया के लिए मानक टीयर 1-2 लागू कर रहा है। इस परियोजना में बीओसी के मौजूदा सिस्टम से डाटा का स्थानांतरण शामिल है।

एफएम प्रसारण के लिए परामर्श और टर्नकी सोल्यूशन: बेसिल, स्थापना और सामग्री निगरानी के लिए भारत में निजी एफएम प्रसारण सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बेसिल, निजी एफएम प्रसारकों के विभिन्न एफएम ट्रांसमिशन साइट के लिए सिस्टम समाकलक के रूप में कार्य कर रहा है।

7. अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पोर्टफोलियो और सेवाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए बेसिल ने सूचना प्रौद्योगिकी में *भारत-सीरिया नेक्स्ट जेनरेशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस* परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें आपूर्ति, स्थापना, संचालन और आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऑन साइट वारंटी सहायता शामिल है।

8. विभिन्न विभागों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा

बेसिल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जैसे विभिन्न विभागों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जीती हैं। जैसे विभागों ने सीबीटी के माध्यम से शिक्षुओं के चयन के लिए बेसिल की सेवाएं ली हैं जबकि जैसे विभागों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से भर्ती का काम बेसिल को दिया है।

9. ई-क्लासरूम परियोजनाएं

बेसिल ने आईआईएमसी (दिल्ली), नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेज (निमहांस-बेंगलुरु) जैसे अपने विभिन्न ग्राहकों के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग और ई-क्लासरूम के लिए व्यापक परामर्श और परियोजना प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए परियोजना कार्यान्वित की है।

10. सामुदायिक रेडियो स्टेशन परियोजनाएं

बेसिल, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए एफएम ट्रांसमीटरों का विनिर्माण करता है और इन स्टेशनों के नियोजन तथा स्थापना के लिए परामर्श और टर्नकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके कुछ ग्राहकों में सोलापुर विश्वविद्यालय और जिपमेर-पांडिचेरी शामिल हैं।

11. जनशक्ति नियुक्ति पश्चात कर्मचारियों का प्रबंधन

बेसिल देश भर में विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय महत्व की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी सरकारी संगठन है। विभिन्न श्रेणियों जैसे पेशेवर, तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, अत्यधिक बेसिल लगभग 30 सरकारी संगठनों को जनशक्ति उपलब्ध करा रहा है। इनमें राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत का निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल हैं।

वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2019-20 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

(राशि लाख में)

	विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष
		2020-21	2019-20
क	**संचालन का परिणाम**		
	परिचालनों से आय	55,282.33	34,707.48
	अन्य आय	303.17	354.89
	पूर्व अवधि आय	4.22	14.12
	वर्ष के दौरान कुल कारोबार	**55,589.72**	**35,076.48**
	व्यय	54,427.43	34,491.69
	संचालन लाभ/(हानि)	**1,162.29**	**584.79**
	वित्तीय लागत	909.23	780.03
	अवमूल्यन और परिशोधन	152.43	157.98
	पूर्व अवधि समायोजन	50.16	22.93
	अतिरिक्त साधारण और असाधारण वस्तुएं	-	85.19
	कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	**50.47**	**(461.34)**
	कर व्यय	(204.25)	20.07
	लाभ/(हानि) कर व्यय के बाद	**254.72**	**(481.41)**
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में अंतरण आय/(हानि) प्रति शेयर (रु.)	-	-
	आय/(हानि) प्रति शेयर (रु.)	**187**	**(353)**
ख	**फंड के स्रोत**		
	जारी, अभिदान और चुकता पूंजी	136.50	136.50
	रिजर्व और अधिशेष	880.55	625.83
	गैर-मौजूदा देनदारियां	864.11	819.39
	वर्तमान देनदारियां	33,076.05	35,954.14
	कुल	**34,957.21**	**37,535.86**
	निधियों का उपयोग		
	अचल सम्पत्ति	1,048.77	1,100.07
	वर्तमान संपत्ति	32,949.02	35,694.81
	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	915.97	711.71
	लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	-	-
	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	43.36	29.26
	कुल	**34,957.12**	**37,535.86**
ग	**अन्य सूचना**		
	अधिकृत पूंजी	**250.00**	**250.00**
	नियोजित पूंजी	1,017.05	762.33
	कुल मूल्य	101.08	50.61

शेयर पूंजी

बेसिल को 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था। चुकता इक्विटी वर्ष 1995-96 में 25 लाख रुपये से बढ़कर 136.50 लाख रुपये हो गई है। वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बेसिल को भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के संचालन से 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने रिपोर्ट किए गए वर्ष में 552.82 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है, जो कंपनी के निगमन के बाद से सबसे अधिक कारोबार है। कंपनी द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद, रिपोर्ट किए गए वर्ष में शुद्ध लाभ पिछले वर्ष 2019-20 में 4.81 करोड़ रु. के शुद्ध नुकसान की तुलना में 2.55 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का शुद्ध मूल्य बढ़कर 1.01 करोड़ रुपये हो गया।

भविष्य की व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी ने आने वाले वर्षों में लाभ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविध कार्य किए हैं:

सामरिक परियोजनाएं

i) **ड्रोन-साइबर और एयरोस्पेस सुरक्षा:** बेसिल ड्रोन और काउंटर ड्रोन में टर्नकी परियोजनाएं चलाता है, और संगठनों के आधुनिकीकरण तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ii) **बेसिल डिजिटल फोरेंसिक लैब**

नवीनतम उपकरणों और सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ ही बेसिल में डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। विभिन्न संस्थानों में विशेषज्ञता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और विभिन्न फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में काम करने का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक अधिकारियों को प्रयोगशाला में नियुक्त किया गया है।

प्रयोगशाला अब कंप्यूटर फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, आईओएस और एंड्रॉइड विश्लेषण, फोरेंसिक डेटा रिकवरी, ईमेल फोरेंसिक, क्लाउड तथा आईओटी फोरेंसिक, सीसीटीवी फोरेंसिक और ड्रोन फोरेंसिक के लिए तैयार है।

डिजिटल फोरेंसिक लैब के माध्यम से बेसिल, राष्ट्रीय डिजिटल फोरेंसिक क्षमता के निर्माण में सहायता कर रहा है और जांच तथा अभियोजन को बेहतर सहायता देने के लिए साक्ष्य प्रबंधन प्रक्रियाओं का विकास कर रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति

कंपनी, आरक्षण नीतियों पर सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करती है। तदनुसार, कंपनी में भर्ती और पदोन्नति करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों का ध्यान रखा गया है।

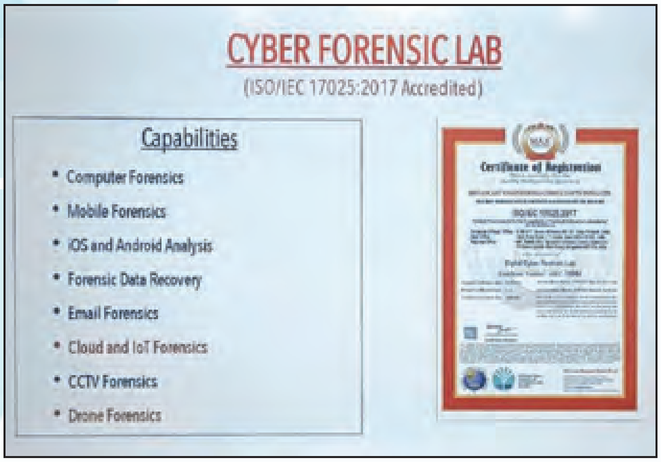

आरटीआई सूचना

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रश्नों का समय पर उत्तर देने के वास्ते उचित कार्रवाई की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किए गए हैं और सूचना के समय के अनुपालन तथा प्रसार के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है।

सतर्कता गतिविधियां

बेसिल में सतर्कता अनुभाग, बेसिल में अनुपालन के लिए निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने के उपायों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार नियमित रूप से मानदंड और दिशानिर्देश जारी करता रहा है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नियमित रूप से आवधिक विवरणियां प्रस्तुत की जा रही हैं और पूछताछ पर उचित तथा तुरंत कार्रवाई की जाती है, इसके अलावा, समय-समय पर औचक जांच/निरीक्षण किए जाते हैं।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत द्वारा इंडियन फ़िल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार अभिनेत्री और मथुरा से सांसद, श्रीमती हेमा मालिनी को 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव उद्‌घाटन पर प्रदान किया गया।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 20 नवंबर, 2021 को पणजी, गोवा में भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईआईएफएफ-2021) के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

6 फ़िल्म क्षेत्र

अवलोकन

फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित सभी मामले अर्थात निर्माण, प्रसार और फ़िल्मी सामग्री के संरक्षण को बढ़ावा देने सहित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन, अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह, फ़िल्मों का प्रमाणन, फ़िल्म की शूटिंग की अनुमति, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, फ़िल्म प्रभाग द्वारा संभाले जाते हैं।

इस संबंध में मंत्रालय का दृष्टिकोण हैः मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के निरंतर विकास और मूल्य आधारित स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा प्रदान करने और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से सूचना का प्रसार करने के लिए सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना।

फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय के मिशन का उद्देश्य–

- सभी उम्र के लोगों के लिए मूल्य आधारित स्वस्थ मनोरंजन के लिए सिनेमा को बढ़ावा देना और इसके लिए नीति बनाना।
- फ़िल्म, वीडियो और ऑडियो संसाधनों को पुनर्स्थापित, डिजिटलीकृत तथा संरक्षित करना और अधिक से अधिक लोगों तक उनकी पहुंच को बढ़ाना।
- फ़िल्म समारोहों के माध्यम से अच्छे सिनेमा और फ़िल्म संस्कृति को बढ़ावा देना।

फ़िल्म प्रभाग

फ़िल्म प्रभाग की स्थापना, राष्ट्र का इतिहास, उसकी यात्रा एवं सर्वांगीण विकास की कहानी सिनेमा के माध्यम से व्यक्त करने के उद्देश्य से 1948 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। फ़िल्म प्रभाग की कहानी आज़ादी के बाद के महत्वपूर्ण वर्षों के साथ ही चलती रही है और पिछले 73 वर्षों से फ़िल्म प्रभाग राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में आम जनता की सहभागिता दिखाकर उसे प्रेरित करता रहा है।

प्रभाग का लक्ष्य एवं उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शिक्षित तथा प्रेरित करना और देश की छवि तथा धरोहर को भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना है। फ़िल्म प्रभाग का लक्ष्य वृत्तचित्र आंदोलन का विकास करना है, जिसका देश के लिए सूचना, संचार एवं सुदूर क्षेत्रों में बहुत महत्व है। यह सिनेमाघरों द्वारा प्रदर्शन के लिए सामग्री वितरित करता है, देश भर में फ़िल्म सोसायटियों, स्वैच्छिक संगठनों की मदद से फ़िल्म महोत्सवों में विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था करता है, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू फ़िल्म महोत्सवों में हिस्सा लेता है, टेलीविजन चैनलों तथा विदेश मंत्रालय को फ़िल्में देता है, डिजिटल प्रारूप में फ़िल्म सामग्री की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मार्केटिंग करता है और भारत एवं विदेश में प्रोडक्शन हाउसों की अभिलेखीय अर्थात् पुराने फुटेज की आवश्यकता पूरी करता है।

1. फ़िल्म प्रभाग के प्रखंड

फ़िल्म प्रभाग को तीन प्रखंडों में बांटा गया हैः

(क) निर्माण

(ख) वितरण एवं संपर्क (आउटरीच)

(ग) प्रशासन और वित्त

(क) निर्माण प्रखंडः

इस विभाग पर सार्वजनिक सूचना, शिक्षा और प्रेरणा के साथ-साथ निर्देशात्मक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए वृत्तचित्रों, एनीमेशन फ़िल्मों और पीएसए फ़िल्मों के निर्माण का

जिम्मा है। फ़िल्म प्रभाग ने अब तक 9,000 से अधिक फ़िल्मों का निर्माण किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों और मुद्दों पर वृत्तचित्र, फीचर, लघु और एनीमेशन फ़िल्में, पीएसए शॉर्ट्स और समाचार कवरेज शामिल हैं।

विभाग ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक 27 वृत्तचित्र, एनीमेशन और पीएसए फ़िल्मों का निर्माण घरेलू बुनियादी संरचना के साथ-साथ बाहरी निर्माताओं के माध्यम से विभिन्न विषयों और अवधि में पूरा किया।

फ़िल्म प्रभाग ने खोजकर्ताओं, विद्वानों और जनता को असीम अभिलेखीय महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता से पहले और बाद में निर्मित समाचार रीलों और वृत्तचित्र फ़िल्मों के अपने संग्रह को संरक्षित किया है जिसमें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्राएं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण शामिल हैं।

2021-22 में उल्लेखनीय पहलें

1. **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)** विषय पर **महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय** द्वारा प्रायोजित 05 पीएसए फ़िल्में निर्माणाधीन हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित तथा प्रसारित की जा रही हैं।

2. **पंढरी के रंग, गुरु बानी, अरिबम श्याम शर्मा, क्रिएटिव मैन ऑफ पिपलांत्री, टी एन कृष्णन** जैसे उल्लेखनीय विषयों पर फ़िल्में पूरी हो चुकी हैं।

3. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** और **दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता रजनीकांत** पर भी फ़िल्में पूरी हो चुकी हैं।

4. **''आज़ादी का अमृत महोत्सव''** के अंतर्गत फ़िल्म प्रभाग की टीम द्वारा फ़िल्म प्रभाग अभिलेखागार और अन्य स्रोतों से प्राप्त फुटेज के आधार पर 5 पीएसए फ़िल्मों का निर्माण किया गया।

5. **संविधान दिवस, देविका रानी, वसीम बरेलवी, योग, श्रुति महापात्रा, नारी शक्ति पुरस्कार विजेता- श्रीमती रवीना उमादेवी नागराज, इसरो** जैसे उल्लेखनीय विषयों पर फ़िल्में निर्माणाधीन हैं।

6. **''भारतीय स्वतंत्रता का 75वां वर्ष''** विषय पर फ़िल्म प्रभाग की इन-हाउस निर्देशन और गैर-निर्देशन इकाई को सौंपे गए 06 वृत्तचित्र निर्माणाधीन हैं।

7. बाहरी फ़िल्म निर्माताओं को सौंपी गई **''नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती''** विषय पर 02 वृत्तचित्र फ़िल्में निर्माणाधीन हैं।

8. **''आपदा प्रबंधन''** विषय पर 02 वृत्तचित्र फ़िल्म निर्माणाधीन हैं।

उत्पादन और आउटरीच पहलें -इंडिया@75

इन विषयों पर 24 वृत्तचित्र फिल्में बाहरी फिल्म निर्माताओं को सौंपी गई हैं जिनमें शामिल हैं 1) भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के साथ गत वर्षों में 'विकास, शासन, प्रौद्योगिकी, सुधार, प्रगति और नीति' के प्रदर्शन के लिए अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं और 2) आम पुरुषों और महिलाओं की सफलता की कहानियां जिन्होंने समाज के लिए असाधारण योगदान दिया और जिन्हें पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

भारत के समृद्ध सिनेमाई इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ-साथ सिनेमा के विकास में उजागर भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास को संजोये रखने के लिए मुंबई में फ़िल्म प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआइसी) स्थापित किया गया है। संग्रहालय दर्शकों को विजुअल्स और ग्राफिक्स, फ़िल्म क्लिप्स, कलाकृतियों, प्रचार सामग्री, इंटरैक्टिव प्रदर्शनों और कई अन्य माध्यमों द्वारा कहानी सुनाने के ढंग से भारतीय सिनेमा की एक सदी से अधिक की रोचक यात्रा पर ले जाता है। इसके अलावा फ़िल्म संग्रहालय के हिस्से के रूप में गांधी और सिनेमा विषय पर एक विशेष गैलरी स्थापित की गई है।

कोविड-19 महामारी के कारण 17 मार्च, 2020 से संग्रहालय को बंद कर दिया गया था और 22 अक्टूबर, 2021 से जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। **मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एनएमआईसी के संचालन और रखरखाव को 31 दिसंबर, 2021 से राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को स्थानांतरित कर दिया गया है।**

(ख) वितरण और लोक संचार प्रखंडः

फ़िल्म प्रभाग के छह वितरण शाखा कार्यालय हैं जो कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित हैं तथा मुंबई और नई दिल्ली में प्रदर्शन प्रकोष्ठ हैं। शाखा कार्यालय और प्रदर्शक प्रकोष्ठ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सिनेमाघरों द्वारा पीएसए फ़िल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की निगरानी करते हैं, फ़िल्म समारोहों और विशेष प्रदर्शन आयोजित करते हैं और फ़िल्म प्रभाग की मार्केटिंग करते हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों को फ़िल्म डिवीजन मुख्यालय, मुंबई में डीएचओ द्वारा नियंत्रित और मॉनीटर किया जाता है।

आउटरीच गतिविधियाँ

क. फ़िल्म समारोहों में पुरस्कृत/चयनित/प्रविष्ट/प्रदर्शित फ़िल्में

1. 67वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार - 2020

(i) एलीफैन्ट्स डू रिमेम्बर- सर्वश्रेष्ठ जीवनी फ़िल्म - रजत कमल

(ii) चरण अत्वा - एसेंस ऑफ़ नोमैड - सर्वश्रेष्ठ नृवंशविज्ञान फ़िल्म - रजत कमल

2. चयनित फ़िल्में: 18 फ़िल्में/8 उत्सव

क्रमांक	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की संख्या
i)	भारतीय पैनोरमा-52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2021	2
ii)	नोर्ग्स इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फ़िल्म फेस्टिवल (एनआईआईएफ) ईरान	1
iii)	7वां जेबेक फ्यूचर फ़िल्म फेस्टिवल, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कनाडा	1
iv)	फिल्लम इंटरनेशनल स्टोरिकल एंड शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल, मैसाचुसेट्स, यूएसए	1
v)	फखशाफ़्टराट (एफएसआर) साउथ एशिया इंस्टिच्युट, हेडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा दक्षिण एशिया फ़िल्म महोत्सव की झलक	1
vi)	नीला अंतरराष्ट्रीय लोकगीत फ़िल्म महोत्सव 2021	8
vii)	शिमला का 7वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफएस) 2021	3
viii)	मदुरै अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म महोत्सव	1

3. फ़िल्म प्रविष्टि : 64 फ़िल्में/14 महोत्सव

क्रमांक	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की संख्या
i)	एशियन टेलीविजन पुरस्कार, सिंगापुर	1
ii)	यामागाटा वृत्तचित्र फ़िल्म महोत्सव, टोक्यो जापान	1
iii)	तिराना अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, अल्बानिया	1
iv)	एथेंस एथनोग्राफिक फ़िल्म फेस्टिवल-एथनोफेस्ट, ग्रीस	1
v)	इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुंबई द्वारा आयोजित उत्कृष्टता के लिए 13वां आईडीपीए पुरस्कार	6
vi)	भारतीय पैनोरमा-2021, 52वां आईएफएफआई, गोवा	3
vii)	केरल का 13वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म महोत्सव (आईडीएसएफएफके)	26
viii)	27वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, कोलकाता	6

क्रमांक	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की संख्या
ix)	एनएफडीसी फ़िल्म बाजार, 52वां आईएफएफआई, गोवा-2021	5
x)	शिमला का 7वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 21	3
xi)	नीला अंतरराष्ट्रीय लोकगीत फ़िल्म महोत्सव 2021	4
xii)	चेन्नई अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म महोत्सव-2022	2
xiii)	5वां अंतरराष्ट्रीय लोकगीत फ़िल्म महोत्सव-आईएफएफएफ-2022	2
xiv)	चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फ़िल्म महोत्सव, भोपाल	3

4. प्रदर्शित फ़िल्में: 7 फ़िल्में/3 महोत्सव

क्रमांक	फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की संख्या
i)	पंचजन्यम अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, केरल	1
ii)	सुचित्रा फ़िल्म सोसायटी द्वारा पर्यावरण फ़िल्म महोत्सव, बेंगलुरु	2
iii)	केरल का 13वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म महोत्सव (आईडीएसएफएफके)	4

(ख) ऑनलाइन महोत्सव/विशेष प्रदर्शन

क्रमांक	फ़िल्म महोत्सव का नाम	अवधि	ऑनलाइन दर्शकों की संख्या
i)	जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को उनकी 102वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि	13.04.2021	1,480
ii)	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि	14.04.2021	1,611
iii)	भारतीय सिनेमा के पितामह दादासाहेब फाल्के की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि	19.04.2021 – 30.04.2021	4,577
iv)	विश्व धरोहर दिवस	18.04.2021 – 19.04.2021	23,354
v)	सत्यजित रे का जन्म शताब्दी महोत्सव	02.05.2021	12,661
vi)	महान समाज सुधारक और "भारतीय पुनर्जागरण के जनक" राजा राम मोहन राय को उनकी 249वीं जयंती पर श्रद्धांजलि	22.5.2021	2,259
vii)	महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि	22.6.2021	1,605
viii)	7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया	21.6.2021	495
ix)	सू.प्र. मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह मनाने और आज़ाद हिंद दिवस को स्मरण करने के अवसर पर	21.10.2021	973
x)	जनजातीय गौरव दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में	15.11.2021	1,651
xi)	आज़ादी का अमृत महोत्सव	17.11.2021	50
xii)	स्वच्छता पखवाड़ा		

विशेष ऑनलाइन प्रदर्शन:

क्रम संख्या	उपलक्ष्य	अवधि	ऑनलाइन दर्शकों की संख्या
1.	विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस	28.7.2021	485
2.	विश्व फोटोग्राफी दिवस	19.8.2021	1,814
3.	अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस	10.11.2021	2,484
4.	जनजातीय गौरव दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव	15.11.2021	1,651

(ग) प्रशासन एवं वित्त प्रखंड:

प्रशासन प्रखंड में वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, फैक्ट्री प्रबंधन और सामान्य प्रशासन शामिल हैं।

नागरिक चार्टर

फ़िल्म प्रभाग ने पहले ही नागरिक चार्टर तैयार कर लिया है और यह http://www.filmsdivision.org पर उपलब्ध है। चार्टर के उचित कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी को मनोनीत किया गया है। इसमें नए पहलुओं को शामिल करके नागरिक चार्टर को अद्यतन किया जा रहा है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र:

सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, जन शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। प्रशासन निदेशक को फ़िल्म प्रभाग के लिए लोक शिकायत अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। लोक शिकायतों के निपटारे का विवरण रखा जाता है। जनता और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए रजिस्टर रखा जाता है और लोक शिकायतों के निपटारे की अपेक्षित रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती है।

01/04/2021 से 14/12/2021 के दौरान फ़िल्म प्रभाग में चलायी गई सतर्कता गतिविधियां

प्रभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों सहायक की देखरेख के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसमें एक अधीक्षक, एक सहायक और एक अवर श्रेणी लिपिक होता है जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासन निदेशक (सतर्कता अधिकारी) की देखरेख में काम करते हैं।

निगरानी रखने के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है: चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और कोलकाता में स्थित वितरण शाखा कार्यालय।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, फ़िल्म प्रभाग ने प्रशासन निदेशक को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में और एक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामले प्रधान कार्यालय में नोडल अनुभाग यानी इस्टेब्लिशमेंट-I अनुभाग द्वारा निपटाये जाते हैं।

सोशल मीडिया पर फ़िल्म प्रभाग

फ़िल्म प्रभाग अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल और फेसबुक एकाउंट्स के माध्यम से कोविड-19 महामारी #Indiafightscorona के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय है और इसने अप्रैल 2021 से नवम्बर 2021 तक @narendramodi, @pmoindia, @ianuragthakur, @murugan_mos, @mohfw_india और अन्य **ट्विटर हैंडल्स के कुल 4,886 ट्वीट्स को रीट्वीट** किया।

बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)

कोविड-19 के कारण, जब पूरे देश में नियमित नाट्य और नॉन-थियेट्रिकल स्क्रीनिंग्स बच्चों के लिए प्रतिबंधित थीं, तब सीएफएसआई ने बच्चों को सुरक्षित और मनोरंजन में तल्लीन रखने के लिए ऑनलाइन शो आयोजित करना शुरू किया। ये ऑनलाइन शो विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध स्रोतों द्वारा और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों के माध्यम से अनाथालय, रिमांड और शेल्टर होम्स में रहने वाले बच्चों और गैर सरकारी संगठनों के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आयोजित किए गए।

1 अप्रैल, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक सीएफएसआई ने 1,257 शो सफलतापूर्वक आयोजित किए जिनका लाभ 36,492 दर्शकों ने उठाया।

वर्ष 2021-22 के दौरान बाल चित्र समिति ने 7 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में अपनी फ़िल्में भेजीं।

वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता

आज़ादी का अमृत महोत्सव को अनूठे ढंग से मनाने के लिए **सीएफएसआई** ने **भारत के मेक्सिको स्थित दूतावास** और **गुरुदेव टैगोर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र** के साथ मिलकर 2 अक्टूबर, 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाने के लिए मेक्सिको में स्कूली बच्चों के लिए महात्मा गांधी पर एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी ताकि "लिटिल डायरेक्टर्स" के रूप में उनकी रचनात्मकता उजागर की जा सके।

इस कार्यक्रम का नाम था **'वॉलपेपरिंग मैक्सिको विद गांधीज़ फिलॉसफी एंड थॉट्स'** मेक्सिकी बच्चों से कुल 50 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

जिला बाल संरक्षण इकाइयां

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन स्क्रीनिंग गतिविधि का विस्तार करने के लिए, सीएफएसआई ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले एनजीओ/संगठन में ऑनलाइन स्क्रीनिंग में सहयोग के लिए भारत में कुल 573 जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क किया है।

फ़िल्म निर्माण:

स्वच्छता कार्य योजना के तहत स्वच्छता फ़िल्में जैसे *सफाई, लोक्य, अ क्लीन गेम, बंजर, रेवा* फ़िल्मों को हाथ धोने के लाभों, व्यक्तिगत स्वच्छता के लाभ में, खुले में शौच के बारे में जागरूकता और शौचालयों की कमी के बारे में शिक्षित करने के लिए द्वितीय चरण में 6-16 वर्ष (लिटिल डायरेक्टर्स) के आयु वर्ग के छात्रों द्वारा राजस्थान में बनाई गई इन फ़िल्मों का प्रमाणन सम्पूर्ण हो चुका है।

आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण

सीएफएसआई अलग-अलग विभागों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर कंप्यूटरों का उपयोग कर रहा है जिन्हें समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है।

गतिविधियों में ई-कॉमर्स

फ़िल्म निर्माण के लिए प्रस्ताव जमा करने और प्रतिनिधियों के पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन कर दी गयी है और भुगतान गेटवे के साथ जोड़ दी गयी है। सीएफएसआई द्वारा आयोजित फ़िल्म महोत्सवों के लिए फ़िल्म प्रविष्टियां ऑनलाइन जमा की जाती हैं। सभी भुगतान और प्राप्तियां ऑनलाइन हो रही हैं। सेवाओं की खरीद के लिए ई-निविदा की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

Film and Television Institute of India

भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फ़िल्म संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। बाद में नाम बदलकर भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान कर दिया गया और अक्टूबर 1974 में सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसायटी में फ़िल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रख्यात हस्तियां, संस्थान के भूतपूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष की

अध्यक्षता में एक शासी परिषद द्वारा इसका संचालन होता है। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री शेखर कपूर हैं।

संस्थान के दो प्रभाग, फ़िल्म और टेलीविजन प्रभाग हैं, जो दो वर्षीय और तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

वर्ष 2021-22 की खास बातें

- **रे की स्मृति में:** सत्यजित रे की वर्ष-भर मनाये जाने वाली जन्मशती के भाग के रूप में एफटीआईआई द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में ख्यातिप्राप्त फ़िल्म शिक्षाविदों और उद्योग के जाने-माने पेशेवरों की विशिष्ट मंडली जिनमें से कई एफटीआईआई के पूर्व छात्र थे, ने रे के काम और उनकी पीछे छोड़ी गई धरोहर के बारे में चर्चा की।
- **श्री राज कुमार हिरानी की बातचीत:** एफटीआईआई के पूर्व छात्र और पारंगत फ़िल्मकार श्री राज कुमार हिरानी ने छात्रों और संकाय के साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली ऑनलाइन चर्चा की जिसका संचालन श्री शेखर कपूर, अध्यक्ष एफटीआईआई ने किया।
- **श्री ए.आर. रहमान की बातचीत:** अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार श्री ए.आर. रहमान ने एफटीआईआई के छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत की और संगीत से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की।
- **सुश्री सुमित्रा भावे की विरासत का जश्न:** एफटीआईआई ने एनएफएआई के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पुरस्कार विजेता निर्देशक सुश्री सुमित्रा भावे को ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने के लिए स्मरांजलि नामक कार्यक्रम का आयोजन किया।
- **श्री राज खोसला, श्री बिमल रॉय और श्री शांताराम को श्रंद्धाजलि देने के लिए भी स्मरांजलि कार्यक्रम किए गए।**
- 1971 के अभिनय बैच की स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया।
- **टीवी प्रभाग का स्वर्ण जयंती समारोह:** भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन प्रभाग ने भी अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इन गतिविधियों के एक भाग के रूप में एफटीआईआई आने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एन. नरवणे ने संस्थान के टीवी भवन के बाहरी भाग में लगे एक विशाल भित्तिचित्र का अनावरण करके उसे बहुआयामी श्री पी.एल. देशपांडे (जिसे पुल के नाम से जाना जाता है) की स्मृति में समर्पित किया।
- **एफटीआईआई का 23वां दीक्षांत समारोह:** भारतीय मूल की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता-निर्देशक मीरा नायर 28 सितंबर, 2021 को आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि थीं।
- **ब्रिक्स फ़िल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी:** सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिक्की के साथ एफटीआईआई ने 01-02 सितंबर, 2021 को ब्रिक्स फ़िल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी की सह-मेजबानी की। संगोष्ठी में पैनलिस्ट के रूप में अकादमिक परिषद के सदस्य थे जिन्होंने ब्रिक्स देशों और उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच फ़िल्म निर्माण के लिए सहयोग पर चर्चा की।
- **स्वर्णिम विजय वर्ष - विजय ज्वाला:** एफटीआईआई ने 18 अक्टूबर, 2021 को 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विजय ज्वाला का स्वागत किया।
- **आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह** के एक भाग के रूप में राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से एफटीआईआई ने विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों के लिए 75 लघु पाठ्यक्रम निःशुल्क आयोजित करने का निर्णय लिया। इन पाठ्यक्रमों को अमृत महोत्सव पाठ्यक्रम जो नाम दिया गया है और ऐसे चार पाठ्यक्रम जो प्रदान किए जा रहे हैं - (i) अभिनय, (ii) पटकथा लेखन (iii) स्मार्टफोन फ़िल्म मेकिंग और (iv) फ़िल्म एप्रिसिएशन। अमृत महोत्सव पाठ्यक्रम अक्टूबर, 2021 में शुरू हुए और अब तक एफटीआईआई ने 25 ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिसके अंतर्गत सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में 475 अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये पाठ्यक्रम मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और ओडिशा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिभागियों के लिए आयोजित किए गए थे।

फ़िल्म समारोहों में एफटीआईआई फ़िल्मों की भागीदारी

1. सुश्री पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित *'एंड व्हाट इज़ द समर सेइंग'* को मकाऊ में आयोजित सिनेमैथीक पैशन (26 जून से 4 जुलाई, 2021) में भेजा गया।

2. श्री वामसी तेलुगु द्वारा निर्देशित *'3सी48'* को फ़िल्म लाइट कलर अवाड्र्स (15 से 25 सितंबर, 2021) के लिए भेजा गया था।

3. 13वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म महोत्सव (25 से 30 सितंबर, 2021)
   i. श्री अनुनय बरभुइया की *भेजा नील तेरपाल*
   ii. सुश्री अस्मिता गुहा की *कैटडॉग*
   iii. सुश्री अरण्या सहाय की *चैत*
   iv. श्री प्रतीक गुप्ता की *शांताबाई*
   v. श्री सूरज मधाले की *वावतल*
   vi. श्री कौशिककुमार गरासिया की *वालन*
   vii. श्री मजहर कामरान की *नीलानी*
   viii. श्री सेरेल मुर्मू की *सोंधयानी*
   ix. श्री मलयज अवस्थी की *इन शैडोज़ वी हाईड*
   x. श्री राजर्षि सरकार की *रिटर्न टू द सिंडर*
   xi. श्री प्रतीक गुप्ता की *जंक्शन*

4. टोरून, पोलैंड में केमरिमेज़ 29वां इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ़ द आर्ट ऑफ़ द सिनेमेटोग्राफी (13 से 20 नवंबर, 2021)
   i. श्री जयदीप मानेपल्ली की *विकेड्नेस अनटू द विकेड*
   ii. श्री मानसिंह सी की *अंकाई टंकाई*
   iii. गुलसन जी नायक की *कामबडवाने*
   iv. श्री रंजन कुमार की *आरोह*
   v. श्री सौम्यजित गुहा की *व्हिस्पर्स ऑफ़ द हिना ट्री*

5. भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, गोवा का भारतीय पैनोरमा खंड (20 से 28 नवंबर, 2021)
   i. श्री लोहित लोधवाल की *अगातिक*
   ii. श्री राजर्षि सरकार की *रिटर्न टू द सिंडर*
   iii. सुश्री प्राची बजानिया की *द स्पेल ऑफ़ पर्पल*
   iv. श्री रोहित कुमार की *आशाओं के पार*
   v. श्री तुहिनाभ मजूमदार की *सांग्स फ्रॉम फारअवे लैंड*
   vi. श्री वामसी तेलुगु की *3सी48*
   vii. श्री सूरज मधाले की *वावतल*
   viii. श्री कौशिक कुमार गरासिया की *वालन*
   ix. श्री हिमांशु सिंह की *सांग्स ऑफ़ एन ओएसिस*
   x. श्री मजहर कामरानी की *नीलानी*

6. बेलफोर्ट फ़िल्म फेस्टिवल (21 से 28 नवंबर, 2021)
   i. श्री गणेश गायकवाड़ की *नन अदर*
   ii. श्री प्रशांतनु महापात्र की *अ लाइट आफ काइंडनेस*

7. इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म फेस्टिवल पिटरकिट, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस (नवंबर, 2021)
   i. सुश्री प्राची बजानिया की *द स्पेल ऑफ़ पर्पल*
   ii. श्री रोहित कुमार की *आशाओं के पार*
   iii. सुश्री नवनीता कृष्णन की *इलेक्ट्रिक टॉवर दैट स्वॉलो स्टोरीज*
   iv. श्री अभ्रदीप गांगुली की सलीम नगर की *चौथी गली मालेगांव*
   v. श्री युद्धजीत बसु की *कलसुबाई*
   vi. सुश्री अपूर्वा दुआ की *भोर*
   vii. सुश्री सिसिरा अनिल सी के की *कैथार्सिस*
   viii. श्री जयेश जोशी की *फ्लक*
   ix. श्री अंकुर अभिषेक की *मांगलिक*
   x. श्री जयेश जोशी की *निर्मल्या*

8. कौटिक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (23 से 26 नवंबर, 2021)
   i. श्री गणेश गायकवाड़ की *नन अदर*
   ii. श्री मिलिंद बापट की *स्वरमंथन*

9. साउथ एशियन फेमिनिस्ट फ़िल्म फेस्टिवल (1 से 4 दिसंबर, 2021)
   i. सुश्री प्राची बजानिया की *द स्पेल ऑफ़ पर्पल*
   ii. श्री सुशांत भट्ट की *पृथा*
   iii. श्री एम एम राहुल की *स्प्रिंग ऑफ़ मशरूम*
   iv. श्री सूरज मधाले की बेनरंग बंददी

10. 19वां कल्पनिर्झर फ़िल्म महोत्सव (8 से 12 दिसंबर, 2021)
   i. श्री गणेश गायकवाड़ की *नन अदर*
   ii. सुश्री नवनीता कृष्णन की *इलेक्ट्रिक टॉवर दैट स्वॉलो स्टोरीज*

iii. श्री रोहित कुमार की *आशा के पार*

iv. श्री जयेश जोशी की *निर्मल्या*

v. श्री वामसी तेलुगु की *3सी48*

vi. श्री अंकुर अभिषेक की *खलिक-ए-कुल*

11. सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता द्वारा आयोजित क्लैप स्टिक फ़िल्म महोत्सव (8 से 18 जनवरी, 2022)

i. सुश्री प्राची बजानिया की *द स्पेल ऑफ़ पर्पल*

ii. श्री रोहित कुमार की *आशाओं के पार*

iii. श्री लोहित लोधवाल की *अगातिक*

iv. श्री अभ्रदीप गांगुली की सलीम नगर की *चौथी गली मालेगांव*

v. श्री युद्धजीत बसु की *कलसुबाई*

vi. सुश्री अस्मिता गुहा की कैटडॉग

vii. श्री वामसी तेलुगु की *3सी48*

viii. श्री सौम्यजित गुहा की *व्हिस्पर्स ऑफ़ द हिना ट्री*

ix. श्री अमर्त्य रॉय की *आपला भासे डोंगाभर*

x. श्री रंजन कुमार की *आरोह*

12. श्री गणेश गायकवाड़ की निर्देशित फ़िल्म 'नन अदर' 51वें इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल रॉटरडैम (26 जनवरी से 6 फरवरी, 2022) में भेजी गई।

13. 24वां क्योटो इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म एंड वीडियो फेस्टिवल, 2021, जापान (फरवरी, 2022)

i. श्री रोहित कुमार की *आशाओं के पार*

ii. श्री अभ्रदीप गांगुली की सलीम नगर की *चौथी गली मालेगांव*

iii. श्री सौम्यजित गुहा की *व्हिस्पर्स ऑफ़ द हिना ट्री*

iv. श्री अमर्त्य रॉय की *आपला भासे डोंगाभर*

v. श्री युद्धजीत बसु की *कलसुबाई*

vi. सुश्री अपूर्वा दुआ की *भोर*

vii. सुश्री सिरसिरा अनिल की *कैथार्सिस*

viii. श्री जयेश जोशी की *फलक*

ix. श्री अंकुर अभिषेक की *मांगलिक*

x. श्री जयेश जोशी की *निर्मल्या*

14. बर्लिन फ़िल्म समारोह (11 से 20 फरवरी, 2022)

i. श्री गणेश गायकवाड़ की *नन अदर*

ii. श्री मिलिंद बापट की *स्वरमंथन*

एफटीआईआई फ़िल्मों के लिए पुरस्कार

1. श्री युद्धजीत बसु द्वारा निर्देशित *"कलसुबाई"* ने ओबरहाउज़ेन में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता में सार्वदेशिक जूरी का विशेष उल्लेख और जर्मनी के ओबरहाउज़ेन शहर का ग्रैंड ऑनलाइन पुरस्कार (10 मई, 2021) जीता।

2. श्री टी. वामसी द्वारा निर्देशित ''3सी48'' ने कल्पनिर्झर फ़िल्म महोत्सव, कोलकाता (11 दिसंबर, 2021) में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता।

Satyajit Ray Film and Television Institute

सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान

सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की स्थापना 1995 में एक स्वायत्तशासी शिक्षण संस्था के रूप में की गई और यह पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है। महान फ़िल्मकार सत्यजित रे के नाम पर स्थापित यह संस्थान सिने-शिक्षण का राष्ट्रीय केंद्र है, जो फ़िल्मों में छह विशेषज्ञताओं-(1) निर्देशन एवं पटकथा लेखन, (2) सिनेमैटोग्राफी, (3) संपादन, (4) साउंड रिकॉर्डिंग एवं डिजाइन, (5) फ़िल्म एवं टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया प्रबंधन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है।

वर्ष की खास बातें

➢ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तत्वावधान में वर्ष भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रम जैसे चर्चा/वेबिनार, 'पोषक' प्रतियोगिता आदि आयोजित किए गए।

- एसआरएफटीआई के छात्र शरण वेणुगोपाल की फ़िल्म *'ओरु पाथिरा स्वप्नम पोल'* ने **अक्टूबर, 2021 को आयोजित 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में** "पारिवारिक मूल्यों" श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता।

- अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में संस्थान ने बहुमुखी प्रतिभासंपन्न और रचनात्मक फ़िल्मकार सत्यजित रे की जन्म शताब्दी भव्य रूप से मनाया। इसी सिलसिले में जनवरी, 2022 में एक अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था।

- एसआरएफटीआई में 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2021 यथोचित ढंग से मनाया गया। सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार एक योग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमे संकाय अधिकारियों और छात्रों ने भाग लिया।

- सोलह अधिकारी प्रशिक्षुओं का एसआरएफटीआई से एक-दिवसीय अटैचमेंट था। इस ऑनलाइन अटैचमेंट के दौरान, निदेशक, रजिस्ट्रार और संकाय सदस्यों ने प्रशिक्षुओं के साथ फ़िल्म निर्माण पद्धति में उभरते क्षेत्रों और डिजिटल मीडिया पर विशेष जोर देने के साथ नई सामग्री, नई तकनीक और नई नीतियों पर चर्चा की।

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की अधिसूचना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर, संस्थान ने 9 दिसंबर, 2021 को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में अमृता दासगुप्ता ने इस संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों के समक्ष व्याख्यान दिया।

- संस्थान ने 2 से 31 अक्टूबर, 2021 तक गहन स्वच्छता अभियान चलाया। विभिन्न परिसरों, सभागारों, कार्यालयों, छात्रावासों और कैंटीन में विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

- संस्थान ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। संस्थान में *स्वतन्त्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता* विषय पर एक बैनर प्रदर्शित किया गया था।

- संस्थान ने 14 से 28 सितंबर, 2021 तक 'सदैव ऊर्जावान: निरंतर प्रयासरत' के आदर्श वाक्य का पालन करते हुए हिंदी पखवाड़ा मनाया। प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी निबंध, टिप्पण और श्रुतलेख पर हिंदी में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

- समीक्षकों द्वारा सराहे गए फ़िल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता की स्मृति में सिनेमा ऑफ बुद्धदेव दासगुप्ता नामक प्रस्तुति 10 जून, 2021 को वर्चुअल मोड पर आयोजित की गई।

- निर्देशन और पटकथा लेखन विभाग ने सीएपीए और सीआईएलईसीटी पुरस्कारों के लिए फ़िल्म प्रविष्टियां भेजना आसान और सुनिश्चित किया। फ़िल्मों की संस्थान रैंकिंग सीआईएलईसीटी को भेजी गई। इसके अलावा निर्देशन और पटकथा लेखन विभाग ने प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती के साथ एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया। इस सत्र में 80 फ़िल्म पारखी, आकांक्षी कला निर्देशक और फ़िल्म निर्माताओं ने भाग लिया।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए संस्थान गैर-सीआईएलईसीटी सदस्य देशों को मांग और जरूरतों के आधार पर ऑनलाइन और प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तैयार है। इस संबंध में संकाय सदस्यों ने ग्रिफिथ फ़िल्म स्कूल, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन गोलमेज चर्चा में भाग लिया।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान परियोजना ए जर्नी टू यूरोप के तहत संस्थान के पूर्व छात्रों की पटकथाओं का चयन किया गया।

महान फ़िल्म उस्ताद स्वर्गीय सत्यजित रे का जयंती समारोह

- सुप्रसिद्ध फ़िल्म फनकार सत्यजित रे के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए संस्थान ने वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई। आयोजन के आरंभ को चिह्नित करने के लिए, 2 मई, 2021 को एक संक्षिप्त प्रस्तावना वीडियो लॉन्च किया गया। वीडियो में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री के संदेश को दिखाया गया।

फ़िल्म महोत्सवों में भागीदारी					
नाम	**विभाग**	**फ़िल्म का नाम**	**पुरस्कार**	**श्रेणी**	**अवधि**
असाधारण उपलब्धियां					
शरण वेणुगोपाल	निर्देशन और पटकथा लेखन	*ओरु पाथिरा स्वप्नम पोल*	सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म के लिए 67 वां राष्ट्रीय पुरस्कार	पारिवारिक मूल्य	अक्टूबर, 2021
अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों में भागीदारी					
नाम	**विभाग**	**फ़िल्म का नाम**	**फ़िल्म महोत्सव**	**श्रेणी**	**अवधि**
सुबर्ना दास	एनिमेशन सिनेमा	*अमयी*	वीजीआईके (रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिनेमा) स्टूडेंट्स फ़िल्म फेस्टिवल, एनेसी फ़िल्म फेस्टिवल, क्राकोव फ़िल्म फेस्टिवल, ड्रामा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, ले फेम्मा एनिमेन्ट	–	जून, 2021
अनिंदिता दत्ता	एनिमेशन सिनेमा	*ट्राइसी*	बच्चों और युवाओं के लिए रोजाफा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव	–	नवंबर, 2021
भारत में फ़िल्म महोत्सवों में भागीदारी					
सोवन दत्ता	एनिमेशन सिनेमा	*नोतुन फसल*	आसिफा एनिमेशन	–	अक्टूबर, 2021
अभिजीत सारथी	निर्देशन और पटकथा लेखन	*बबलू बेबीलोन से*	इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	इंडियन पैनोरमा	नवंबर, 2021
ऋषि भौमिक	एनिमेशन सिनेमा	*मेघा*	इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	–	नवंबर, 2021
शरण वेणुगोपाल	निर्देशन और पटकथा लेखन	*ओरु पाथिरा स्वप्नम पोल*	इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	–	नवंबर, 2021
प्रतीक ठाकरे	निर्देशन और पटकथा लेखन	*सालाना जलसा*	इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	–	नवंबर, 2021
देबोत्तम बासु	निर्देशन और पटकथा लेखन	*निरापोद दुरोत्तो बोजय राखुन*	इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	–	नवंबर, 2021
वृशब मैत्री	निर्देशन और निर्माण	*गृह आर पैइबो कोठा*	इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फ़िल्म फेस्टिवल	–	नवंबर, 2021

- 2 मई, 2021 को एक विशेष वेबसाइट raytoday.in भी लॉन्च की गई। वेबसाइट का उद्देश्य शताब्दी समारोह के भाग के रूप में भारत सरकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों को प्रदर्शित करना था।
- ऑनलाइन फ़िल्म एप्रीसिएशन पाठ्यक्रम को स्वयं नामक ऑनलाइन प्लेटफार्म चालू किया गया।
- स्कूली बच्चों के लिए एक गतिविधि पुस्तक "मैजिशियन कॉल्ड रे" का परीक्षण किया जा रहा है। दिनांक 27.11.21 को विभिन्न केन्द्रीय विद्यालय संगठन, कोलकाता के स्कूलों के 20 कला शिक्षकों के लिए "शिक्षकों को प्रशिक्षण" का एक सत्र आयोजित किया गया।

अरुणाचल प्रदेश में फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान

देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की पहल के रूप में और फ़िल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) और सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की तर्ज पर एक फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) अरुणाचल प्रदेश में एफटीआईआई के निर्माण कार्य में सक्रिय है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर है (52% निर्माण पूर्ण)।

वर्तमान में फ़िल्म और टेलीविजन क्षेत्र से संबंधित लघु अवधि के पाठ्यक्रम कैंपस के अस्थायी परिसर में संचालित किए जा रहे हैं।

nfai
national film archive of india
राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में फ़िल्मों के संरक्षण का महत्व पूरे विश्व में माना जाता है। अपनी विविध अभिव्यक्तियों और स्वरूपों में फ़िल्म संरक्षण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार को सौंपा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त मीडिया इकाई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार की 1964 में स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार सरकार की अनुभूति का नतीजा है कि फ़िल्में किताबों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह ही मूल्यवान हैं और देश की फ़िल्म विरासत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की जरूरत है।

भारतीय सिनेमा की विरासत को संगृहीत करने और उसे संरक्षित करने के प्राथमिक चार्टर के अलावा, यह सुनिश्चित करना कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी दुनिया भर में और अधिक दृष्यमान बनी रहे, यह अभिलेखागार के घोषित उद्देश्यों में से एक है।

भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं:

1. भारतीय सिनेमा की धरोहर की पहचान, इसकी प्रगति और इसे चिरस्थायी बनाना और विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संकलन तैयार करना।
2. फ़िल्मों से जुड़े आंकड़ों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करना, सिनेमा के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसी सामग्री को प्रकाशित तथा वितरित करना।
3. भारत में फ़िल्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के केन्द्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज करना।

सांगठनिक ढांचा

पुणे में मुख्यालय के अलावा एनएफएआई के बेंगलुरु, कोलकाता एवं तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य समितियों, शैक्षिक संस्थाओं तथा सांस्कृतिक संगठनों के जरिये संबंधित क्षेत्रों में फ़िल्म संस्कृति का प्रसार करना है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज पर एनएफएआई के निदेशक नजर रखते हैं। तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर एनएफएआई के कर्मचारियों की कुल संख्या – प्रशासनिक प्रखंड में 22 और तकनीकी प्रखंड में 27 है।

एनएफएआई की फ़िल्म अधिग्रहण नीति

- वे फ़िल्में जिन्हें भारत में फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में पुरस्कार और श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।

- भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई गई फ़िल्में।
- फ़िल्में जो बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय रही हैं और भारत और विदेशों में ज्यादा दर्शकों द्वारा देखी गई हैं।
- भारतीय और विदेशी दोनों प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों का फ़िल्म रूपांतरण। भारत और विदेशी स्थानों में शूट की गई और भारतीय या विदेशी नागरिकों द्वारा बनाई गई फ़िल्में।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फ़िल्में। बच्चों की अच्छी फ़िल्मों के प्रतिरूप नमूने।
- भारतीय और विदेशी निर्माताओं द्वारा किए गए समाचार कवरेज में दर्ज वास्तविक सामग्री।
- सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक महत्व के वृत्तचित्र।

फ़िल्म संग्रहण/संरक्षण

एनएफएआई में अभिलेखीय मानकों और विशिष्टताओं के साथ लगभग 27 अत्याधुनिक फ़िल्म संरक्षण सुविधाएं/वॉल्ट हैं। इन वाल्टों में लगभग 2 लाख रीलों के संग्रहण की क्षमता है। ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों, रंगीन फ़िल्मों और नाइट्रेट आधारित फ़िल्मों के लिए फ़िल्म वाल्टों को निम्नलिखित तापमानों के साथ बनाए रखा जाता है:

फ़िल्मों के प्रकार	तापमान	आपेक्षिक आर्द्रता
नाइट्रेट फ़िल्म	10 डिग्री -12 डिग्री से.	40 प्रतिशत
ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में	10 डिग्री -12 डिग्री से.	40 प्रतिशत ± 5
रंगीन फ़िल्में	2 डिग्री -4 डिग्री से.	30 प्रतिशत ± 5

एफआईएएफ

एनएफएआई मई, 1969 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म आर्काइव्स का सदस्य है। एफआईएएफ की सदस्यता के कारण एनएफएआई को संरक्षण की तकनीकों, दस्तावेजीकरण, संदर्भ ग्रंथ सूची आदि पर विशेषज्ञों की सलाह, जानकारी एवं सामग्री प्राप्त होती है। इससे अभिलेखीय आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्य अभिलेखागारों से दुर्लभ फ़िल्मों की अदला-बदली भी हो जाती है।

महत्वपूर्ण अधिग्रहण

प्रमुख वृत्तचित्र फ़िल्म निर्माता और फ़िल्म इतिहासकार विजय मुले के व्यक्तिगत संग्रह से पुस्तकों और फ़िल्मों का एक विशाल संग्रह अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का हिस्सा है। उनकी बेटी, प्रसिद्ध अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने एनएफएआई को बहुमूल्य संग्रह दान किया। व्यक्तिगत संग्रह में 200 से अधिक किताबें, विभिन्न वीएचएस टेप और 16 मिमी फारमैट में एक फ़िल्म शामिल है। इस संग्रह में विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों की भारी संख्या में भारतीय सिनेमा, प्रमुख फ़िल्म निर्माताओं, विश्व सिनेमा की फिक्शन और गैर फिक्शन फ़िल्में और विश्व विख्यात फ़िल्म निर्माताओं की विशाल विविधता शामिल है। इसमें विभिन्न फ़िल्म महोत्सवों की पत्रिकाएं, शोध पत्रिका, फ़िल्म शब्दकोष और विवरणिका/आधिकारिक दस्तावेज भी हैं।

- वयोवृद्ध अभिनेता डॉ. मोहन अगाशे ने एनएफएआई को विभिन्न फ़िल्म समारोहों के लगभग 150 कैटलॉग दान में दिए।
- विभिन्न फ़िल्म वितरकों से प्राप्त फ़िल्मों का एक विशाल संग्रह अब भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार का हिस्सा है। इस संग्रह में हिंदी और मराठी फ़िल्में शामिल हैं।
- एनएफएआई को श्री प्रमोद लाहिड़ी, निर्माता, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से तपन सिन्हा की लौह कपाट (1957/बंगाली) की एक डीवीडी प्राप्त हुई।
- सुश्री अलीका किर्लोस्कर, पुणे से किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से संबंधित वीएचएस, बीटाकैम, यू मैटिक, 16 एमएम फ़िल्म के पांच बॉक्स प्राप्त हुए।
- श्री दिनेश ठाकुर द्वारा एक डिजिटल ऑडियो टेप (शीर्षकः *पु.ला. देशपांडे*) एनएफएआई को दान में दिया गया।
- श्री ज्वंगदाओ बोडोसा (बोडोसा फ़िल्म निर्माण) से बोडो फ़िल्म सामग्री प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 2के डीपीएक्स, 2के एमओवी फाइल तथा डिजिटल संरक्षण के उद्देश्य से मेसर्स बोडोसा फ़िल्म निर्माण असम से "अलायरोन" का साउंड स्कैन प्राप्त हुआ।

श्री किरण वी. शांताराम (अध्यक्ष), राजकमल स्टूडियो एस.एस. राव रोड परेल द्वारा थर्ड आई फ़िल्म फेस्टिवल से डीवीडी के इक्कीस बॉक्स प्राप्त हुए हैं जिसे परेल द्वारा लाया गया है। मैसर्स प्रिया सिनेमा, कोलकाता (सुश्री पूर्णिमा दत्ता) से दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को एनएफएचएम के तहत

डिजिटलीकरण के लिए प्राप्त अन्य फ़िल्म एलीमेंट्स के साथ सत्यजित सहित दो खिताबों के कैमरा निगेटिव प्राप्त हुए।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को एनएफएचएम के तहत डिजिटलीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अन्य फ़िल्म एलीमेन्ट के साथ-साथ चार और सत्यजित रे खिताब के कैमरा निगेटिव प्राप्त हुए।

फ़िल्म समारोहों में भागीदारी

दिनांक 02 से 09 दिसंबर, 2021 तक 19वें पुणे अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। एनएफएआई इस उत्सव का एक इवेंट भागीदार था। पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए एनएफएआई द्वारा मुख्य थियेटर में प्रतिदिन 4 शो आयोजित किए गए।

हंगरी के महावाणिज्य दूतावास के संयोजन तथा अमीरात एयरलाइंस के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार द्वारा दिनांक 10 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2021 तक मुम्बई में हंगरियन फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया।

मौखिक इतिहास योजना

मार्च/अप्रैल 2021 में एनएफएआई द्वारा वेबसाइट पर लगभग 8,000 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मौखिक इतिहास योजना उपलब्ध कराई गई जो एनएफएआई अनुसंधान योजना का हिस्सा है। इसमें 1980 के दशक में रिकॉर्ड किए गए प्रसिद्ध फ़िल्म हस्तियों के 53 साक्षात्कार 5 भाषाओं में शामिल हैं, जो उनके जीवन, कहानियों और किस्सों के बारे में बताते हैं। जिन हस्तियों के साक्षात्कार लिए गए हैं उनमें अन्य के साथ-साथ जे.वी.एच. वाडिया, अक्किनेनी नागेश्वर राव, विजय भट्ट, पी भानुमति, एस.डी. सुब्बुलक्ष्मी, सी. होन्नप्पा भागवतर, जुनजाराव पवार, दादा सालवी, चन्द्रकान्त गोखले, आरएम कृष्णास्वामी, एस.वी. वेंकटरमण, विष्णुपंत जोग, नाना साहेब साठे, नीलू फुले, शोभा सेन और सौमित्र चटर्जी शामिल हैं। एनएफएआई ने क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड की गई सभी सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया है।

सोशल मीडिया आउटरीच

अगली पीढ़ियों के लिए फ़िल्मों को संगृहीत और संरक्षित करने के मिशन के साथ, फ़िल्मी साक्षरता भी एनएफएआई के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। यहीं सोशल मीडिया भारतीय सिनेमा पर ज्ञान और जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों को समृद्ध करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। एनएफएआई अपने सोशल मीडिया पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पर्यावरण दिवस, महात्मा गांधी की जन्मशती, डॉ. बी आर अंबेडकर जयंती आदि जैसे महत्वपूर्ण दिवसों पर भी वीडियो अपलोड करता है। एनएफएआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सशक्त उपस्थिति है।

विशेष कार्यक्रम

चित्रांजलि@75: एक प्लैटिनम पैनोरमा:

भारत की आज़ादी के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एनएफएआई ने फ़िल्म पोस्टर और तस्वीरों की एक विशेष वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई है। भारत में सिनेमा के जन्म के बाद से, सिल्वर स्क्रीन ने कई युगों में स्वतंत्रता आंदोलन के अद्वितीय संघर्ष को कई भाषाओं में चित्रित किया है। एनएफएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर 75 प्रतिष्ठित फ़िल्मों की विशेषता वाले पोस्टरों की एक वर्चुअल प्रदर्शनी, एकत्रित दृश्यों, सूचनाओं, डेटा और सामग्रियों को एक साथ रखते हुए प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ 27 अगस्त, 2021 को माननीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया था।

- आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, विभिन्न वृत्तचित्रों को एनएफएआई द्वारा डिजिटाइज किया गया है और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित किया गया है।
- एनएफएआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे फेस ऑफ द वीक सेगमेंट के साथ दिग्गज फ़िल्म निर्माता सत्यजित रे की जन्म शताब्दी मनाई गई। उनके शानदार कॅरियर में विभिन्न फ़िल्मों से उनके काम की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न चित्र, वीडियो, दुर्लभ समाचार लेख, पुस्तक अंश पोस्ट किए गए।
- शर्मिला टैगोर, अपर्णा सेन, अनंत महादेवन, के. हरिहरन, समिक बंदोपाध्याय, अरुणाराजे पाटिल और अमित त्यागी की उपस्थिति में एनएफएआई यूट्यूब चैनलों पर रे के कालातीत योगदान पर एक लाइव कार्यक्रम को कवर किया गया तथा इसे एनएफएआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया।
- विश्व पर्यावरण दिवस पर *बनानी* (1989) और *स्वास्थ्य के लिए योग* (1950) और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर समाधि (1977) को एनएफएआई के यूट्यूब चैनलों पर अपलोड किया गया तथा इसके महत्व को दर्शाते हुए एनएफएआई के सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया गया।

विभिन्न कार्यक्रमों और एनएफएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए फ़िल्मों की आपूर्ति:

भारत में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एनएफएआई की गतिविधियां अनेक हैं। इसकी वितरण लाइब्रेरी में देश भर में लगभग 25 सदस्य हैं। सक्रिय फ़िल्म क्लब अभिलेखागार भारत भर में विभिन्न स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और फ़िल्म समारोहों के लिए फ़िल्मों की आपूर्ति करता है। वर्ष के दौरान एनएफएआई द्वारा अन्य संगठनों के साथ उनके समन्वय से विभिन्न फ़िल्म समारोहों हेतु फ़िल्मों की आपूर्ति की जाती है।

एनएफएआई, अर्थात फ़िल्म क्लब और राजू सुतार ने मिलकर वृत्तचित्र फ़िल्मों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक फ़िल्म क्लब का शुभारंभ किया। फ़िल्म क्लब हर महीने फ़िल्म निर्माताओं और फ़िल्म विद्वानों के साथ संवादात्मक सत्रों के द्वारा एक वृतचित्र फ़िल्म का प्रदर्शन करेगा।

अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों के लिए भेजी गई फ़िल्में:

- मृणाल सेन द्वारा निर्देशित *इंटरव्यू,* फुल एचडी डिजिटल फाइल का अनलिस्टेड यूट्यूब लिंक बी'बॉक बर्लिन के साथ साझा किया गया।
- जॉन अब्राहम की *अम्मा एरियन* के 2के डीसीपी को II सिनेमा रित्रोवतो महोत्सव 2021 (बोलोग्ना, इटली) के साथ-साथ 17वें बेरविक फ़िल्म एंड मीडिया आर्ट महोत्सव, 2021 को प्रदान किया गया।
- मनमोहन महापात्रा की *नीरबा झाडा* की फुल एचडी डिजीटल फाइल दुबई में प्रतिष्ठित वर्ल्ड एक्सपो 2020 के दौरान प्रदर्शित 'सिने ओडिशा, दुबई - ओडिशा का अनंत सिनेमा' के लिए प्रदान की गई थी।
- श्याम बेनेगल के *मंथन* के लिए फुल एचडी डिजीटल फाइल का अनलिमिटेड यूट्यूब लिंक लिबरेटिंग सिनेमा एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम को प्रदान किया गया।

फ़िल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम

ऑनलाइन माध्यम से एफटीआईआई के समन्वय से दिनांक 20 मई से 19 जून, 2021 के दौरान चार सप्ताह का फ़िल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस कोर्स में कुल 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2021 के दौरान फेडरेशन ऑफ फ़िल्म सोसायटी ऑफ इंडिया के समन्वय में मराठी में एक फ़िल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में कुल 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दिनांक 6 दिसंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2022 के दौरान शीतकालीन फ़िल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पाठ्यक्रम में कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

योजना परिव्यय

एनएफएआई के अंतर्गत योजना स्कीम यथा फ़िल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 37.20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत परिव्यय स्कीम के अंतर्गत कुल 12.62 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

बजट आंकलन 2021-2022

(धनराशि करोड़ में)

मुख्य शीर्ष "2220" -सूचना और प्रसार	स्थापना	केन्द्रीय सेक्टर स्कीमें
राजस्व	10.58	37.20
पूंजी	0.00	12.62
कुल	10.58	49.82

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण

एनएफएआई के कार्यकलापों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए समय-समय पर नियम-कायदों में संशोधन किया जाता है।

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

एनएफएआई में 23.9.2021 और 24.9.2021 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस आयोजन के दौरान हिंदी अनुवाद, राजभाषा नीति संबंधी ज्ञान आदि जैसी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। एनएफएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हिंदी के प्रति अपना लगाव दिखाया। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर दिनांक 24.9.2021 को हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। प्रवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, हिंदी राजभाषा विभाग, पुणे ने राजभाषा और प्रौद्योगिकी पर एक कार्यशाला का संचालन किया।

विभागीय खाते

एनएफएआई 1976 में शुरू की गई विभागीय लेखा प्रणाली का प्रयोग करता है। इस व्यवस्था के तहत एनएफएआई के वेतन और खातों को पीएओ, एफडी और मुंबई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निदेशक, एनएफएआई को विभाग प्रमुख होने के नाते डीडीओ के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने उप निदेशक सह क्यूरेटर, एनएफएआई को अपनी कार्य शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

आरटीआई

एनएफएआई ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। एनएफएआई को 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान 37 आवेदन प्राप्त हुए और आवेदकों को नियमानुसार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से संगठन के कामकाज में पारदर्शिता आई है।

शिकायत प्रकोष्ठ

निदेशक, एनएफएआई को विभाग प्रमुख होने के नाते शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सरकारी नियमों और मानदंडों के अनुसार सभी शिकायतों का निवारण किया गया है।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर एनएफएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नागरिक संगठन की वेबसाइट www.nfaipune.gov.in पर जा सकते हैं और आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। नागरिक चार्टर की सूचना को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

नैशनल फ़िल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम)

एनएफएचएम के तहत एनएफएआई का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:

- एनएफएआई के फ़िल्म रीलों के संग्रह की स्थिति का आकलन और उनके उपयोग की शेष अवधि का पता लगाना।
- लगभग 1,32,000 फ़िल्म रीलों का निवारक संरक्षण।
- 1,160 फीचर फ़िल्मों और 1,660 लघु फ़िल्मों का डिजीटलीकरण।
- भारतीय सिनेमा की 1,086 कालजयी फीचर फ़िल्मों और 1,152 लघु फ़िल्मों की 2के/4के पिक्चर और ध्वनि में सुधार तथा प्रत्येक फ़िल्म की नई पिक्चर और ध्वनि इंटर निगेटिव की रिकार्डिंग।
- अत्याधुनिक अवसंरचना के अंतर्गत नवीनीकृत सामग्री के संरक्षण के लिए अभिलेखीय और संरक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- संरक्षण, परिरक्षण और अभिलेखीय कार्यों के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशालाओं और पाठ्यक्रम का संचालन और आयोजन तथा इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करना।
- वेब आधारित एंड टू एंड आईटी समाधान के माध्यम से आंतरिक क्षमता निर्माण।

भारत सरकार भारत की फ़िल्म विरासत की बहाली, डिजिटलीकरण और अभिलेखन के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रह के माध्यम से (एनएफएआई) मिशन मोड में राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) लागू कर रही है। एनएफएचएम को नवंबर 2014 में एक योजना के रूप लॉन्च किया गया था, जो शुरू में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक थी और 597.41 करोड़ रुपये की कुल लागत पर परिकल्पित थी। एनएफएचएम को मिशन मोड में पुनर्गठित किया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि के दौरान 544.82 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जारी रहा।

आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस/ई-कॉमर्स

एनएफएआई एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है और यह भारतीय सिनेमा की विरासत का संवर्धन और संरक्षण करने के प्रमुख कार्य में लगा हुआ है। यह देश में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। आम जनता, सिनेमा के गंभीर छात्र और देश के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर से शोधकर्ता संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से इसके सग्रह और सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फ़िल्म अभिमूल्यन पाठ्यक्रम और अनुसंधान अध्येतावृत्ति स्कीमों के आवेदन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सार्वजनिक प्रश्नों का ज्यादातर ई-मेल (nfaipune@gmail.com) के माध्यम से जवाब दिया जाता है। एनएफएआई के आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट हैं तथा ये सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।

सतर्कता गतिविधियां

इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है और इस प्रकार विभाग के प्रमुख होने के नाते निदेशक सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

अवधि के दौरान और 12 औचक निरीक्षण किए गए।

निगरानी में रखे जाने के लिए चिन्हित किए गए व्यक्तियों की संख्या : शून्य

रंगमंच सुविधाएं

एनएफएआई के तीन बहुउद्देश्यीय थिएटर हैं। मुख्य परिसर में 35 सीटों वाला एक पूर्वावलोकन थियेटर और 300 सीटों का मुख्य थिएटर तथा कोथरुड में 200 सीटों वाला अत्याधुनिक थिएटर। एनएफएआई के अपने कार्यक्रमों और एफटीआईआई की अकादमिक स्क्रीनिंग कार्यक्रमों, व्याख्यानों, सेमिनारों आदि के लिए भी सुविधाओं का लाभ उठाया गया।

निर्माताओं/कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

एनएफएआई निर्माताओं/कॉपीराइट मालिकों को फ़िल्मों की आपूर्ति के संबंध में उनकी ओरिजनल निगेटिव्स, डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने और प्रसारण उद्देश्यों के लिए वीडियो कॉपी करने के संबंध में सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्कों पर प्रसारित किए जा रहे कई सेल्युलाइड क्लासिक्स इसके संग्रह से एकत्र किए गए थे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान संग्रह (आर्काइव) में जोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण नए शीर्षकः-

ऑब्जेक्ट	35	आरपी	हिंदी	1 रील
ऑब्जेक्ट	35	डीएन (+)	हिंदी	1 रील
बेगुनाह	35	आरपी	हिंदी	1 रील
बेगुनाह	35	डीएन (+)	हिंदी	1 रील
ब्लफ मास्टर	35	आरपी	मराठी	7डी रील्स
अनरारिचा देवा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
सुभद्राहरण	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
बड़ा वर्षे साहा महीने तीन दिवस	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
चंद प्रीतिचा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
पुधरी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
हाट लविन टीथे सोना	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
चांडाल चौकड़ी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
दीद शाहने	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
नवसाचे पोर	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
जीव सखा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
कुठे कुठे शोधु मी तुला	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
धमाल बबल्या गणप्याची	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
आई एकवीरेचा उड़ो उड़ो	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
सदा हल्दी कुंकुवचा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
रखंदार	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
तैच्य बंगद्या	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
पोरिंची कमल बापची धमाल	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
फेका फेकी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
खिचड़ी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
वत पनाते पुनवेची	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
संत सखुवाई	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
दिस्ता तासा नास्ता	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
घोलत घोल	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
पंढारीची वारी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
आपली मानसा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
हाच सूनबैचा भाऊ	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
घायल	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
तू सुखकर्ता	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
चिकत नवारा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
टोपी वार टोपी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स

संत नामदेव	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
स्वप्न सौभाग्यचे	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
हिर्वे कुंकू	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
मुन्नाभाई एसएससी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
बापू बीरू वतेगांवकर	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
इक्ति	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
धक्ति बहिन	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
साधी मानसे	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
भाऊबीज	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
ओवलिटे भौरैया	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
अनोखी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
ताई तेलिन	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
सुगंधी कट्टा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
राजमान्य राजश्री	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
पवनकत्या धोंडी (एनएएडब्ल्यू)	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
घरकुल	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
देव पावला	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
कलत नकलत	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
जगवेगली पैज	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
सौभाग्य कंकन	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
दुर्गा अली धारा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
बला जो जो रे	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
जय सप्तश्रृंगी माता	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
रणपाखरण	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
नवारा मुंबईचा	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
महेराची मनसे	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
गेंधलत गोंधल	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
देवकी	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
ऐकवे ते नवलच	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स

बन्या बापू	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
भराला मालवत रक्ताने	16	आरपी	मराठी	4 स्पूल्स
ढकाण	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
जवाब	16	आरपी	हिंदी	5 स्पूल्स
जुड़वा	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
ज्योति बने ज्वाला	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
धनवानी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
टाज का गुंडाराजी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
बिदाई	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
सहेब	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
हेरा फेरी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
जानी दुश्मन	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
अर्पण	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
एलान	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
धर्मात्मा	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
अदालत	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
अमान	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
नॉटी ब्याय	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
ताजमहल	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
सूर्या	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
बहुरानी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
बंदी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
दा यार	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
शिकारी	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
बुलन्दी	16	आरपी	हिंदी	1 स्पूल्स
पाकीजा (प्रीमियर गीत)	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
ईजा बीजा तीजा	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
गेस्ट हाउस	16	आरपी	हिंदी	2 स्पूल्स
ब्रज दर्शन	16	आरपी	हिंदी	

खान अब्दुल गफार खान	35	सिर्फ एसएन	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राम अवतार	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
पैसा ही पैसा	16	आरपी	हिंदी	5 स्पूल्स
माडी माने केहवा दे	16	आरपी	गुजराती	2 रील्स
मजियारा हैया	16	आरपी	गुजराती	1 रील
मेरा घर मेरे बच्चे	16	आरपी	हिंदी	2 रील्स
दिल तेरा दीवाना	16	आरपी	हिंदी	4 स्पूल्स
बेगुनाह	16	आरपी	हिंदी	2 रील्स
मुगल-ए-आजम	35	आरपी	हिंदी	10 डब्ल
गुंडा नबंर 1	35	आरपी	हिंदी (डब)	6 डब्ल
बिग ब्रदर	35	आरपी	हिंदी	8 डब्ल
जान पहचान	35	पीएन	हिंदी	11 रील्स
सनम	35	पीएन	हिंदी	12 रील्स
सनम	35	एसएन	हिंदी	9 रील्स

31 दिसम्बर, 2021 तक वर्ष के दौरान अभिलेखीय अधिग्रहण का विवरण:

मद	संख्या
फ़िल्में	107
वीडियो कैसेट्स	869
डीवीडी	2,000
पुस्तकें	1,095
प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्ट	01
चित्र	4,420
वॉल पोस्टर्स	1,192
गीत पुस्तिका	409
ऑडियो कैसेट्स	255
पैम्फलेट/फोल्डर्स	113
स्लाइड्स	863
सहायक फ़िल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	5,201

योजना प्रदर्शन 2021-22

धनराशि (करोड़ में)

कार्यक्रम/स्कीमें	एस.बी.जी. 2021-22	आर.ई. 2021-22	14.12.2021 तक वास्तविक व्यय
फ़िल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	37.20	24.06	8.40
पूंजीगत परिव्यय (प्रमुख कार्य) (एनएफएचएम)	12.62	12.62	7.75

एनएफएआई के सभी महत्वपूर्ण कार्यालापों के आंकड़े:

रील्स/फ़िल्मों की संख्या		16 एमएम	35 एमएम
1.	फ़िल्मों की विस्तृत जांच	-	514
फ़िल्म संस्कृति का प्रसार			
1.	विशेष अवसरों के लिए उपलब्ध कराई गई फ़िल्में	-	6
2.	संयुक्त स्क्रीनिंग	-	4
3.	अनुसंधान कार्यकर्ता को प्रदान की गई अवलोकन सुविधाएं	-	11
4.	अकादमिक स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई को उपलब्ध कराई गई फ़िल्में	-	5
5.	एनएफएआई में प्रदर्शित फ़िल्मों की संख्या	-	109
6.	पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने वाले पाठकों की संख्या	-	567
7.	दस्तावेजीकरण अनुभाग की सेवाओं का लाभ उठाने वाले अनुसंधानकर्ताओं की संख्या	-	778

फ़िल्म समारोह निदेशालय

फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 1973 में भारतीय फ़िल्म कला को प्रोत्साहन देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उद्देश्य के साथ हुई थी।

डीएफएफ कई ऐसे आयोजन करता है जिसमें प्रमुख हैं- दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन, भारतीय फ़िल्मों के भारत एवं विदेशों में संवर्द्धन के लिए भारतीय पैनोरमा।

52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) गोवा में 20 से 28 नवम्बर, 2021 तक आयोजित हुआ। वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों को देखते हुए आईएफएफआई का 52वां संस्करण हाइब्रिड फॉर्मेट में- भौतिक तथा वर्चुअल दोनों में आयोजित हुआ।

आईएफएफआई में संपूर्ण विश्व की बेहतरीन कन्टेमपोरेरी तथा क्लासिक फ़िल्मों के कोलाज का शोकेस होता है। विश्व के जाने-माने फ़िल्मकार, अभिनेता, तकनीशियन, समालोचक, अकादमिक विशेषज्ञ तथा फ़िल्मों के शौकीन साथ-साथ आकर विभिन्न फ़िल्म स्क्रीनिंग, प्रस्तुतीकरण, मास्टर क्लासेस, पैनल चर्चाओं, सह-निर्माण, सेमिनार तथा इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के जरिए फ़िल्म निर्माण की कला का तथा सिनेमा के उत्सव का लुत्फ उठाते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा में 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन के दौरन कुल 52 भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय अतिथि मौजूद थे। अतिथियों की सूची में स्टीयरिंग कमेटी सदस्य, तकनीकी कमेटी सदस्य, प्रिव्यु कमेटी सदस्य, अंतरराष्ट्रीय जूरी सदस्य, बीआरआई सीएस जूरी सदस्य, मुम्बई में फ्रांस के माननीय कौंसुल जनरल, हंगरियन एम्बेसी के कौंसुल जनरल, भारत-चीन फ़िल्म सोसायटी के सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे। इवेंट को श्री करन जौहर (स्टीयरिंग कमेटी सदस्य) तथा श्री मनीष पॉल ने को-होस्ट किया।

52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में 90 देशों से कुल 624 फ़िल्मों की भागीदारी हुई जिनमें से कुल 148 अंतरराष्ट्रीय फ़िल्में 73 देशों से प्रिव्यू कमेटी द्वारा अनुशंसित और स्क्रीन की गई थीं कम फ़िल्में बनाने वाले देश यथा चाड, अन्डोरा, माल्टा, सेनेगल, सोमालिया तथा अफगानिस्तान ने भी 52वें आईएफएफआई में भागीदारी की।

52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में कुछ ओटीटी प्लेयर्स यथा अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ज़ी तथा सोनीलिव ने मास्टरक्लास/इन कनवरसेशन सत्र आईएफएफआई के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया। 8 दिनों में 75 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई। समारोह के दौरान ऑनलाइन तथा भौतिक दोनों प्रकार से मास्टरक्लासेस/इन कनवरसेशन सत्र आयोजित किए गए।

फ़िल्म समारोह निदेशालय ने सत्यजित रे लाइफटाइम अचीवमेन्ट पुरस्कार (एसआरएलटीए) की स्थापना की है। पहली बार विश्व सिनेमा के दो प्रमुख हस्ताक्षरों, हंगरी के इस्तवान सजाबो तथा अमेरिका के श्री मार्टिन स्कोरसेसी को विश्व सिनेमा में उनके योगदान के लिए एसआरएलटी से सम्मानित किया गया।

ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका की फ़िल्मों की स्क्रीनिंग ''कन्ट्री फोकस – बीआरआईसीएस'' फ़िल्म सेक्शन के अंतर्गत की गई। फ़िल्मों की प्राप्ति ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के डिप्लोमैटिक मिशनों द्वारा की गई।

भारतीय पैनोरमा

भारतीय पैनोरमा सदैव ही आईएफएफआई का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। भारतीय पैनोरमा की विविध एवं बहु आयामी पैकेज फ़िल्में एक माह की प्रक्रिया के दौरान भारत के सभी हिस्सों की प्रमुख फ़िल्मी हस्तियों के चयन से तय हुई जो कि जूरी का प्रमुख हिस्सा थे।

भारतीय पैनोरमा में 12 भारतीय भाषाओं की 24 फीचर फ़िल्में तथा 12 भारतीय भाषाओं की 21 गैर फीचर फ़िल्में 52वें आईएफएफआई में स्क्रीनिंग हुईं।

फीचर श्रेणी में 7 तथा गैर फीचर श्रेणी में 10 निर्देशकों की पहली फ़िल्मों की स्क्रीनिंग आईएफएफआई के दौरान

हुई। साथ ही इनमें 5 विद्यार्थी फ़िल्म निर्माता तथा 4 महिला निर्देशिका भी रहीं।

द हिमालयन फ़िल्म फेस्टिवल, लेह, लद्दाख

द हिमालयन फ़िल्म फेस्टिवल, का आयोजन लद्दाख की केन्द्र शासित सरकार द्वारा फ़िल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया।

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांच दिवसीय पहले हिमालयन फ़िल्म फेस्टिवल का उद्घाटन सिंधु संस्कृति केन्द्र, लेह, लद्दाख के केन्द्र शासित क्षेत्र में किया। पांच दिवसीय यह समारोह भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के क्रम में था। प्रधानमंत्री के 'जन-भागीदारी' के आह्वान पर फ़िल्म समारोह में स्थानीय फ़िल्म निर्माताओं तथा 12 हिमालयन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्रतिभाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

हिमालयन राज्यों से लोकप्रिय फ़िल्मों में आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख की फ़िल्में तथा भारतीय पैनोरमा की चयनित फ़िल्में समारोह के दौरान दिखाई गईं। संपादन पर मास्टरक्लास प्रिया कृष्णास्वामी, वाइल्डलाइफ पर एस नालामुत्थू, निर्देशन पर नीला माधब पान्डा तथा अभिनय में फोनसोक लद्दाखी ने उचित कौशल तथा नेटवर्किंग अवसर उभरते तथा स्थापित फ़िल्मकारों के सम्मुख इस समारोह के दौरान प्रदान किया।

इसके साथ-साथ जानी-मानी फ़िल्मी हस्तियों यथा राकेश ओमप्रकाश मेहरा, अनुपम चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा तथा कीर्ति कुल्हारी के साथ भी सत्र आयोजित किए गए।

साथ ही, लघु फ़िल्मों तथा डॉक्यूमेन्ट्री के लिए एक प्रतियोगी खंड भी था जिसके जरिए भारत के हिमालयन क्षेत्र के प्रतिभाशाली फ़िल्मकारों की पहचान की जा सके तथा उन्हें मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

24 से 28 सितम्बर तक 5 दिनों तक विस्तृत समारोह में हिमालयन/केन्द्र शासित क्षेत्रों से 100 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। 26 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग हुई तथा जूरी द्वारा अनुशंसित 18 प्रविष्टियों की भी स्क्रीनिंग की गई।

सर्वोत्तम तीन लघु फ़िल्मों का पुरस्कार *द टेंटेड मिरर* (मेइतिलोन/मणिपुर), *गो फॉर ऑरगेनिक* तथा *होमवर्क एंड गॉडलीनेस* को प्राप्त हुआ, जिन्हें 3.50 लाख रुपये प्रत्येक का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। टैंकांग की प्रशंसित फ़िल्म *सिकूल* को सर्वोत्तम स्टोरी का पुरस्कार तथा गुरमीत की *शेडीः ए फॉरगॉटेन लैण्ड* ने सर्वोत्तम संपादन का पुरस्कार प्राप्त किया।

लेह, लद्दाख में, 24 सितम्बर, 2021 को पहले हिमालयन फ़िल्म समारोह, 2021 के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर। साथ में फ़िल्मी हस्तियां सिद्धार्थ मल्होत्रा और विधु विनोद चोपड़ा भी हैं।

67वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रमुख फ़िल्म पुरस्कारों में से है। 1954 में स्थापित इसका प्रशासन फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पुरस्कार निम्न खण्डों में विभक्त हैं : फीचर फ़िल्म तथा गैर-फीचर फ़िल्म खण्ड और सिनेमा पर सवोत्तम लेखन। राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के 67वें एडीशन में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2019 के राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार तथा सम्मानजनक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नई दिल्ली में 25 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया।

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, श्री अपूर्व चन्द्र, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जूरी के अध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में आयोजित इस इवेन्ट में मौजूद रहे। 67वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के नतीजे 31 विभिन्न श्रेणियों में घोषित किए गए थे।

हिन्दी फ़िल्म *'एन इन्जीनियर्ड ड्रीम'* ने सर्वोत्तम गैर फीचर फ़िल्म श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया जबकि *'माराक्कर-अरबिकाडालिन्ते-सिम्हम'* ने सर्वोत्तम फीचर फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। *'कस्तूरी'* को सर्वोत्तम बाल फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। *'श्रीक्षेत्रा-रु-सहीजाता'* को सर्वोत्तम कला तथा संस्कृति का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सिक्किम को सर्वोत्तम फ़िल्म फ्रेन्डली राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सवानी रवीन्द्र को सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मराठी फ़िल्म *बारदो* में उनके गीत रान पेटाला के लिए प्राप्त हुआ। मलयालम फ़िल्म *जल्लीकेट्टू* में सर्वोत्तम सिनेमेटेग्राफी के लिए गिरीश गंगाधरन को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ब्रिक्स फ़िल्म समारोह

इस वर्ष, आईएफएफआई ने विश्व की 5 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा 5 प्रमुख फ़िल्म निर्माता देशों को साथ-साथ प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगी समारोह की जूरी में 5 सदस्य थे जिनमें से एक-एक सदस्य प्रत्येक ब्रिक्स देश से था। पहली बार ब्रिक्स फ़िल्म समारोह 52वें आईएफएफआई के साथ 20-28 नवम्बर, 2021 में गोवा में हुआ।

राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के 67वें संस्करण में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु 25 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में लोकप्रिय अभिनेता श्री रजनीकान्त को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा श्री अपूर्व चन्द्र, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी हैं।

निर्देशक ऐमी जेफटा की दक्षिण अफ्रीकी फ़िल्म *बाराकट* तथा निर्देशक ल्यूबोव बोरिसेवा की रुसी फ़िल्म *द सन अबव मी नेवर सेट्स* ने सर्वोत्तम फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार ब्राजीलियन फ़िल्मकार लूसिया मूरट को उनकी डाक्यूमेन्टरी फ़िल्म *ऐना* के लिए दिया गया।

75 क्रिएटिव माइन्ड्स ऑफ टुमॉरो :

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे देश के प्रत्येक हिस्से में झंडा लहरा रहा है। 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में भाग लेने के लिए पूरे देश से 75 युवा प्रतिभाशाली फ़िल्मकार तथा फ़िल्म कलाकार चयनित हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के दिए विचारों से आकार पाए ''75 क्रिएटिव माइन्ड्स ऑफ टुमॉरो'' की अनोखी पहल का आभार कि इस प्रक्रिया से उभरती सिनेमाई प्रतिभाओं का चयन हो सका। यह प्रतियोगिता देश के रचनात्मक तथा उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का एक बेहतरीन प्रयास था। सभी चयनित व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का सर्वोत्कृष्ट देखने का अवसर प्राप्त हुआ साथ ही समारोह के दौरान मास्टर क्लास तथा परिचर्चाओं के जरिए सीखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता के लिए चयनित सबसे युवा उम्मीदवार - आर्यन कुमार बिहार से है और मात्र 16 वर्ष का है और जिसे फ़िल्म निर्देशन के उसके कौशल के लिए चुना गया। 75 युवा जो सभी 35 वर्ष से कम आयु के हैं, का चयन फ़िल्म निर्माण में निर्देशन, संपादन, गायन तथा स्क्रीनप्ले के उनके अनोखे कौशल के कारण हुआ।

भारतीय पैनोरमा फ़िल्म समारोह, मणिपुर

इम्फाल में 11 से 15 दिसम्बर, 2021 को 5 दिवसीय 'भारतीय पैनोरमा फ़िल्म फेस्टिवल, मणिपुर' का आयोजन मणिपुर स्टेट फ़िल्म डेवलेपमेन्ट सोसायटी (एमएसएफडीएस) तथा फ़िल्म समारोह निदेशालय, के सहयोग से किया गया। यह समारोह 9 अप्रैल, 2021 से 9 अप्रैल, 2022 तक एकवर्ष चलने वाले मणिपुरी सिनेमा के स्वर्ण जयन्ती समारोह का एक भाग है।

2020 तथा 2021 के भारतीय सिनेमा के सर्वोत्तम शोकेस से सजे इस फ़िल्म समारोह में मणिपुर फ़िल्मों के मास्टर फ़िल्ममेकर अरिबम श्याम शर्मा की दुर्लभ फ़िल्मों का पश्चावलोकन शामिल है। 35 एमएम तथा 16 एमएम की *'इमागी निंगथेम', 'ओलंगथागी वांगबडासु' 'सनाबी'* तथा *'इशानोउ'* उनकी अन्य समालोचक जानी-पहचानी डाक्यूमेन्टरी तथा लघु फ़िल्मों के साथ प्रदर्शित होना है।

फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं के सहयोग से अन्य समारोहों का आयोजन

उपरोक्त वर्णित प्रमुख गतिविधियों के अलावा डीएफएफ ने विभिन्न क्षेत्रीय संस्थाओं के सहयोग से पूरे देश में फ़िल्म समारोहों का आयोजन किया। डीएफएफ ने निम्नलिखित समारोहों में भारतीय पैनोरमा/राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के क्यूरेटेड पैकेज के साथ समारोहों में गैर-व्यावसायी स्क्रीनिंग की।

आईआईसी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स 2021 : अक्टूबर 22, 2021 से अक्टूबर 26, 2021 तक इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर (आईआईसी) ने अपने वर्षिक 'फेस्टिवल ऑफ ऑर्ट्स 2021' का आयोजन किया। आईआईसी के विशेष अनुरोध पर डीएफएफ ने फ़िल्मों का एक पैकेज समारोह के दौरान

52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्ज्वलन

52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह की झलकियां

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सुश्री सुमनलता, संसद सदस्य तथा श्री प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा बीआरआईसीएस (ब्रिक्स) जूरी का अभिनंदन करते हुए।

इंडियन पैनोरमा जूरी का प्रस्तुतीकरण तथा सम्मान

स्क्रीनिंग के लिए उपलब्ध कराया।

इन्टरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला : तीन दिवसीय सातवां इन्टरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला हिमालयन वेलासिटी द्वारा भाषा, कला तथा संस्कृति के सहयोग से आयोजित किया गया। शिमला अथॉरिटीज के विशेष अनुरोध पर डीएफएफ ने फ़िल्मों का एक पैकेज समारोह के दौरान स्क्रीनिंग के लिए उपलब्ध कराया।

पटना चिल्ड्रेन फ़िल्म फेस्टिवल 2021 : नवम्बर 13, 2021 से नवम्बर 14, 2021 तक बिहार म्यूजियम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सहयोग से दो दिवसीय 'पटना चिल्ड्रेन फ़िल्म फेस्टिवल 2021' का आयोजन किया गया। डीएफएफ ने प्रेरणाप्रद तथा बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विजेता फ़िल्में यथा *तारे ज़मीन पर* तथा *आई एम कलाम* समारोह के दौरान स्क्रीनिंग के लिए उपलब्ध कराया।

झारखंड अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह : रांची में अक्टूबर 29, 2021 से अक्टूबर 30, 2021 तक रेडियो खान्ची, पत्रकारिता तथा जन संचार विभाग, रांची विश्वविद्यालय तथा झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) के संयुक्त तत्वाधान में चौथा झारखंड अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह आयोजित किया गया।

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड

फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड को केन्द्र सरकार द्वारा सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत गठित किया गया। बोर्ड अपने मुंबई स्थिति मुख्यालय एवं मुम्बई, चेन्नेई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी स्थित नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है।

प्रमाणन संबंधी कार्य

कोविड–19 महामारी के कारण पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष फ़िल्मों के निर्माण में कमी आई जिसके कारण प्रमाणन के आंकड़ों में भी कमी आई। हालांकि वर्ष 2020–21 की पहली तीन तिमाहियों की तुलना में 2021–22 की पहली तीन तिमाहियों में 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जो इस तथ्य का द्योतक है कि भारत में फ़िल्म निर्माण में सुधार हुआ है।

फ़िल्मों का प्रमाणन				
	1.4.2018 से 31.12.2018	1.4.2019 से 31.12.2019	1.4.2020 से 31.12.2020	1.4.2021 से 31.12.2021
भारतीय दीर्घ फ़िल्में	2,434	2,554	1,574	2,391
विदेशी दीर्घ फ़िल्म	706	906	650	528
भारतीय लघु फ़िल्में	13,272	12,154	2,946	5,840
विदेशी लघु फ़िल्में	602	655	99	355
योग	**17,014**	**16,269**	**5,269**	**9,114**

अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान बोर्ड ने कुल **9,114** प्रमाणपत्र जारी किए। इनमें से शून्य प्रमाणपत्र सेल्युलॉइड फ़िल्मों, **4,561** प्रमाणपत्र वीडियो फ़िल्मों तथा **4,553** प्रमाणपत्र डिजिटल फ़िल्मों के लिए जारी किए गए। अप्रैल से दिसम्बर 2021 के दौरान भारतीय दीर्घ (फीचर लेंथ, प्रत्येक 72 मिनट से ज्यादा) फ़िल्मों को जारी कुल प्रमाणपत्रों की संख्या **2,391** थी जबकि इसी अवधि में वर्ष 2020 में **1,574** प्रमाणपत्र जारी हुए थे।

डिजिटल

अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान बोर्ड ने **4,553** प्रमाणपत्र डिजिटल फ़िल्मों के लिए जारी किए गए। इनमें से **1,422** प्रमाणपत्र भारतीय दीर्घ फ़िल्मों को, **137** विदेशी दीर्घ फ़िल्मों को, **2,760** भारतीय लघु फ़िल्मों को तथा **234** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए थे।

वीडियो

इसी प्रकार **4,561** प्रमाणपत्रों में से **969** प्रमाणपत्र भारतीय दीर्घ फ़िल्मों को, **391** विदेशी दीर्घ फ़िल्मों को, **3,080** भारतीय लघु फ़िल्मों को तथा **121** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए थे।

आवेदकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सी.बी.एफ.सी. द्वारा अनेक पहलें की गईं तथा तन्त्र में सुव्यवस्थित सुधार किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से चार विभिन्न आवेदन प्रपत्रों को एक द्विभाषी आवेदन प्रपत्र में परिवर्तित करना रहा। साथ ही प्रमाणन में चरणों को कम करना जिसमें ई-सिनेप्रमाण पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड हेतु संपादक की भूमिका को समाप्त करना तथा संशोधनों की जांच करना एवं वीडियो फ़िल्मों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग हेतु प्रावधान करना रहा।

बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्मों का समेकित विवरण
(01.04.2021 से 31.12.2021)

वीडियो								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	योग
भारतीय फीचर फ़िल्में	159	84	404	305	11	6	–	969
विदेशी फीचर फ़िल्में	65	5	246	67	4	4	–	391
भारतीय लघु फ़िल्में	2,170	25	791	59	32	3	–	3,080
विदेशी लघु फ़िल्में	17	–	101	–	3	–	–	121
योग (बी)	**2,411**	**114**	**1,542**	**431**	**50**	**13**	–	**4,561**

डिजिटल								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	योग
भारतीय फीचर फ़िल्में	343	162	272	511	42	92	–	1,422
विदेशी फीचर फ़िल्में	18	–	65	9	33	12	–	137
भारतीय लघु फ़िल्में	2,109	16	552	54	24	5	–	2,760
विदेशी लघु फ़िल्में	59	–	170	2	3	–	–	234
योग (सी)	**2,529**	**178**	**1,059**	**576**	**102**	**109**	**–**	**4,553**
महायोग (ए+बी+सी)	**4,940**	**292**	**2,601**	**1,007**	**152**	**122**	**–**	**9,114**

*कट्स के साथ

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्र अनुसार- भाषा अनुसार (डिजिटल)

क्रम संख्या	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	तेलुगु	4	–	19	229	5	2	–	–	–	259
2	कन्नड़	4	–	2	7	191	2	–	–	–	206
3	मलयालम	3	–	6	8	–	158	–	–	–	175
4	तमिल	4	–	148	15	1	3	–	–	–	171
5	हिन्दी	99	5	2	5	1	2	12	1	2	129
6	भोजपुरी	112	5	–	–	–	–	2	–	–	119
7	बांग्ला	3	78	–	–	–	–	–	–	–	81
8	मराठी	75	–	–	–	–	–	–	–	–	75
9	पंजाबी	28	–	–	–	–	–	9	–	–	37
10	गुजराती	37	–	–	–	–	–	–	–	–	37
11	उड़िया	–	–	–	–	–	–	–	30	–	30
12	आसामी	–	–	–	–	–	–	–	–	23	23
13	मणिपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	20	20
14	छत्तीसगढ़ी	1	–	–	–	–	–	–	9	–	10
15	अंग्रेज़ी	4	2	2	–	–	1	–	–	–	9

क्रम संख्या	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
16	तुलू	–	–	–	–	5	–	–	–	–	5
17	मैथिली	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
18	बंजारा	–	–	–	2	2	–	–	–	–	4
19	हिंग्लिश	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
20	कोंकणी	1	–	–	–	2	–	–	–	–	3
21	राजस्थानी	2	–	–	–	–	–	1	–	–	3
22	संस्कृत	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
23	नेपाली	.	2	–	–	–	–	–	–	–	2
24	हरियाणवी	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
25	कोडावा	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
26	इरुला	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
27	साइलेन्ट	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
28	मिशिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
29	नागपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
30	उर्दू	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
31	गढ़वाली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
32	हाजोंग	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
33	कुरुम्बा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
34	माघी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
35	राभा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
36	बियरी (ब्यारी)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	कुल योग	**385**	**93**	**179**	**266**	**211**	**172**	**27**	**40**	**49**	**1,422**

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण थीमेटिक वर्गीकरण (डिजिटल)

क्रम संख्या	थीमेटिक वर्गीकरण	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	फीचर	137	40	56	137	49	36	15	10	5	485
2	सोशल	121	20	35	39	73	49	2	23	43	405

3	अन्य	61	26	28	77	20	43	7	1	–	263
4	एक्शन / थ्रिलर	23	1	27	1	17	21	3	2	–	95
5	कामेडी / व्यंग्य	13	–	7	6	19	2	–	2	–	49
6	क्राइम	4	1	15	4	4	2	–	1	–	31
7	हॉरर	5	1	11	2	4	1	–	–	–	24
8	बाल फ़िल्म	3	–	–	–	16	5	–	–	–	24
9	बॉयोग्राफिकल	11	–	–	–	2	–	–	1	–	14
10	फैन्टेसी / एडवेन्चर	1	–	–	–	–	8	–	–	1	10
11	डॉक्यूमेन्ट्री	2	3	–	–	–	3	–	–	–	8
12	हिस्टॉरिकल	3	1	–	–	3	1	–	–	–	8
13	माइथोलॉजिकल / डिवोशनल	1	–	–	–	3	–	–	–	–	4
14	साइन्टिफिक	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
	कुल योग	**385**	**93**	**179**	**266**	**211**	**172**	**27**	**40**	**49**	**1,422**

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार - देश अनुसार (डिजिटल)

क्रम संख्या	मूल देश	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	फ्रांस	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
2	जर्मनी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
3	हंगरी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
4	सिंगापुर	3	–	–	–	–	–	2	–	–	5
5	यूनाइटेड किंगडम	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2
6	अमेरिका	119	7	–	–	–	–	.	–	–	126
	कुल योग	**127**	**7**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**137**

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण

थीमेटिक वर्गीकरण (डिजिटल)

क्रम संख्या	थीमेटिक वर्गीकरण	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	फीचर	58	5	–	–	–	–	–	–	–	63
2	एक्शन/ थ्रिलर	24	–	–	–	–	–	2	–	–	26
3	फैन्टेसी/ एडवेन्चर	18	–	–	–	–	–	–	–	–	18
4	अन्य	13	2	–	–	–	–	–	–	–	15
5	हॉरर	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
6	कामेडी/व्यंग्य	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
7	क्राइम	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
8	बाल फ़िल्म	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
9	डॉक्यूमेन्ट्री	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
10	हिस्टॉरिकल	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	कुल योग	**127**	**7**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**137**

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार - भाषा अनुसार (वीडियो)

क्रम संख्या	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	हिन्दी	211	1	–	1	–	–	21	1	–	235
2	तमिल	3	61	–	65	3	7	–	–	–	139
3	मलयालम	–	65	–	40	.	31	–	–	–	136
4	कन्नड़	15	35	–	53	27	1	–	–	–	131
5	तेलुगु	1	74	–	20	1	1	–	–	–	97
6	भोजपुरी	74	–	–	–	–	–	1	1	–	76
7	मराठी	42	–	–	–	–	–	1		–	43
8	हिन्दुस्तानी	5	–	–	–	–	–	20	1	–	26
9	गुजराती	22	–	–	–	–	–	1	–	–	23

10	उड़िया	2	–	–	–	–	–	1	12	–	15
11	बांग्ला	8	–	5	–	–	–		1	–	14
12	पंजाबी	3	–	–	–	–	–	6	–	–	9
13	अवधी	6	–	–	–	–	–	1	1	–	8
14	उर्दू	7	–	–	–	–	–	1	–	–	8
15	मणिपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
16	अंग्रेज़ी	–	1	–	–	–	.	1	–	–	2
17	हिंगलिश	2	–	–	–	–	–		–	–	2
18	पहाड़ी / हिमाचली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
19	संस्कृत	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	**401**	**238**	**5**	**179**	**31**	**40**	**55**	**17**	**3**	**969**

1.4.2021 से 31.12.2021 की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी दीर्घ (फीचर लेंथ) फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार - देश अनुसार (वीडियो)

क्रम संख्या	मूल देश	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरु-वनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल योग
1	अमेरिका	284	1	–	4	–	3	2	–	–	294
2	चीन	19	8	–	–	–	–	–	–	–	27
3	हांगकांग	13	–	–	–	–	–	–	–	–	13
4	यूनाइटेड किंगडम	11	–	–	–	–	–	–	–	–	11
5	जापान	11	–	–	–	–	–	–	–	–	11
6	फ्रांस	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8
7	हंगरी	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8
8	डेनमार्क	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
9	दक्षिण कोरिया	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
10	मंगोलिया	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
11	आइसलैन्ड	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
12	नेपाल	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13	नीदरलैन्ड	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1

14	उत्तरी कोरिया	1		–	–	–	–	–	–	–	1
15	रुस	1		–	–	–	–	–	–	–	1
16	स्पेन	1		–	–	–	–	–	–	–	1
17	स्विटजरलैन्ड	1		–	–	–	–	–	–	–	1
18	ताइवान	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
19	कनाडा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
20	बेलारुस	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	कुल योग	**371**	**11**	**–**	**4**	**–**	**3**	**2**	**–**	**–**	**391**

बोर्ड की वित्त व्यवस्था

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बोर्ड और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में फ़िल्मों के प्रमाणन के शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा राजस्व प्राप्ति का प्रावधान है। बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्रों में फ़िल्मों की स्क्रीनिंग का शुल्क भी लेता है। 1.4.2021 से 31.12.2021 के दौरान बोर्ड की कुल आय **9,10,39,303** रुपये हुई जो भारत की समेकित निधि में जमा कर दी गई। बोर्ड का इस मद के लिए कोई बैंक खाता नहीं है।

बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय से गैर-योजना शीर्ष एवं इन्हीं उप-शीर्षों में किए व्यय के तहत अनुदान प्राप्त करता है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक बोर्ड के व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है-

बजट आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

	गैर योजना बीई (2020-21)	संशोधित/रिड्यूस्ड आवंटन अनुमानित आरई के अनुसार	दिसम्बर, 2021 तक व्यय
वेतन	484.00	500.00	326.44
मेडिकल	11.00	11.00	3.52
डीटीई	22.00	7.50	7.00
ओई	340.00	121.90	112.28
पीपीएसएस	400.00	390.00	235.46
रेन्ट रेट्स एवं टैक्सेस	35.00	11.00	5.81
अन्य प्रशासनिक व्यय	25.00	19.10	15.74
सूचना तकनीकी	07.00	03.00	2.72
एसएपी	09.00	1.50	1.49
योग	**1,333.00**	**1,065.00**	**710.46**

NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना, राष्ट्रीय आर्थिक नीति एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत एवं सक्षम विकास की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने एवं क्रियान्वित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई। 1980 में फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (इम्पेक) का विलय कर एनएफडीसी की पुनः स्थापना की गई। स्थापना के बाद से एनएफडीसी 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों का निर्माण अथवा उनके निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करा चुका है। इनमें से कई फ़िल्मों को व्यापक सराहना मिली है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं।

फ़िल्म निर्माण के अतिरिक्त एनएफडीसी सरकारी एजेन्सियों के लिए समेकित विपणन का सम्पूर्ण समाधान भी उपलब्ध कराता है तथा विज्ञापनों, वृत्तचित्रों, लघु फ़िल्मों, टीवी सीरीज, वेब विज्ञापनों, रेडियो सीरीज तथा विषयगत संगीत एन्थेम भी निर्मित करता है।

मीडिया इकाइयों का विलय:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड के साथ विलय करने का फैसला किया अर्थात्, फ़िल्म प्रभाग (एफडी), भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) ज्ञापन का विस्तार करके और एनएफडीसी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स (एमओएए), जो उसके बाद अब तक की सभी गतिविधियों को अंजाम देंगे, उनके द्वारा किया गया और सभी परिणामी कार्रवाई/कार्रवाई, जिसमें शामिल हैं एफडी/एनएफएआई/डीएफएफ/सीएफएसआई को बंद करना।

हाइलाइट

1. भारतीय फ़िल्म निर्माण (आईएफपी)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ''विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्म निर्माण'' उप योजना के तहत निगम **'डेवलपमेन्ट कम्युनिकेशन एन्ड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कन्टेंट' (डीसीडीएफसी)** योजना को निष्पादित करता है। इस योजना के तहत फ़िल्म निर्माण के लिए अपने प्रचलित दिशानिर्देशों के अंतर्गत एनएफडीसी फ़िल्मों का निर्माण एवं सह-निर्माण करता है। इसके जरिए अपनी पहली फ़िल्म बना रहे फ़िल्मकारों को प्रोत्साहित करने के लिए शत प्रतिशत योगदान निगम द्वारा किया जाता है तथा भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के फ़िल्म निर्माताओं द्वारा अच्छी गुणवत्ता की फ़िल्मों के निर्माण के लिए सह-निर्माण में भागीदारी निगम द्वारा की जाती है। 12वीं के दौरान शुरू की गई डीसीडीएफसी योजना पंचवर्षीय योजना (2012-17) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। 759.7 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ। योजना के प्रमुख घटक हैं:

- भारत और विदेश में फ़िल्म समारोह और फ़िल्म बाजार के माध्यम से भारतीय सिनेमा का प्रचार
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में वृत्तचित्र फ़िल्मों और फ़िल्मों का निर्माण
- फ़िल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फ़िल्म प्रभाग)
- अभिलेखीय फ़िल्मों और फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण
- फ़िल्म सुविधा कार्यालय
- दृश्य श्रव्य सह-उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
- भारत में विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन
- वैश्विक मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन

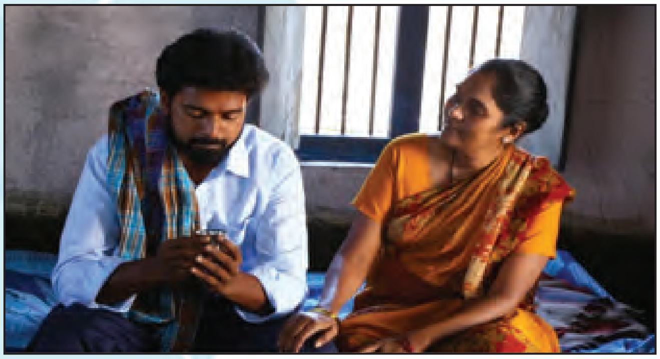

'कोरान्नी नुन्छी' (तेलुगु फ़िल्म)

'छाड' (बंगाली फ़िल्म)

डीसीडीएफसी योजना के अंतर्गत फ़िल्मों का निर्माण/सह-निर्माण

1. श्री के. जयदेव द्वारा निर्देशित तेलुगु फ़िल्म *'कोरान्नी नुन्छी'* – फ़िल्म का निर्माणोपरान्त कार्य पूरा किया जा चुका है तथा फ़िल्म को सेन्सर प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
2. सुश्री इन्द्राणी चक्रबर्ती द्वारा निर्देशित बांग्ला फ़िल्म 'छाड' की शूटिंग पूरी हो चुकी है तथा फ़िल्म पोस्ट प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है।
3. एनएफडीसी भारत सरकार का एक निकाय तथा **फ़िल्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, बांग्लादेश** ने ''बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान'' के जीवन पर बनी एक बांग्ला फीचर फ़िल्म ***''बंगबन्धु''*** का सह-निर्माण किया है जहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार फ़िल्म के निर्माता हैं।
4. मणिपुरी फीचर फ़िल्म ***जोसेफ की माचा*** एक साहसिक ड्रामा है जिसमें अन्य प्रमुख अदाकारों के साथ-साथ प्रमुख भूमिका में पद्‌म श्री पुरस्कार विजेता गुरु र्‌यूबेन माशांग्या हैं। इसकी पहली शूटिंग पूरी हो चुकी है।
5. श्री अमित दत्ता द्वारा निर्देशित हिन्दी फ़िल्म ''पेड़ पे कमरा'' के सह-निर्माता के साथ निगम एक एग्रीमेन्ट करेगा।

2. वितरण, सिंडीकेट प्रबंधन एवं ओटीटी

वितरण विभाग को सात प्रमुख अंगों थिएटर वितरण, सिंडीकेशन, भारतीय ओटीटी के सिनेमा, निर्यात, संगीत वितरण तथा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव एवं मार्केटिंग में बांटा गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म **www.cinemasofndia.com** वर्ष भर एनएफडीसी की फ़िल्मों का प्रसारण करता है और दुनिया में किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता है।

स्वतन्त्र सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए, निगम द्वारा वर्ष 2012 में भारत के सिनेमा (वीओडी प्लेटफॉर्म), भारत में फ़िल्मों के वितरण के लिए स्थायी तन्त्र का विकास करने के उद्देश्य से, प्रारम्भ किया। इसमें एनएफडीसी निर्मित फ़िल्मों के साथ साथ अन्य स्वतन्त्र फ़िल्मकारों की उन फ़िल्मों को भी शामिल किया गया है जिनकी घरेलू बाज़ारों में सीमित पहुंच है। 21 भारतीय भाषाओं में 85 टाइटल पुर्ननिर्मित करने के साथ 300 से अधिक फ़िल्में इसमें हैं। एनएफडीसी के वितरण विभाग ने 100 फ़िल्मों से अधिक का एक कैटलॉग तैयार किया है जिसमें प्रीमियम तथा विशिष्ट फ़िल्में शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा पहचान हासिल की है। इस लाइब्रेरी में हिन्दी तथा भारतीय क्षेत्रीय भाषाई फ़िल्में शामिल हैं।

थिएटर वितरण

1. वितरण विभाग ने श्री जी.वी. अय्यर द्वारा संस्कृत, हिन्दी तथा तमिल में निर्देशित फीचर फ़िल्म ***आदि शंकराचार्य*** के दूरदर्शन तथा डीडी भारती चैनलों पर प्रसारण में सहयोग दिया।

डिजिटल

1. एनएफडीसी की फ़िल्में साझेदार प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो, एपिक ऑन तथा नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही हैं। एनएफडीसी की फ़िल्में रिलायन्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर भी देख जा सकेगा।
2. एनएफडीसी की फ़िल्में एमयूबीआई (मूबी), पर भी उपलब्ध हैं जो कि विश्व स्तर पर स्वतन्त्र क्लासिक कृतियों के प्रोग्राम तथा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक

प्रमुख लोकप्रिय एवं जाना माना नाम है। जुलाई 2021 में प्लेटफॉर्म पर 24 शीर्षकों को रि-लाइसेन्स किया गया।

विमान के भीतर (इन-फ्लाइट)

1. एनएफडीसी का पुराना इन-फ्लाइट सहयोगी कन्टेनटिनो मीडिया एलएलपी, निगम को विमानन कम्पनियों के द्वारा वांछित सामग्री हेतु सहयोग करता रहेगा। इस सम्बन्ध में सितम्बर, 2021 में एक परिशिष्ट को औपचारिक रूप दिया गया।

सिनेमाज ऑफ इंडिया का वीडियो ऑन डिमांड - ओटीटी प्लेटफॉर्म

प्रसिद्ध फ़िल्मकार सत्यजित रे का शताब्दी समरोह मनाने के क्रम में **सत्यजित रे फ़िल्म फेस्टिवल** www.cinemasofindia.com पर मई, 2021 के दौरान आयोजित किया गया। इसमें कुल 6 फ़िल्में, जिनमें 3 निर्देशक क्लासिक आगन्तुक *(द स्ट्रेन्जर), गणशत्रु (एनेमी ऑफ द प्यूपिल), घरे बाइरे (द होम ऐंड द वर्ल्ड), सन्दीप रॉय की उत्तोरन (द ब्रोकेन जर्नी)* के साथ-साथ वृत्त फीचर म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे, निर्देशक उत्पलेन्दु चक्रबर्ती और नेमाई घोष, ए रे ऑफ लाइट- अनिरबन मित्रा तथा तीर्थो दास गुप्ता द्वारा, प्रदर्शित की गईं। एनएफडीसी ने **इंडिपेंडेंस डे फ़िल्म फेस्टिवल** का आयोजन फ़िल्म *गांधी (विभिन्न भारतीय भाषाओं में), द मेकिंग ऑफ द महात्मा (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी) तथा घरे बाइरे (बांग्ला)* **www.cinemasofindia.com** पर 15 से 21 अगस्त, 2021 के बीच आयोजित किया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, 23 से 29 अगस्त, 2021 के दौरान, आइकॉनिक वीक समारोह, 2021 का आयोजन किया गया। आधुनिक भारत तथा पिछले वर्षों में फ़िल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति पर आधारित फ़िल्में इस अवधि के दौरान एनएफडीसी के ओटीटी प्लेटफॉर्म **www.cinemasofindia.com** पर दिखाई गईं।

पिछले सालों में एनएफडीसी ने विभिन्न लाइसेन्सरों, संघों, कन्टेंट प्लेटफॉर्मों तथा टेलीविजन प्रसारकों के साथ भागीदारी जारी रखी है। हाल में एनएफडीसी ने निम्नलिखित भागीदारों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक विक्रय भागीदारी जारी रखी है-

1. एनएफडीसी के वितरण विभाग ने रिलायन्स जियो सिनेमा के साथ 90 फ़िल्मों की सब्सक्रिप्शन आधारित स्ट्रीमिंग ओटीटी सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में समझौता किया है। एनएफडीसी फ़िल्मों की जियो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग 2021-22 तक रहेगी।

2. एनएफडीसी के वितरण विभाग ने मारीशस ब्राडकॉस्टिंग कारपोरेशन (एमबीसी), जो कि मारीशस का राष्ट्रीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, के साथ अपने हिन्दी भाषी सह-निर्माण *अंग्रेज़ी में कहते हैं,* का सह-संयोजन किया है जो कि 2022-23 तक प्रसारित होता रहेगा।

3. एनएफडीसी ने जेनस फ़िल्म जो कि अब क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, के साथ *पाथेर पांचाली* तथा सत्यजीत रे के अन्य शीर्षकों – *आगंतुक, घरे बाइरे, गणशत्रु* का करार अमेरिकी, कनाडा, न्यूजीलैन्ड, आयरलैन्ड तथा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के लिए नवीनीकृत किया।

4. *सूर्या फ़िल्म्स, मलेशिया*– ब्रुनेई तथा मलेशिया क्षेत्र के लिए एनएफडीसी की प्रतिष्ठित फ़िल्म गांधी।

5. *एमयूबीआई* – यूनाइटेड किंगडम आधारित एसवीओडी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर फ़िल्मों की स्ट्रीमिंग 2022 तक की जाती रहेगी।

6. *रॉटरडैम का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह* – आईएफएफआर – इस समारोह के दौरान पश्चावलोकन की शृंखला में मणि कौल की *उसकी रोटी* अनलीश्ड प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर यह फ़िल्म 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

फ़िल्म समारोह तथा बाज़ार

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, फ़िल्म समारोह तथा बाज़ार ऑनलाइन रुप में आयोजित किए गए तथा एनएफडीसी ने भी मार्श डु कान तथा अमेरिकी फ़िल्म मार्केट, 2021 के ऑनलाइन एडीशन में भागीदारी की।

- **स्टुटगार्ट मीट्स मुम्बई (ऑनलाइन इवेन्ट) – सेलेब्रेटिंग इंडियन सिनेमा 18वां भारतीय फ़िल्म समारोह, स्टुटगार्ट**

  भारतीय माननीय कौन्सुलेट स्टुटगार्ट ने एनएफडीसी को अपने वेबिनार, सेलेब्रेटिंग इंडियन सिनेमा: 18वां भारतीय फ़िल्म समारोह, स्टुटगार्ट, जो कि 22-28 फरवरी, 2021 को ऑनलाइन आयोजित हुआ, में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया।

- **हांगकांग-एशिया फ़िल्म फाइनैन्सिंग फोरम (एचएएफ)**

  फ़िल्म मार्ट, हांगकांग के फ़िल्म मार्केट के दौरान 15 से 18 मार्च 2021 के आयोजन में एनएफडीसी ने

हांगकांग–एशिया फ़िल्म फ़ाइनैन्सिंग फ़ोरम के ऑनलाइन सत्र में भागीदारी की।

- **मार्श डु फ़िल्म (कान्स फ़िल्म बाजार)**

6 से 15 जुलाई, 2021 के दौरान आयोजित मार्श डु फ़िल्म (कान्स फ़िल्म बाजार) में फ़िल्म बाज़ार के निदेशक ने भागीदारी की तथा भविष्य की संभावनाओं एवं संभव सहयोग के विषय पर अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स के साथ कई बैठकें की।

- **72वां बर्लिन यूरोपियन फ़िल्म बाजार**

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 72वें बर्लिन यूरोपय फ़िल्म बाजार 2022 में भारतीय पवेलियन का आभासी उद्घाटन 10.02.2022 को हुआ। भारतीय पवेलियन 17.02.2022 तक लाइव रहा और आज़ादी का अमृत महोत्सव और सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव तथा अन्य का प्रदर्शन किया। फ़िल्म सुविधा कार्यालय ने अपनी पहल 'भारत में फ़िल्म' को बढ़ावा देने के लिए ईएफएम 2022 में भाग लिया।

- **मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव**

17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव दक्षिण एशिया में गैर-फीचर फ़िल्मों के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसका आयोजन 29 मई से 4 जून, 2022 तक फ़िल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, वर्तमान संस्करण ने इंडिया @75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की स्थापना की है।

आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा सत्यजित रे शताब्दी समारोह के वैश्विक स्तर पर हुई स्क्रीनिंग्स –

1) जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित **डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर (2000)** की स्क्रीनिंग भारतीय ऑडिटोरियम, जकार्ता, इंडोनेशिया में 14 अप्रैल, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान प्रदर्शित हुई।

2) **विश्व दुग्ध दिवस** के अवसर पर एनएफडीसी ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित **मंथन (1976)** का प्रदर्शन अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म www.cinemasofindia.com पर किया।

3) 23वें शंघाई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह, शंघाई में 11-20 जून, 2021 के दौरान सत्यजित रे द्वारा निर्देशित ***पांथेर पांचाली* (1955)** की स्क्रीनिंग की गई।

4) 21वें न्यूयार्क भारतीय फ़िल्म समारोह, न्यूयार्क, 2021 में 4-13 जून, 2021 के दौरान उत्पलेन्दु चक्रबर्ती द्वारा निर्देशित **म्यूजिक ऑफ सत्यजित रे (1984)** की स्क्रीनिंग की गई।

5) 10वें साउथ एशियाई फ़िल्म समारोह, टोरन्टो, 2021 में 12-22 अगस्त, 2021 के दौरान सत्यजित रे द्वारा निर्देशित ***घरे बाइरे* (1954)** की स्क्रीनिंग की गई।

6) 70वें मैनहेम अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह, हेडेलबर्ग में 11-21 नवम्बर, 2021 के दौरान सत्यजित रे द्वारा निर्देशित ***पाथेर पांचाली* (1955)** की स्क्रीनिंग की गई।

7) सत्यजित रे फ़िल्म्स को हांगकांग इंटरनेशनल फ़िल्म समारोह सोसायटी लिमिटेड को उनके समारोह के लिए सुविधा प्रदान की, जो सिंतबर-अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था।

एनएफडीसी लैब तथा फ़िल्म बाज़ार

(i) **एनएफडीसी स्क्रिप्ट राइटर्स लैब** स्थापित भारतीय फ़िल्म निर्माताओं के प्रोफेशनल विकास के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। इसकी संरचना में स्क्रिप्ट लेखन के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय उद्योग एक्सपर्ट को फीडबैक तथा मेन्टरशिप उपलब्ध कराना है।

(ii) **मराठी स्क्रिप्टराइटिंग कैम्प**

महाराष्ट्र फ़िल्म, स्टेज तथा सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड (एमएफएससीडीसी) के सहयोग से एनएफडीसी ने 4-5 माह की अवधि का **मराठी स्क्रिप्ट लेखन** कैम्प आयोजित किया। कुल 3 सत्रों में मराठी की 6 पटकथाएं चयनित हुई तथा क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा मेन्टर की गई।

(iii) **एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार**

20-25 नवम्बर, 2021 की नियमित तिथियों पर यह बाज़ार वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया। ऑनलाइन फ़िल्म बाज़ार के लिए एक अनोखा स्टेट ऑफ द आर्ट 3डी वर्चुअल पोर्टल निर्मित किया गया था जिसे पूरे विश्व में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा जो काफी

सफल रहा। 39 देशों से कुल 553 डेलीगेट्स ने इसमें भागीदारी की।

कमीशंड मीडिया प्रोडक्शन, नई दिल्ली

एनएफडीसी ने विभिन्न मंत्रालयों में विज्ञापनों के निर्माण एवं विज्ञापनीय संचार के प्रसार हेतु एक प्रमुख विश्वस्त समेकित मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में नाम कमाया है। कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित नए माहौल में एनएफडीसी ने अपनी सेवाओं का विविधीकरण एनएफडीसी ने वर्चुअल इवेन्ट्स तथा प्रदर्शनी, संवादपरक वीडियो आदि को आत्मसात किया जो कि सरकारी संचार को टू वे प्रक्रिया के रूप में स्थापित कर संदेशों की प्रभावकारिता में और वृद्धि करते हैं।

फ़िल्में

टोक्यो ओलम्पिक 2021 हेतु फ़िल्म शृंखला

टोक्यो ओलम्पिक वर्ष 2021 में, एनएफडीसी ने राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के साथ भागीदारी की तथा टोक्यो बाउन्ड एथलीट के प्रोफाइल से सम्बन्धित 40 डाक्यूमेन्ट्री के निर्माण का कमीशन किया। 14 अप्रैल, 2021 को माननीय खेल तथा युवा मामले राज्य मंत्री ने टोक्यो ओलम्पिक 2021 प्रारम्भ होने से 100 दिनों पूर्व ''ओलम्पिक की आशा'' शीर्षक समेकित प्रमोशनल फ़िल्म के जरिए काउन्टडाउन प्रारम्भ किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2021 के लिए एन्थेम

7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनएफडीसी ने आयुष मंत्रालय की भागीदारी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2021 के लिए एक संगीत आधारित वीडियो का निर्माण किया।

इस गाने को महाद्वीपों में शूट किया गया और इसमें 13 भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय गायकों ने भाग लिया।

15 अगस्त, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फ़िल्म शृंखला

संस्कृति मंत्रालय ने एनएफडीसी को विभिन्न थीम से सम्बन्धित 7 फ़िल्में बनाने का कार्य दिया जो आज़ादी के अमृत महोत्सव से सम्बन्धित थीं। यह एक सघन देशव्यापी अभियान था जिसमें नागरिक भागीदारी पर फोकस किया गया था जिसे जन आन्दोलन में परिवर्तित करने का संकल्प था जहां स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे परिवर्तनों को प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धि में परिवर्तित करने का उद्देश्य था।

आयोजन

प्रमुख रूप में एनएफडीसी ने सफलतापूर्वक अपने पहले मेगा हाइब्रिड इवेन्ट, द इंडिया इन्टरनेशनल साइन्स फेस्टिवल, 2021 को पूरा किया जो भू-विज्ञान मंत्रालय के एनसीपीओआर द्वारा में 10 से 13 दिसम्बर, 2021 के दौरान कमीशन किया गया। इस इवेन्ट की प्रमुख विशिष्टता 3 ***नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड*** थे जो निम्न श्रेणियों में रहे-

क. दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को सर्वाधिक लोगों द्वारा एकत्र होना तथा रॉकेट किट को लॉन्च करना

ख. दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 को सर्वाधिक लोगों द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किट्स को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एकत्र करना

ग. दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को सर्वाधिक लोगों द्वारा रेडियो टेलिस्कोप को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एकत्र करना

क्षेत्रीय कार्यालय - दक्षिण (कौशल विकास)

क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका - एनएफडीसी का दक्षिण एनएफडीसी के विज़न की प्रमुख तथा गौड़ गतिविधियों को आत्मसात कर दक्षिणी बाज़ार से सम्बन्धित अपने नियमित कार्यों का संपदान करता है। इन गतिविधियों में फ़िल्म निर्माण, फ़िल्म वितरण, सरकारी विज्ञापन हेतु मीडिया सामग्री का विकास, विदेशी फ़िल्मकारों को भारत में फ़िल्म शूटिंग के लिए सहयोग तथा संवर्द्धन हेतु फ़िल्म सहयोग कार्यालय तथा फ़िल्म बाज़ार का आयोजन शामिल है।

लोक सभा टीवी के जरिए वितरण

लोक सभा टीवी के साथ एमओयू के तहत एनएफडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रॉयल्टी आधार पर पुरस्कृत फ़िल्मों का टेलीकास्ट करती है। लोक सभा टीवी तथा राज्य सभा टीवी का संसद टीवी के रूप में दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को मर्जर के पश्चात फ़िल्मों का टेलीकास्ट शीघ्र ही प्रारम्भ होगा।

सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फन्ड ऑफ इंडिया

1991 में बने सबसे बड़े सिने आर्टिस्ट ट्रस्ट सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फन्ड ऑफ इंडिया (सीएडब्ल्यूएफआई) का प्रशासन एवं प्रबंधन एनएफडीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा किया जाता है।

फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

सरकार की ईज आफ डूइंग बिजनेस की नीति की निरन्तरता में फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना दिसंबर, 2015 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में फ़िल्म बनाने को इच्छुक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट (फीचर फ़िल्म, टीवी/ वेब शो तथा सीरीज़ तथा रिएलिटी टीवी/ वेब शो तथा सीरीज़) को सहयोग करना है। एफएफओ की सेवाएं 2019 से घरेलू फ़िल्मकारों को भी प्रदान की गईं।

पिछले 6 वर्षों के दौरान, अपने वेब पोर्टल www.ffo.gov.in को प्रारम्भ कर एफएफओ ने सफलतापूर्वक एक एकल खिड़की स्वीकृति सहायता तन्त्र की संरचना की है जिसका उद्देश्य पूरे देश में फिल्मिंग के लिए स्वीकृति प्रदान करना है। इसके जरिए भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के फ़िल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मिंग तथा शूटिंग हेतु प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इसमें भारत में फिल्मिंग हेतु स्वीकृतियों का समयबद्ध जारी किए जाने के साथ-साथ यह पोर्टल पूरे विश्व में फ़िल्मकरों के लिए भारत की एक पसंदीदा फिल्मिंग डेस्टीनेशन के बारे में जानकारी हेतु वन स्टॉप डिजिटल समाधान का कार्य करता है। सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग पृष्ठों वाले इस वेब पोर्टल में स्टेट नोडल ऑफिसर को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि विभिन्न घरेलू तथा विदेशी फ़िल्मकारों द्वारा फिल्मिंग की स्वीकृति हेतु उनके क्षेत्र में प्राप्त होने वाले आवेदनों तक सीधी पहुंच रख सकें।

भारत में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के सरकार की पहल के प्रयास के रूप में वेब पोर्टल को व्यापारिक मंजूरियों सम्बन्धी भारतीय नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) ''माध्यम'' से भी जोड़ा गया है। साथ ही एफएफओ वेब पोर्टल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा रेल मंत्रालय के साथ भी जोड़ा गया है जिससे फ़िल्मकारों को इनसे सम्बन्धित स्वीकृतियां प्राप्त करने में सरलता हो सके।

डिजिटल मीडिया

डिजिटल मीडिया एक मुद्रीकृत माध्यम है जो कि एनएफडीसी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदत्त वर्तमान चैनलों के मीडिया मिक्स को पोषित करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो भारत जैसे बड़े देश की विविध दर्शक क्षमता तक पहुंच हेतु प्रचुर माध्यम प्रदान करता है। डिजिटल मीडिया की पहुंच के लाभ स्वरूप विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों ने एनएफडीसी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के जरिए नागरिकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंच का विकल्प लिया है।

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के एक भाग के रूप में "संविधान का निर्माण" और फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी "चित्रांजलि@75" पर आभासी (वर्चुअल) फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर।

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को के महासम्मेलन के 21वें सत्र में संचार के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी और इसकी अंतर-सरकारी परिषद (आईजीसी) का सदस्य भी रहा है। इसके महासम्मेलन के 35वें सत्र में भारत को मौखिक मतदान के जरिए 2009-2013 की अवधि के लिए आईजीसी का सदस्य चुना गया था।

शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में यूनेस्को के साथ कार्य करने में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा 1949 में भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की गई थी। चार वर्ष बाद इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया।

आईएनसीसीयू के अधीन संचार तंत्र पर एक उप-कमीशन की बैठक 02.11.2021 को सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में यूनेस्को द्वारा संचार एवं सूचना क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एजेंडा पर विमर्श किया गया।

यूनेस्को की 41वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का चौथा सत्र 09.11.2021 से 24.11.2021 के दौरान पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व माननीय शिक्षा मंत्री ने किया तथा सूचना एवं संचार क्षेत्र पर 41वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने किया।

शंघाई सहयोग संगठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य राज्यों के तीसरे मास मीडिया फोरम में शिरकत की। ताज़िकिस्तान की अध्यक्षता में यह समारोह 6 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया। आयोजन का विषय 'एससीओ सदस्य राज्यों के मध्य परस्पर संवाद में मास मीडिया की भूमिका को सशक्त करने के लिए एससीओ मीडिया स्पेस सशक्त सहयोग भूमिका' था।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के दौरान मंत्रालय की भूमिका और आपसी सहयोग को मजबूत करने में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एससीओ के सदस्य राज्यों ने बिश्केक में 13-14 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए जिसकी पुष्टि 12.08.2021 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने की थी।

शंघाई सहयोग संगठन ने एसीओ फ़िल्म समारोह के नियामकों को साझा किया और इस संबंध में मंत्रालय ने अपनी विवेचना और सलाह को एससीओ फ़िल्म समारोह के अंतिम नियामकों में शामिल करने के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द किर्गिज़ रिपब्लिक, द रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ ताज़िकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ने किया था। शंघाई फाइव मैकेनिज़्म इसका पूर्ववर्ती संगठन है। शंघाई सहयोग संगठन काउंसिल के राष्ट्राध्यक्षों की ऐतिहासिक बैठक 8-9 जून, 2017 को अस्ताना में आयोजित हुई थी। बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया।

भारत-बांग्लादेश सहयोग

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) और बांग्लादेश के फ़िल्म विकास निगम ने आपसी सहयोग से एक फीचर फ़िल्म मुजीब - द मेकिंग ऑफ ए नेशन का निर्माण किया है। यह फ़िल्म बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित है। इसके निर्माता हैं, भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा बांग्लादेश का सूचना मंत्रालय। फ़िल्म का निर्माण पूरा होने के अवसर पर, 17 मार्च, 2022 को शेख मुजीबुर रहमान की 102वीं जयंती पर फ़िल्म का पोस्टर जारी किया गया था। फ़िल्म का निर्माण दोनों देशों के बीच ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन एग्रीमेंट के अंतर्गत किया गया है।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) फ़िल्म समारोह

गोवा में 20-28 नवंबर, 2021 के दौरान भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) के साथ ही पहली बार ब्रिक्स फ़िल्म समारोह का भी आयोजन किया गया। यह ब्रिक्स फ़िल्म समारोह का छठा संस्करण था जिस दौरान पांच सदस्य देशों, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की फ़िल्मों के विशेष पैकेज का प्रदर्शन किया गया। इस प्रतिस्पर्धात्मक समारोह के लिए गठित ज्यूरी में प्रत्येक देश से एक सदस्य शामिल था।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक हितों को सशक्त बनाने के लिए प्रसारण एवं मनोरंजन, जनसामान्य के बीच संपर्क सुदृढ़ करने और दोनों देशों के बीच सॉफ्ट पावर संभावना का पता लगाने के लिए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय डॉ. हसन महमूद के नेतृत्व में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने 7 सितंबर, 2021 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मुलाकात की।

भारत और वियतनाम के बीच आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 16 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वियतनाम के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गुयेन मान हंग के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। आशयपत्र में दोनों देशों के बीच डिजिटल मीडिया एवं सोशल नेटवर्क्स तथा मीडिया पेशेवरों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्षमता विकास से जुड़ी नीतियां एवं नियामक रूपरेखा की परिकल्पना तैयार की गई है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

भारत सकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों/अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए और संबंधों को सुदृढ़ करने के लक्ष्य एवं उद्देश्य से इन कार्यक्रमों/अनुबंधों के अंतर्गत भारत एवं अन्य देशों के बीच मीडिया, प्रसारण एवं फ़िल्म क्षेत्र में आदान-प्रदान पर जोर दिया जाएगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अमल में लाए जाने के लिए मंत्रालय की ओर से 24.09.2021 को भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच एक सीईपी पर हस्ताक्षर किए गए।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 16 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में दूरदर्शन पर 21 अगस्त से प्रसारित होने वाले 'रग रग में गंगा' के सीज़न 2 के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 25 सितंबर, 2021 को कारगिल युद्ध स्मारक, लद्दाख में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

अनुलग्नक-I

	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (पद पर कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व %)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व %)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व %)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अन्य (प्रतिनिधित्व %)
'ए'	4,285	1,779	270 (6.3)	119 (2.78)	125 (2.91)	1,265 (29.52)
'बी'	22,349	10,546	1,635 (7.31)	973 (4.35)	1,339 (5.99)	6,599 (29.52)
'सी'	24,796	11,600	2,549 (10.28)	1,651 (6.66)	1,440 (5.80)	5,960 (24.03)
'डी'	188	112	43 (22.87)	9 (4.79)	31 (16.48)	29 (15.42)
कुल	**51,618**	**24,037**	**4,497 (8.71)**	**2,752 (5.33)**	**2,935 (5.68)**	**13,853 (26.83)**

नोटः-विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का प्रतिशत (%) स्वीकृत संख्या के आधार पर निकाला गया है।

श्रेणी	क्रम. संख्या	कार्यालय	कुल कर्मचारी		अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अन्य की संख्या
			(स्वीकृत)	(वास्तविक)				
ए	1	मुख्य सचिवालय (भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों सहित)	639	475	65	34	46	330
	2.	प्रकाशन विभाग	16	3	2	0	0	1
	3.	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	13	4	0	0	0	4
	4.	फोटो प्रभाग	3	1	0	0	0	1
	5	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	27	6	2	1	1	2
	6.	बेसिल	116	56	13	1	8	34
	7.	पत्र सूचना कार्यालय	107	92	10	8	6	68
	8.	भारतीय प्रेस परिषद	9	6	1	1	0	4
	9.	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	35	11	3	0	1	7
	10.	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	35	27	1	0	0	26
	11.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	5	2	0	1	0	1
	12.	न्यू मीडिया विंग	5	2	0	0	0	2
	13.	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	4	2	0	0	0	2
	14.	भारतीय जन संचार संस्थान	34	16	2	1	1	12
	15	फ़िल्म समारोह निदेशालय	8	5	1	0	1	3
	16.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	10	7	1	1	0	5,
	17.	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	66	26	5	2	2	17
	18.	फ़िल्म प्रभाग	31	13	2	1	3	7
	19.	डीजीः ऑल इंडिया रेडियो	2,002	613	103	35	29	446
	20.	डीजीः दूरदर्शन	1,117	412	59	33	27	293
	21.	बाल चित्र समिति, भारत	3	0	0	0	0	0
		कुल	**4,285**	**1,779**	**270**	**119**	**125**	**1,265**

श्रेणी	क्रम. संख्या	कार्यालय	कुल कर्मचारी		अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अन्य की संख्या
			(स्वीकृत)	(वास्तविक)				
	1	मुख्य सचिवालय (भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों सहित)	618	413	54	24	100	235
	2.	प्रकाशन विभाग	70	38	12	3	1	22
	3.	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	24	12	2	0	2	8
	4.	फोटो प्रभाग	7	3	0	1	0	2
	5	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	148	78	15	2	17	44
	6.	बेसिल	15	4	0	0	0	4
	7.	पत्र सूचना कार्यालय	109	52	11	6	13	22
	8.	भारतीय प्रेस परिषद	27	19	5	0	2	12
	9.	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	20	13	4	0	3	6
	10.	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	29	17	1	0	2	14
बी	11.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	0	1	0	0	0	1
	12.	न्यू मीडिया विंग	14	3	1	0	0	2
	13.	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	3	1	0	0	0	1
	14.	भारतीय जन संचार संस्थान	36	15	5	1	1	8
	15.	फ़िल्म समारोह निदेशालय	10	4	1	0	1	2
	16.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	41	25	7	1	5	12
	17.	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	51	26	6	2	1	17
	18.	फ़िल्म प्रभाग	192	133	31	9	33	60
	19.	डीजीः ऑल इंडिया रेडियो	12,056	4,735	711	488	596	2,940
	20.	डीजीः दूरदर्शन	8,866	4,947	767	436	560	3,184
	21.	बाल चित्र समिति, भारत	13	7	2	0	2	3
		कुल	**22,349**	**10,546**	**1,635**	**973**	**1,339**	**6,599**

श्रेणी	क्रम. संख्या	कार्यालय	कुल कर्मचारी		अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अन्य की संख्या
			(स्वीकृत)	(वास्तविक)				
सी	1.	मुख्य सचिवालय (भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों सहित)	135	97	30	4	11	52
	2.	प्रकाशन विभाग	267	102	25	4	14	59
	3.	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	60	27	3	3	9	12
	4.	फोटो प्रभाग	68	27	5	1	7	14
	5.	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	1,469	839	172	110	178	379
	6.	बेसिल	41	3	0	0	0	3
	7.	पत्र सूचना कार्यालय	209	159	37	10	39	73
	8.	भारतीय प्रेस परिषद	51	45	7	5	4	29
	9.	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	56	30	8	0	9	13
	10.	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	42	33	15	1	5	12
	11.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	0	0	0	0	0	0
	12.	न्यू मीडिया विंग	23	7	3	0	0	4
	13.	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	20	8	1	0	2	5
	14.	भारतीय जन संचार संस्थान	82	40	9	1	11	19
	15.	फ़िल्म समारोह निदेशालय	25	12	7	0	0	5
	16.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	30	21	5	1	3	12
	17.	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	196	71	16	15	8	32
	18.	फ़िल्म प्रभाग	243	145	29	8	46	62
	19.	डीजीः ऑल इंडिया रेडियो	12,071	5,453	1,251	808	495	2,899
	20.	डीजीः दूरदर्शन	9,679	4,460	920	678	591	2,271
	21.	बाल चित्र समिति, भारत	29	21	6	2	8	5
		कुल	**24,796**	**11,600**	**2,549**	**1,651**	**1,440**	**5,960**

श्रेणी	क्रम. संख्या	कार्यालय	कुल कर्मचारी		अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अन्य की संख्या
			(स्वीकृत)	(वास्तविक)				
डी	1.	मुख्य सचिवालय (भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों सहित	0	0	0	0	0	0
	2.	प्रकाशन विभाग	0	0	0	0	0	0
	3.	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	1	0	0	0	0	0
	4.	फोटो प्रभाग	0	0	0	0	0	0
	5.	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	0	0	0	0	0	0
	6.	बेसिल	16	6	3	0	0	3
	7.	पत्र सूचना कार्यालय	0	0	0	0	0	0
	8.	भारतीय प्रेस परिषद	0	0	0	0	0	0
	9.	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	6	0	0	0	0	0
	10.	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	0	0	0	0	0	0
	11.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	0	0	0	0	0	0
	12.	न्यू मीडिया विंग	0	0	0	0	0	0
	13.	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	22	10	2	2	2	4
	14.	भारतीय जन संचार संस्थान	0	0	0	0	0	0
	15.	फ़िल्म समारोह निदेशालय	0	0	0	0	0	0
	16.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	0	0	0	0	0	0
	17.	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	0	0	0	0	0	0
	18.	फ़िल्म प्रभाग	143	96	38	7	29	22
	19.	डीजीः ऑल इंडिया रेडियो	0	0	0	0	0	0
	20.	डीजीः दूरदर्शन	0	0	0	0	0	0
	21.	बाल चित्र समिति, भारत	0	0	0	0	0	0
		कुल	**188**	**112**	**43**	**9**	**31**	**29**
		कुल योग	**51,618**	**24,037**	**4,497**	**2,752**	**2,935**	**13,853**

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 25 सितंबर, 2021 को कारगिल, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन हम्बोटिंग ला में हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन करते हुए।

9 सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर सभी मीडिया इकाइयों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालयों को कड़े तौर पर अमल में लाने के आदेश तथा दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मंत्रालय में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने की विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 01/01/2022 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं तरक्की कोटा नीचे दिया गया है-

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट-I

कार्यक्षेत्र में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका

वर्ष 2021 के लिए (01/01/2022 तक)

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पद	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
समूह क	3,172	49	06	04	09	00	00
समूह ख	21,008	230	28	24	111	05	29
समूह ग और घ	19,904	157	24	14	99	00	06
कुल	**38,631**	**436**	**58**	**42**	**219**	**05**	**35**

उपर्युक्त डेटा में दूरदर्शन महानिदेशालय का पीडब्ल्यूडी डेटा शामिल नहीं है।

नोट :

(i) A (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)

(ii) B (बधिर व्यक्ति)

(iii) C (मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार)

(iv) D (ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी)

(v) E (ए से डी तक के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है)

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट-II

कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाली सूची
वर्ष 2021 के लिए (01/01/2022 तक)

समूह	पीडब्ल्यूडी के लिए सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या					सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या							पीडब्ल्यूडी के लिए प्रमोशन कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पदों की संख्या					प्रमोशन कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या						
	ए	बी	सी	डी	ई	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	ए	बी	सी	डी	ई	ए	बी	सी	डी	ई	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	ए	बी	सी	डी	ई
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
समूह क	00	00	01	00	02	23	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
समूह ख	05	04	04	03	03	01	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	07	01	00	00	01	00	00
समूह ग और घ	09	11	29	28	02	31	07	01	02	04	00	00	01	00	00	00	00	11	00	00	00	00	00	00
कुल	14	15	34	31	07	55	08	02	02	04	00	00	01	00	01	00	00	18	01	00	00	01	00	00

नोट :

(i) ए (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)

(ii) बी (बधिर व्यक्ति)

(iii) सी (मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार)

(iv) डी (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी)

(v) ई (ए से डी तक के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है)

नोट : समूह 'क' के पदों में तरक्की के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

■■■

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन 25 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में संबोधित करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, 16 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में, वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री, श्री गुयेन मान हंग के साथ डिजिटल मीडिया में सहयोग पर आशय पत्र के हस्ताक्षर के अवसर पर। प्रधान महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय, श्री जयदीप भटनागर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

10 राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, भारतीय संघ की राजभाषा है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, सरकार की एक सुविचारित नीति है जिसके तहत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है।

उपयुक्त दायित्व के मद्देनज़र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप अपने दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में मूल रूप से हिंदी का उपयोग करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है, जो मुख्य सचिवालय के साथ-साथ इससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की निगरानी करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की जाती है और सदस्यों द्वारा आधिकारिक कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इससे राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

मंत्रालय के विभिन्न नियमित और महत्वपूर्ण समयबद्ध दस्तावेजों जैसे- कैबिनेट नोट, संसदीय प्रश्न और स्थायी समिति के मामलों आदि के अनुवाद की जरूरतों को पूरा करने और राजभाषा को लागू करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के लिए जिन पदों की स्वीकृति दी गई है, वे हैं-एक निदेशक (राजभाषा), एक उप निदेशक (राजभाषा), दो सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत सभी कागज़ातों/दस्तावेज़ों का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के स्तर पर चेक-पॉइंट बनाए गए हैं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के केवल हिंदी में ही उत्तर दिए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है ताकि राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिालय में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस संबंध में मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14-28 सितंबर, 2021 के दौरान किया गया था। इस दौरान, छह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये हैं-(1) हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग (2) हिंदी वाद-विवाद (3) निबंध लेखन (4) (केवल एमटीएस के लिए) हिंदी श्रुतलेख (5) हिंदी टाइपिंग (6) हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता। इनमें लगभग 110 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के सभी अनुभागों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना लागू है जिसमें उन्हें उनके आधिकारिक कार्य में हिंदी के इस्तेमाल से संबंधित वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर नकद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में अधिकारियों की सुविधा के लिए, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी पखवाड़ा और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया।

■■■

बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री, डॉ. हसन महमूद 07 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात करते हुए।

11 महिला कल्याण

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक महिला सेल का गठन किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2002 को इस सेल को पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत इसे कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों की शिकायत समिति के अधिकार दिए गए। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला सेल के गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।

बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25 अक्टूबर, 2013 को महिला सेल का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

अंतिम बार 18 अक्टूबर, 2021 को सर्कुलर नं. बी-11020/17/2011-एडमिन-III (खंड-II) के आधार पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। सुश्री नीरजा शेखर, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आईसीसी का अध्यक्ष नामित किया गया था। इसके अलावा, सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय सचिव प्रशासन को भारत की वाईडब्ल्यूसीए की ओर से समिति की गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर नामित किया गया। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य एवं एक पुरुष सदस्य समिति के आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां मंत्रालय की संबद्ध/अधीनस्थ एवं स्वायत्त इकाइयों में भी कार्यरत है। समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय लोक सेवा (आचार) नियम, 1964 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अनुपालन हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

■■■

श्रीमती नीरजा शेखर, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 09 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंत्रालय की महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक में।

12 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के एक संभाग प्रमुखों में से की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक उप सचिव (सतर्कता), एक अपर सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता अनुभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा सीवीसी के साथ-साथ सीबीआई के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी, पृथक सतर्कता इकाइयां होती हैं। मंत्रालय का सीवीओ संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। प्रक्रियाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जाता है। संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की अदला-बदली के प्रयास भी किए जाते हैं। 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक, 37 नियमित एवं 18 औचक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा विभिन्न मीडिया इकाइयों एवं मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निगरानी के अधीन रखे जाने के लिए 16 क्षेत्रों एवं 8 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्त्रोतों से 148 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों की जांच हुई और इनमें से 21 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा इस दौरान 21 मामलों से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। निर्धारित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत 17 मामलों में बड़े जुर्माने एवं 03 मामलों में छोटे जुर्माने की शुरुआत की गई। इस अवधि में 06 मामलों में छोटा जुर्माना लगाया गया और 16 मामलों में नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की गई। दो अधिकारियों को नियमों के उपयुक्त प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया।

■■■

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन 22 अक्टूबर, 2021 को तिरुपति में आकाशवाणी तिरुपति स्टेशन के माध्यम से तेलुगु में स्थानीय दर्शकों को संबोधित करते हुए।

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण

नागरिक चार्टर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का वर्ष 2021–22 के लिए नागरिक/उपभोक्ता घोषणा-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझीदारों को प्रत्यक्ष दी जाने वाली निम्न 12 प्रमुख सेवाएं घोषणा-पत्र में शामिल की गई हैं:

(i) भावी लाइसेंस धारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(ii) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस निर्गत करना;

(iii) भावी लाइसेंस धारक को एचआईटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(iv) भारत में कार्य के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलिपोर्ट्स की स्थापना;

(vi) भारत से अपलिंक्ड किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(vii) विदेश से अपलिंक्ड टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी करना;

(viii) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति देना;

(ix) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रकाशन के लिए स्वीकृति-पत्र निर्गत करना;

(x) समाचार और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करण को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्था/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त संस्था द्वारा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र निर्गत करना;

(xi) शिकायत निवारण तंत्र और

(xii) फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय के माध्यम से फीचर फ़िल्मों/रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों की भारत में टीवी शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत-पत्र प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और संपर्क सूत्र का ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/दफ्तरों/विभागों को शिकायत के निस्तारण हेतु भेजी जाती हैं, नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भेजने के निर्देश के साथ इन याचिकाओं की निरंतर निगरानी होती है जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/प्रखंडों को अनुस्मारक-पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यत: एक कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जे के अधिकारी को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में बात करते हैं। याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के संबंध में स्थिति की सूचना याचिकाकर्ताओं को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजी जाती है।

जन शिकायतों के निपटान/निस्तारण के लिए तंत्र को सक्रिय करने संबंधी दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को समय-समय पर वितरित किया जाता है। शिकायतों के निस्तारण की मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर और मासिक 'प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय सीमा :

क्रम संख्या	विषय	समय
1	शिकायतकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका के स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3	शिकायतकर्ता से शिकायत या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि से उसको दिये जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय	2 माह

01.04.2021 से 31.03.2022 तक मंत्रालय में शिकायत की स्थिति

31/03/2021 तक आगे लाई गईं	प्राप्त शिकायतें (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)	लंबित शिकायत 31.03.2022 तक
690	6,454	7,144	6,766	378

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्न श्रेणियों की होती है :

क्र.सं.	शिकायत श्रेणी	01.04.2021 से 31.03.2022 तक प्राप्त शिकायतों की दर
1	अन्य मंत्रालय के विषय में याचिकाएं	35.93%
2	डीटीएच ऑपरेटरों एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	13.23%
3	प्रसारण विषयवस्तु : समाचार एवं गैर-समाचार कार्यक्रम	6.35%
4	सलाह एवं प्रश्न	6.23%
5	पेंशन मामले: पेंशन एवं अन्य देश भत्तों के निर्गमन में विलंब	5.75%
6	विविध	4.00%
7	कोविड-19 संबंधित मुद्दे	3.56%
8	सेवा मामले : स्थायी कर्मचारी	2.99%
9	डिजिटल मीडिया विषयवस्तु	2.39%
10	सेवा मामले : अस्थायी कर्मचारी	2.37%
11	फ़िल्म विषयवस्तु के मामले	2.36%
12	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	2.26%
13	प्रसारण विषयवस्तु विज्ञापन	1.92%
14	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	1.87%
15	प्रेस विषयवस्तु के मामले	1.84%
16	प्रेस पत्रकारों के मामले	1.77%
17	पेंशन मामले : पेंशन का गलत निर्धारण	1.63%
18	पेंशन मामले : पेंशन का पुनर्निर्धारण	1.38%
19	सदाशयी नियुक्तियां	0.98%
20	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता	0.57%
21	शोषण और दुर्व्यवहार	0.43%
22	अनिर्दिष्ट श्रेणी	0.17%
23	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.02%
24	यौन शोषण	0.00%

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 24 सितंबर, 2021 को लद्दाख के लेह में पहले हिमालयन फ़िल्म महोत्सव 2021 के उद्घाटन के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करते हुए। लद्दाख के उपराज्यपाल, श्री आर.के. माथुर भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 14 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में माईपार्किंग्स ऐप के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए।

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। सूचना का अधिकार का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं–

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संगृहीत होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, वितरित करता है और विषय-वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय तथा इससे संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपीलें और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) में प्राप्त होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और 19 अपीलीय प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्षवार प्राप्त आवेदन तथा अपीलें और उन पर की गई कार्रवाई :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2018	1,580
2019	1,424
2020	1,673
2021	1,512

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में 2021 की अवधि के दौरान 1,334 आवेदन और 178 अपीलें प्राप्त हुईं जिसमें से 958 आवेदन और 22 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों और अपीलों को संबंधित लोक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को तुरंत स्थानांतरित/अग्रेषित कर दिया गया। 2021 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 13,750 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय जनसूचना प्राधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए बार-बार अनुस्मारक केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेजे जाते हैं, ताकि आवेदक को जानकारी प्रदान करने में कोई देरी न हो।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलें

मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती है। भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों के त्वरित और समय पर निपटान के लिए मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को स्कैन, अपलोड कर भेजी जाती है। सभी केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सभी सूचनाएं स्वतः उपलब्ध कराने से संबंधित धारा 4 (b) (i) और 4 (b) (ii) के तहत दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना नियमावली को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट, नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

■■■

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव, श्री अपूर्व चंद्र 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के एक भाग के रूप में "संविधान का निर्माण" और फ़िल्म पोस्टर प्रदर्शनी "चित्रांजलि@75" पर आभासी (वर्चुअल) फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन 04 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते हुए।

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय स्थित तीन प्रधान लेखा अधिकारियों और चौदह वेतन व लेखा कार्यालयों, जिसमें केवल जीपीएफ तथा पेंशन के प्रयोजन से प्रसार भारती और उसकी क्षेत्र संरचना से जुड़े छह वेतन व लेखा कार्यालय शामिल हैं, की सहायता से करते हैं। क्षेत्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात हैं, जिनके कार्यों की निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय में की जाती है।

दायित्व

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां हैं:

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण।
- ''एक नज़र में लेखा'' तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदानग्राही संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना; यदि आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके।
- प्राप्ति बजट की तैयारी।
- पेंशन बजट की तैयारी।
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ के लिए/की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
- लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करना।
- मान्यताप्राप्त बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खातों को संभालना और शेष नकद राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदानग्राही संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय-समय पर पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
- खातों और ई-भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत पीएफएमएस को पेश करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।

वेतन और लेखा विभाग

वेतन और लेखा विभाग विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:–

- नॉन–चैक आहरण डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता अनुदान सहित सभी बिलों का प्री–चेक और भुगतान।
- प्रस्तावित नियम एवं कायदों के अंतर्गत सभी भुगतानों का सटीक और समयोचित निपटारा।
- रसीदों की सामयिक प्राप्ति।
- चैक आहरण डीडीओ को पाक्षिक लेटर ऑफ क्रेडिट देना और उनके वाउचर/बिलों का कार्य पश्चात निरीक्षण।
- रसीदों और खर्चों का मासिक संकलन और चेक आहरण डीडीओ के खातों के साथ उन्हें संलग्न करना।
- विलयित डीडीओ के अतिरिक्त जीपीएफ खातों की देखरेख और सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करना।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का संधारण।
- बैकिंग व्यवस्था द्वारा ई–भुगतान के जरिए मंत्रालय/विभाग की सेवाओं को प्रभावशाली बनाना।
- प्रस्तावित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन।
- सामयिक, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और लाभकारी वित्तीय रिपोर्टिंग।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब–हेड/ऑब्जेक्ट–हेड के तहत मासिक और क्रमिक व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय की बजट शाखा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की प्रगति को साप्ताहिक रूप से सचिव तथा अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों से अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों का भी रखरखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार का सत्यापन और प्रमाणीकरण वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विवरणों और कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पेश किए गए पेंशन कागजातों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे– ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के साथ–साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान, सामान्य भविष्य निधि आदि डीडीओ द्वारा उपयुक्त जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का लेखा–परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के अधीन समग्र मार्गदर्शन में काम करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षण परंपरा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय के अधीन भारत भर में विभिन्न मीडिया 531 इकाइयां (प्रसार भारती–459 और गैर–प्रसार भारती–72) हैं जो आंतरिक लेखा के समीक्षा क्षेत्र में आती हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन 30 दफ्तरों का लेखा परीक्षण किया गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती में 31.03.2021 तक और 01.12.2021 तक के बकाया लेखा परीक्षण की स्थिति:

I. प्रसार भारती					
क्षेत्र	31.03.2021 तक बकाया पैरा	01.04.2021 से 30.11.2021 तक एकत्र किए गए पैरा	30.11.2021 तक कुल बकाया पैरा	01.04.2021 से 30.11.2021 तक ड्राप किए गए पैरा	01.12.2021 तक कुल बकाया पैरा
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	625	62	687	130	557
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	191	62	253	51	202
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	200	50	250	43	207
पूर्वी क्षेत्र (कोलकता)	448	72	520	69	451
कुल (I)	**1,464**	**246**	**1,710**	**293**	**1,417**
II. गैर-प्रसार भारती					
क्षेत्र	31.03.2021 तक बकाया पैरा	01.04.2021 से 30.11.2021 तक एकत्र किए गए पैरा	30.11.2021 तक कुल बकाया पैरा	01.04.2021 से 30.11.2021 तक ड्राप किए गए पैरा	01.12.2021 तक कुल बकाया पैरा
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	400	11	411	84	327
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	599	11	610	47	563
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	377	115	492	80	412
पूर्वी क्षेत्र (कोलकता)	326	15	341	47	294
कुल (II)	**1,702**	**152**	**1,854**	**258**	**1,596**
कुल योग (I + II)	**3,166**	**398**	**3,564**	**551**	**3,013**

व्यक्तिगत क्रियाशील खाता बही लेखा प्रणाली (आईआरएलए)

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) दूसरे मंत्रालयों के अन्य विभागीय पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील खाताबही लेखा प्रणाली) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारियों, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) देश भर के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों के सेवा और वेतन रिकार्ड का रखरखाव कर रहा है। पीएओ (आईआरएलए) को एक नई वेबसाइट (https://iis.mib.gov.in/irla/) की शुरुआत के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एनआईसी प्रकोष्ठ के परामर्श से विकसित किया गया है। यह समूह-ए के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन सेवाओं, जैसे सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स फॉर्म-16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि को प्राप्त करना सुगम बनाता है।

बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित (प्रोसेस्ड) ई-भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा, रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों को भी

भेजी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में कुल 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं जिनमें से प्रसार भारती से जुड़े 6 पीएओ हैं, प्रेस कार्यालय दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दो-दो और नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में एक-एक पीएओ स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान संबंधित पीएओ के साथ संलग्न पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपनी मांगों/बिलों को नामित पीएओ/सीडीडीओ के पास प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई-भुगतान जारी करते हैं। पीएमएस और ई-उच्च भुगतान के माध्यम से भेजे गए सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचते हैं।

खातों का कम्प्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा लेखा कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। प्रधान लेखा कार्यालयों में मासिक खातों के समेकन के लिए कॉन्टैक्ट (CONTACT) नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इस मंत्रालय में सभी पीएओ ने वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर इम्प्रूव (IMPROVE) का उपयोग किया। नवंबर, 2018 और उसके बाद से मासिक खातों को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ पूरे किए गए विवरणों के पीएओ-वार समायोजन के बाद प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित ऐप्लिकेशनों का उपयोग मंत्रालय में जमा करने और अन्य एमआईएस प्रयोजनों हेतु शीर्ष-वार विनियोग खातों, केंद्र सरकार के वित्त खाते (सिविल) की सामग्री और मासिक व्यय व प्राप्ति विवरणों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

ई-भुगतान पर पहल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

ई-भुगतान प्रणाली

चूंकि आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को या अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को मान्यता प्रदान करता है, तो लेखा महानियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-भुगतान) के लिए कॉम्पैक्ट (COMPACT) में एक सुविधा विकसित की थी। इसने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सभी वेतन व लेखा कार्यालयों में चल रहे कॉम्पैक्ट ऐप्लिकेशन का लाभ उठाते हुए चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया था।

विकसित की गई ई-भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली थी, जिसने सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत सरकार से बकाए का भुगतान एक सुरक्षित संचार चैनल पर "सरकारी ई-भुगतान गेटवे" (GePG) के माध्यम से कॉम्पैक्ट से जनरेट किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-अनुदेश के जरिए सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में धन जमा कर किया जाता था। इसका प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणीकरण एसटीक्यूसी निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो स्वीकृति की तैयारी, बिल संसाधन (प्रोसेसिंग), भुगतान, प्राप्ति प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखा महानियंत्रक की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण

वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिन्हें आई-की (i-key) कहा जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएओ पीएफएमएस पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए ई-भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण के लिए

संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

बिल जमा करना

आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई-भुगतान के लिए बिल के साथ प्राप्तकर्ता का मैंडेट फॉर्म और बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, खाता संख्या, नाम, पता आदि विवरण वेतन व लेखा अधिकारी के पास जमा कराते हैं। कॉम्पैक्ट (COMPACT) से एक टोकन नंबर जेनरेट किया जाता है और डीडीओ को सूचित किया जाता है।

सीबीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कर देते हैं।

ई-स्क्रॉल

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल सभी सफल ई-भुगतानों के लिए पीएफएमएस पर बैंक द्वारा जेनरेट और अपलोड किया जाता है। ई-स्क्रॉल पीएओ द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं और मिलान तथा अन्य एमआईएस उद्देश्यों के लिए कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं।

ई-भुगतान के लाभ

- डिजिटल हस्ताक्षरित विशिष्ट ई-स्वीकृति आईडी के उपयोग से ऑनलाइन राशि हस्तांतरण की वजह से समय और प्रयास में बचत।
- भुगतान का सुरक्षित तरीका।
- भुगतान क्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेकों और उनकी हस्तचालित कार्यविधि (मैनुअल प्रोसेसिंग) की समाप्ति।
- प्राप्तकर्ता द्वारा चेक को अपने बैंक खाते में हाथ से जमा कराने में आने वाली बाधाओं की समाप्ति।
- समग्र भुगतान कार्यविधि की कार्यक्षमता में वृद्धि।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्व-मिलान।
- खातों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर लेन-देन का पूर्ण लेखा सत्यापन।

बिल पर कार्यवाही

वेतन और लेखा कार्यालय में बिलों पर कार्यवाही कॉम्पैक्ट सिस्टम में की जाती है।

डिजिटल हस्ताक्षर

पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद सुरक्षित आई-की का उपयोग करके यह हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई-भुगतान स्वीकृति जेनरेट की जाती है।

पीएफएमएस पर अधिकार-पत्र अपलोड करना

ई-भुगतान स्वीकृति फाइल (ई-परामर्श) पीएफएमएस सुरक्षित व्यवस्था से अपलोड की जाती है। संबंधित बैंक पीएफएमएस से ई-परामर्श डाउनलोड करते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर आदि के आवश्यक सत्यापन के बाद, बैंक

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए) के व्यय विभाग के द्वारा विकसित एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशन है। पीएफएमएस की विभिन्न मोड/कार्यों द्वारा क्रियान्वित आउटपुट/डिलिवरेबल्स में शामिल हैं (परंतु इन तक सीमित नहीं हैं):

- भुगतान एवं राजकोष नियंत्रण
- प्राप्तियों का लेखा (कर और गैर-कर)
- लेखा कार्यों का संकलन और राजकोषीय रिपोर्ट तैयार करना
- राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण

पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य आज एक कुशल निधि प्रवाह के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिए सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

पीएफएमएस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग के लिए भी चैनल है। जैसे भारत सरकार का हर विभाग/मंत्रालय पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी (व्यक्तिगत या संस्था) को धनराशि अंतरित करता है।

मौजूदा समय में, पीएफएमएस के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिनमें छह पीओ जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े हैं) के सभी 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

पीएफएमएस के विभिन्न माड्यूल

I. **पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल:** यह माड्यूल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

II. **पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल:** पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में विस्तारित किया गया है।

III. **मंत्रालय में गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष)**

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल 01 नवंबर, 2016 से कार्य कर रहा है।
- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक वन-स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य/उपयोगकर्ताओं/द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों के रूप में आती है।
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी व्यवस्था में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में जाकर ड्राफ्ट बनवाने और फिर सरकारी कार्यालयों में जाकर इन साधनों को जमा कराने के झंझट से बचाने में मददगार होते हैं। यह इन साधनों के सरकारी खाते में प्रेषण में देरी से बचने में मदद करता है और यह इन साधनों के बैंक खातों में देरी से जमा होने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करता है।
- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे-इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- मौजूदा वित्तीय वर्ष (2021-22) में 01.04.2021 से 13.12.2021 की अवधि के लिए मंत्रालय का गैर-कर राजस्व का संग्रह 1,469.00 करोड़ रुपया है और इसमें से 1,464.13 करोड़ रुपया (अर्थात 99.70%) से अधिक है एनटीआर ई-पोर्टल पर भारतकोष के माध्यम से एकत्र किया गया।

IV. **पीएफएमएस का व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी छह स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम, अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर लाया गया है।

मंत्रालय में नई गतिविधियां

I. राजकोष एकल खाते (टीएसए)

सरकारी उधारी की लागत को कम करने, स्वायत्त निकायों को निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने, बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए और सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को उनके बैंक खातों में जारी की गई निधियों की पार्किंग से बचने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने दिनांक 12 मई, 2020 के अपने ओ.एम. संख्या 1(18)-बी(एसी)/2017 के जरिए राजकोष एकल खाते (टीएसए) की शुरुआत की। उपर्युक्त के अनुपालन हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने

भी 1 अक्टूबर, 2020 से प्रसार भारती में, अनुदान प्राप्त वेतन के घटक को छोड़कर टीएसए का संचालन किया है। प्रसार भारती की विभिन्न इकाइयों/उप-इकाइयों से संबंधित चार सौ उनसठ असाइनमेंट खाते भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में खोले गए हैं। मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक विभाग, व्यय विभाग से 4 अन्य स्वायत्त इकाइयों में टीएसए मॉड्यूल लागू किए जाने की पेशकश की है। यह संस्थान है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी), फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (एफटीआईआई) और सत्यजित रे फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई)।

II. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में बढ़ी हुई सुरक्षा परतों का प्रवर्तन

पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु कोष संचालन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं लागू की जा रही हैं:

(क) वेतन व लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बिना कभी चूके, भौतिक बिल के साथ प्रत्येक भुगतान अनुरोध का सत्यापन।

(ख) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल से व्यवहार करने वाले अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए एनआईसी/जीओवी डोमेन ई-मेल आईडी का उपयोग।

(ग) जो उपयोगकर्ता सक्रिय नहीं हैं, उनका तत्काल निष्क्रियकरण।

(घ) स्थायी स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के समय पीएओ/एओ प्रकार के उपयोगकर्ता की यूजर आईडी/डिजिटल-की का निष्क्रियकरण।

(ड.) चरणबद्ध तरीके से पीएफएमएस पर ओटीपी आधारित लॉग इन प्रक्रिया का क्रियान्वयन।

■■■

मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का ढांचा

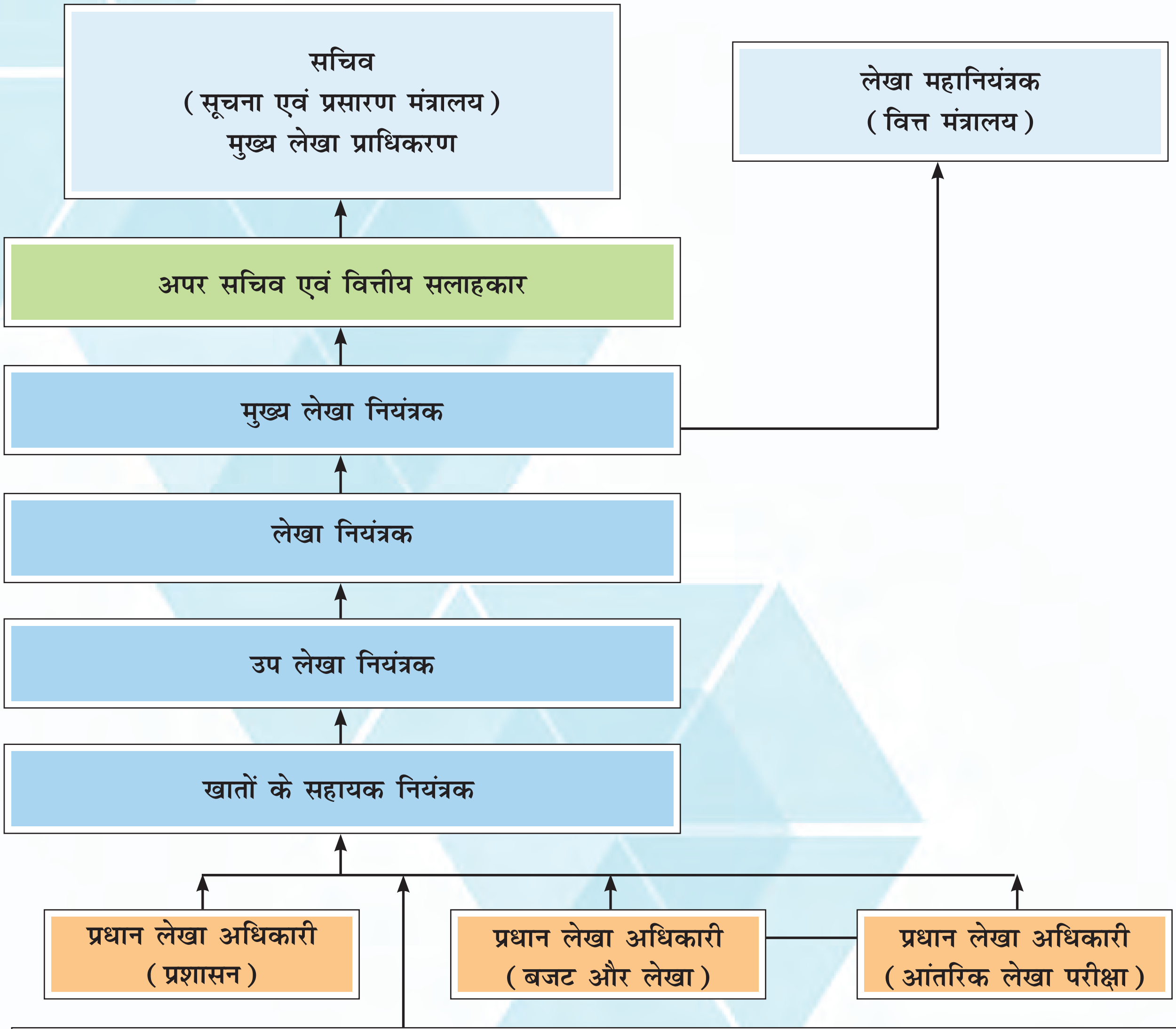

1. वेतन और लेखा कार्यालय (एमएस) नई दिल्ली
2. वेतन और लेखा कार्यालय (बीओसी आदि) नई दिल्ली पूर्व में पीएओ (डीएवीपी आदि)
3. वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) नई दिल्ली
4. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नागपुर
5. वेतन और लेखा कार्यालय (एफडी) मुंबई
6. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) चेन्नई
7. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) लखनऊ
8. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) कोलकाता
9. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नई दिल्ली
10. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) गुवाहाटी
11. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) चेन्नई
12. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) कोलकाता
13. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) मुंबई
14. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) नई दिल्ली
15. 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग (आरओबी) में अपर महानिदेशक (क्षेत्रीय) के एनसीडीडीओ/सीडीडीओ और आईएफए के रूप में कार्यरत हैं।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 10 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 नवंबर, 2021 को पणजी, गोवा में 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईआईएफएफ-2021) के समापन समारोह को संबोधित करते हुए।

16 लेखा पैरा

(क) सीएंडएजी से प्राप्त

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएंडएजी पैरा सूची

क्रम संख्या	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	विषय ब्योरा	कार्रवाई
1.	2021 का 2	9.1	***सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई)-कर्मचारी भविष्य निधि का अतिरिक्त भुगतान-*** कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उल्लंघन में, कोलकाता के सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने अपने 89 कर्मचारियों के लिए 1.89 करोड़ की अतिरिक्त राशि भविष्य निधि के तौर पर जमा कराई है।	अंतिम कार्रवाई के लिए विषय को 14.10.2021 के वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग सेल को भेज दिया गया।

(ख) सार्वजनिक लेख समिति (पीएसी) की सिफारिशें

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.12.2021 तक सीएंडएजी/पीएसी की कोई भी पैरा प्राप्त नहीं हुआ है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'काशी फ़िल्म महोत्सव' में।

17 कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की जानकारी इस प्रकार है:

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2020-21 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	2020-21 में कार्यान्वित निर्णयों/आदेशों की संख्या
1	केंद्रीय संचार ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)	5	5
2	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	2	2
3	भारतीय जन संचार संस्थान	1	1
4	आईआईएस अनुभाग	1	0
5	प्रसार भारती	2	0
6	दूरदर्शन समाचार	2	2
7	महानिदेशकः आकाशवाणी	39	31
8	महानिदेशकः दूरदर्शन	37	29
	कुल	**89**	**70**

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 21 नवंबर, 2021 को पणजी, गोवा में भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई-2021) के दौरान 75 यंग क्रिएटिव माइण्ड्स विजेताओं को सम्मानित करते हुए।

18 योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2021-22):

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (अस्थायी) परिव्यय

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/योजना/मीडिया इकाई का नाम	बजट अनुमान (2021-22)
1	सूचना क्षेत्र (विकास संचार और सूचना प्रसार - डीसीआईडी)	188.00 (169.00 करोड़ - सामान्य और 19.00 करोड़ - पूर्वोत्तर क्षेत्र)
2	फ़िल्म क्षेत्र (विकास संचार और फ़िल्मी सामग्री का प्रसार - डीसीडीएफसी)	124.21 (115.21 करोड़ - सामान्य और 9.00 करोड़ - पूर्वोत्तर क्षेत्र)
3	प्रसारण क्षेत्र (मुख्य सचिवालय)	
ए	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन (सीआरएस)	3.84 (3.60 करोड़ - सामान्य और 0.24 करोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र)
बी	प्रसार भारती (प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास - बीआईएनडी)	316.00 (281.00 करोड़ - सामान्य और 35.00 करोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र)
	कुल प्रसारण क्षेत्र	**319.84 (284.6 करोड़ - सामान्य और 35.24 करोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र)**
	कुल योग	**632.05 (568.81 करोड़ - सामान्य और 63.24 करोड़ - पूर्वोत्तर क्षेत्र)**

योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2021-22):

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय 632.05 करोड़ रुपये है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस*
1.	सूचना क्षेत्र	188.00
2.	फ़िल्म क्षेत्र	124.21
3.	प्रसारण क्षेत्र	319.84
	कुल	**632.05**

63.24 करोड़ रुपये का पूर्वोत्तर अवयव 632.05 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय (जीबीएस) का 10 प्रतिशत दर्शाता है। पूर्वोत्तर अवयव के अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस*
1.	सूचना क्षेत्र	19.00
2.	फ़िल्म क्षेत्र	9.00
3.	प्रसारण क्षेत्र	35.24
	कुल	**63.24**

*सकल बजट सहायता

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 25 सितंबर, 2021 को कारगिल, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन हम्बोटिंग ला में हाई पावर ट्रांसमीटर के उद्घाटन के अवसर पर।

19 मीडिया इकाई-वार बजट

मीडिया इकाई-वार बजट			
मांग संख्या 61 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
			(रु. हज़ार में)
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-2023**
राजस्व अनुभाग			
श्रेणी-I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर-योजना व्यय)			
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	8,91,800	8,72,000	9,75,900
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	4,900	3,900	0
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	1,33,300	1,16,500	1,32,000
फ़िल्म प्रभाग	5,24,000	5,05,000	5,68,900
भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	1,05,800	69,321	92,000
फ़िल्म समारोह निदेशालय	1,41,000	1,29,694	1,20,000
न्यू मीडिया विंग	16,700	18,800	20,800
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)	18,85,300	17,98,700	20,25,700
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	10,29,900	10,34,100	10,74,800
भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक	85,200	82,150	79,500
प्रकाशन विभाग	4,15,000	4,08,410	5,08,100
रोज़गार समाचार	1,41,800	76,025	600
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	2,31,100	1,83,100	2,03,200
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (आईपीडीसी)	2,100	2,100	2,100
एशिया पैसेफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) को योगदान	3,000	3,100	3,100
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	40	40	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	260	260	260
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	26,500	1,500	21,700
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय	**56,37,700**	**53,04,700**	**58,28,700**

(रु. हज़ार में)			
योजनाओं के नाम	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-23**
श्रेणी-II केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (योजना व्यय)			
सूचना क्षेत्र			
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	18,80,000	18,80,000	18,40,000
कुल (सूचना क्षेत्र)	**18,80,000**	**18,80,000**	**18,40,000**
फ़िल्म क्षेत्र			
विकास संचार और फ़िल्म सामग्री का प्रसार	12,26,200	8,45,000	12,71,600
चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना	15,900	0	0
कुल (फ़िल्म क्षेत्र)	**12,42,100**	**8,45,000**	**12,71,600**
प्रसारण क्षेत्र			
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	38,400	25,000	38,400
ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट	31,60,000	17,50,000	31,50,000
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**31,98,400**	**17,75,000**	**31,88,400**
कुल - केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**63,20,500**	**45,00,000**	**63,00,000**
इनमें से पूर्वोत्तर आवंटन	**6,32,400**	**4,50,000**	**6,30,000**
पूंजी के तहत आवंटन	**1,26,200**	**2,11,000**	**2,56,500**

श्रेणी-III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं) (गैर-योजना व्यय)

(रु. हज़ार में)			
स्वायत्त संस्थाओं के नाम	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**बजट अनुमान 2022-23**
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को सहायता अनुदान	6,50,000	3,00,000	5,20,000
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को सहायता अनुदान	2,00,000	1,57,000	2,71,800
बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) को सहायता अनुदान	39,000	35,200	37,400
भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) को सहायता अनुदान	5,84,800	4,50,900	5,53,900
सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)	8,79,200	6,08,800	7,43,000
प्रसार भारती सहायता अनुदान	2,64,01,100	2,62,90,300	2,55,52,900
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं)	**2,87,54,100**	**2,78,42,200**	**2,76,79,000**
कुल - मांग सं. 61	**4,07,12,300**	**3,76,46,900**	**3,98,07,700**

■■■

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 26 सितंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बोनीबाग से बोनीबागबाला को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करते हुए।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन 23 मार्च, 2022 को तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए।

20

सांगठनिक ढांचा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठन चार्ट

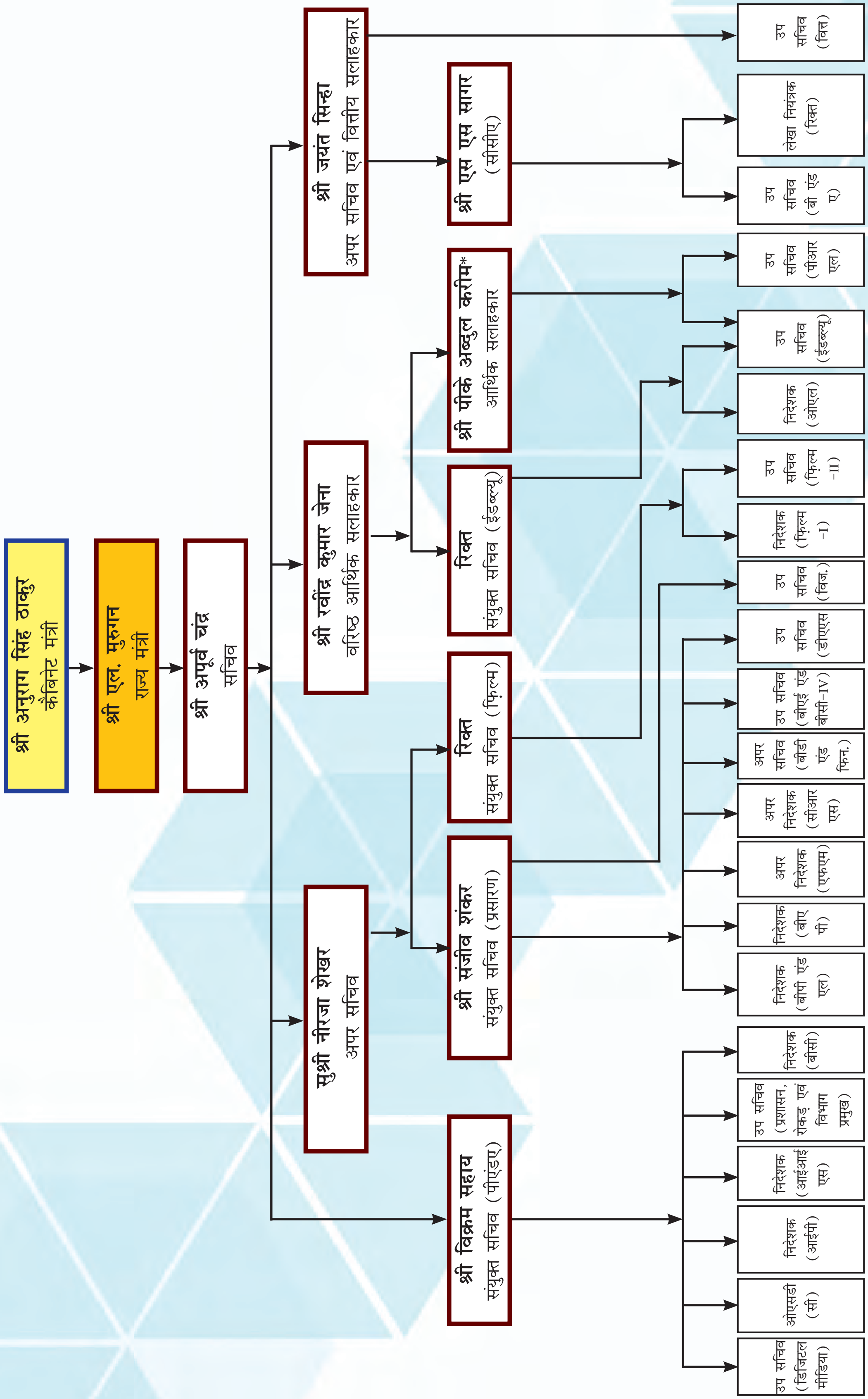

*संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार (ईडब्ल्यू)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पदनाम (2021-22)

सचिव	**सचिव**
एएस	अपर सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
एस ईए	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (आर्थिक विंग)
जेएस (पी एंड ए)	संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन)
जेएस (बी)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
जेएस (एफ)	संयुक्त सचिव (फ़िल्म)
जेएस (ईडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (आर्थिक विंग)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
ओएसडी (सी एंड पीपीसी एंड आईपी एंड एमसी)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय, नीति नियोजन प्रकोष्ठ, सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
निदेशक (फ़िल्म-I)	निदेशक (फ़िल्म-I)
निदेशक (आईपी)	निदेशक (सूचना नीति)
निदेशक (बीसी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक/निदेशक (ओएल)	निदेशक/निदेशक (राजभाषा)
निदेशक (बीपीएंडएल)	निदेशक (प्रसारण नीति और विधान)
निदेशक (बीएपी)	निदेशक (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
उप सचिव (फिन.)	उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (फ़िल्म)-II	उप सचिव (फ़िल्म-II)
डीएस (बी एंड ए)	उप सचिव (बजट और लेखा)
डीएस (कैश, एडमिन एंड एचओडी)	उप सचिव (नकद, प्रशासन और विभागाध्यक्ष)
डीएस (डीएएस)	उप सचिव (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
डीएस (ईडब्ल्यू)	उप सचिव (आर्थिक विंग)
डीएस (विज. एंड पार्ल.)	उप सचिव (सतर्कता और पार्लियामेंट)
डीएस (बीएई एंड बीसी-IV)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग और प्रसारण सामग्री-IV)
अपर निदेशक (एफएम)	अपर निदेशक (फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन)
सीए	लेखा नियंत्रक
यूएस (एडमिन. I, II, III, IV एंड एचओओ)	अवर सचिव (प्रशासन I, II, III एवं कार्यालय का प्रमुख)
यूएस (आईआईएस)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यूएस (एमयूसी-I)	अवर सचिव (मीडिया यूनिट समन्वय-I)
यूएस (एमयूसी-II)	अवर सचिव (मीडिया यूनिट समन्वय-II)
यूएस (प्रेस)	अवर सचिव (प्रेस)
यूएस (विजिलेंस)	अवर सचिव (विजिलेंस)

सचिव	सचिव
यूएस (कैश एंड पार्ल.)	अवर सचिव (कैश और पार्लियामेंट)
यूएस (एनएमसी एंड एनएमडब्ल्यू)	अवर सचिव (न्यू मीडिया सेल और न्यू मीडिया विंग)
यूएस (पीपीसी एंड आईपीएंडएमसी)	अवर सचिव (नीति नियोजन प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
यूएस (बीसी-I, II एंड III)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री-I, II और III)
यूएस (इनसेट-TV)	अवर सचिव (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)
यूएस (डीएएस)	अवर सचिव (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
यूएस (बीपी एंड एल)	अवर सचिव (प्रसारण नीति और कानून)
यूएस (बीडी एंड बी फिन.)	अवर सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
यूएस (बीएपी-I)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम-I)
यूएस (बीएपी-II)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम-II)
यूएस (बीए-ई)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग)
यूएस (बीएस-IV)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री-IV)
यूएस (एफ-I एंड III)	अवर सचिव (वित्त-I और वित्त-III)
यूएस (फिन-II)	अवर सचिव (वित्त-II)
यूएस (बी एंड ए)	अवर सचिव (बजट और लेखा)
यूएस (ईडब्ल्यू)	अवर सचिव (आर्थिक विंग)
यूएस (एफ (सी), एफ (एफ), एंड एफ (आई))	अवर सचिव (फ़िल्म प्रमाणन, फ़िल्म समारोह और फ़िल्म उद्योग)
यूएस (एफ (ए), एफ (एफटीआई) और एफ (पीएसयू))	अवर सचिव (फ़िल्म प्रशासन, फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान और फ़िल्म सार्वजनिक वित्त उपक्रम)
डीडी (ओएल)	उप निदेशक (राजभाषा)
डीडी (सीआरएस)	उप निदेशक (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
डीसीए	उप लेखा नियंत्रक
एडी (ओएल-1)	सहायक निदेशक (राजभाषा-1)
एडी (ओएल-2)	सहायक निदेशक (राजभाषा-2)
एस.ओ. (एडमिन-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I)
एस.ओ. (एडमिन-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II)
एस.ओ. (एडमिन-III)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III)
एस.ओ. (एडमिन-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)
एस.ओ. (कैश)	अनुभाग अधिकारी (कैश)
एस.ओ. (संसद प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (संसद प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (एमयूसी-I)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई सेल-I)
एस.ओ. (एमयूसी-II)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई सेल-II)
एस.ओ. (विजिलेंस-I एंड II)	अनुभाग अधिकारी (विजिलेंस-I) अनुभाग अधिकारी (विजिलेंस-II)
एस.ओ. (आईपी एंडएमसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
एस.ओ. (पीपी सेल)	अनुभाग अधिकारी (नीति योजना प्रकोष्ठ)

सचिव	सचिव
एस.ओ. (प्रेस)	अनुभाग अधिकारी (प्रेस)
एस.ओ. (आईआईएस-I)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-I
एस.ओ. (आईआईएस-II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-II
एस.ओ. (एफ (एफ))	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म समारोह)
एस.ओ. (एफ (एफटीआई))	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान))
एस.ओ. (एफ (ए) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (प्रशासन))
एस.ओ. (एफ (सी) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (प्रमाणन))
एस.ओ. (एफ(आई) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी फ़िल्म (उद्योग) डेस्क)
एस.ओ. (एफ (पीएसयू) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) डेस्क)
एस.ओ. (बीसी-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-I)
एस.ओ. (बीसी-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-II)
एस.ओ. (बीसी-III)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-III)
एस.ओ. (बीसी-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-IV)
एस.ओ. (बी (डी))	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण (विकास))
एस.ओ. (बी (फिन))	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण (वित्त))
एस.ओ. (बीपी एंड एल)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और विधान-I) अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और विधान)
एस.ओ. (बीए-पी)-I	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन- कार्यक्रम-I)
एस.ओ. (बीए-पी)-II	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन- कार्यक्रम-II)
एस.ओ. (बीएई-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी-I)
एस.ओ. (बीएई-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी-II)
एस.ओ. (एफएम सेल)	अनुभाग अधिकारी (फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन सेल)
एस.ओ. (सीआरएस सेल)	अनुभाग अधिकारी (सामुदायिक रेडियो स्टेशन सेल)
एस.ओ. (इनसेट-टीवी I एंड II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)-I अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)-II
एस.ओ. (फिन-I एंड III)	अनुभाग अधिकारी (वित्त I और III)
एस.ओ. (फिन-II)	अनुभाग अधिकारी (वित्त II)
एस.ओ. (पीसी सेल)	अनुभाग अधिकारी (योजना समन्वय प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (बी एंड ए)	अनुभाग अधिकारी (बजट और लेखा)
एस.ओ. (पीएमएस)	अनुभाग अधिकारी (प्रदर्शन प्रबंधन अनुभाग)
एस.ओ. (एनएमसी और एनएमडब्ल्यू)	अनुभाग अधिकारी (न्यू मीडिया सेल और न्यू मीडिया विंग)
एस.ओ. (आरटीआई सेल)	अनुभाग अधिकारी (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (सीपीजीआरएएमएस)	अनुभाग अधिकारी (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली)
पीएंडएओ	वेतन और लेखा अधिकारी

■■■

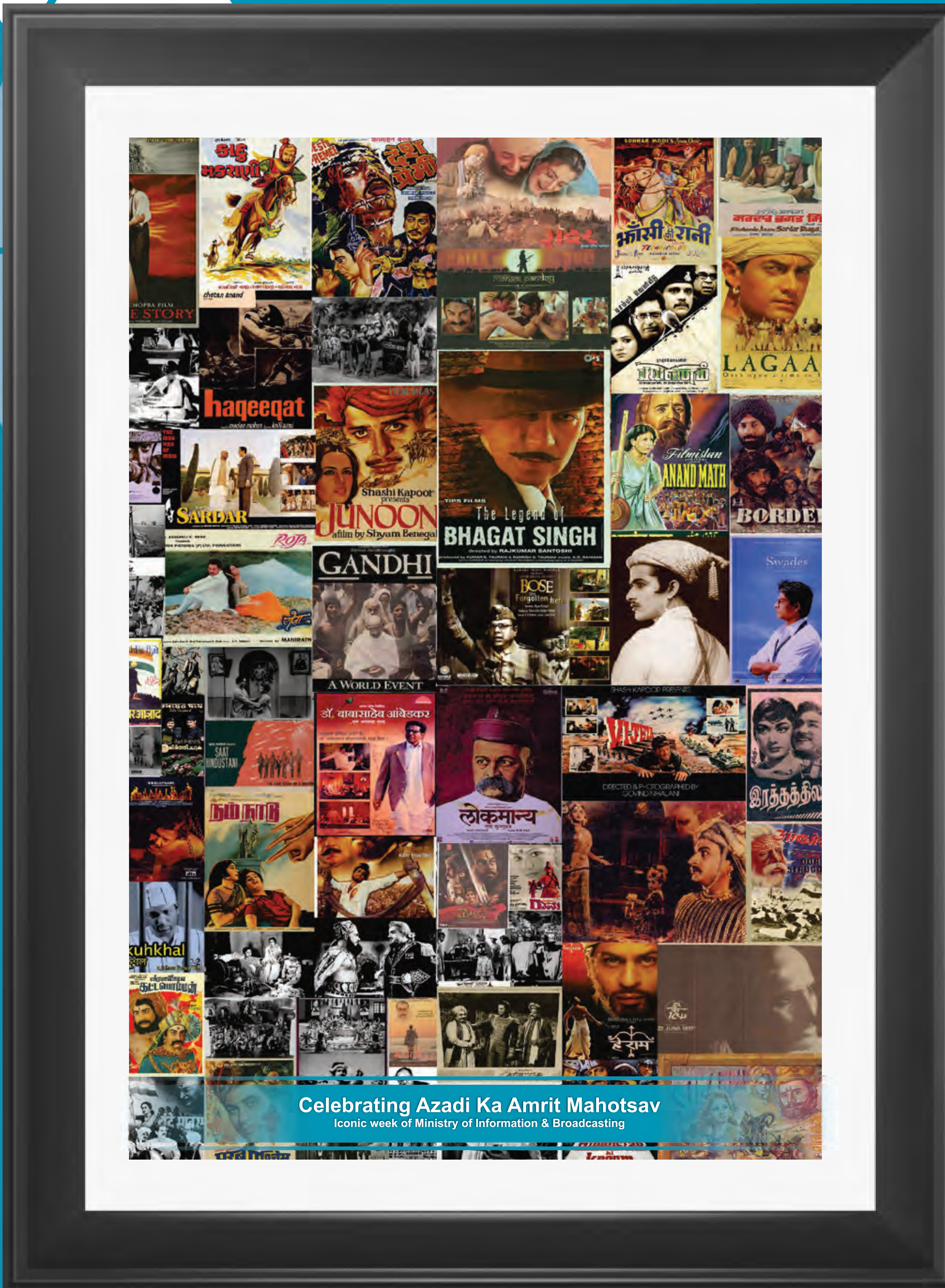
Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav
Iconic week of Ministry of Information & Broadcasting
haqeeqat
SARDAR
Shashi Kapoor presents
JUNOON
a film by Shyam Benegal
GANDHI
A WORLD EVENT
The Legend of
BHAGAT SINGH
Filmistan
ANAND MATH
Swades
झाँसी की रानी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
लोकमान्य
SHASHI KAPOOR PRESENTS
DIRECTED & PHOTOGRAPHED BY
GOVIND NIHALANI
हे राम
chetan anand